R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-25

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 12
16 से 31 मार्च 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

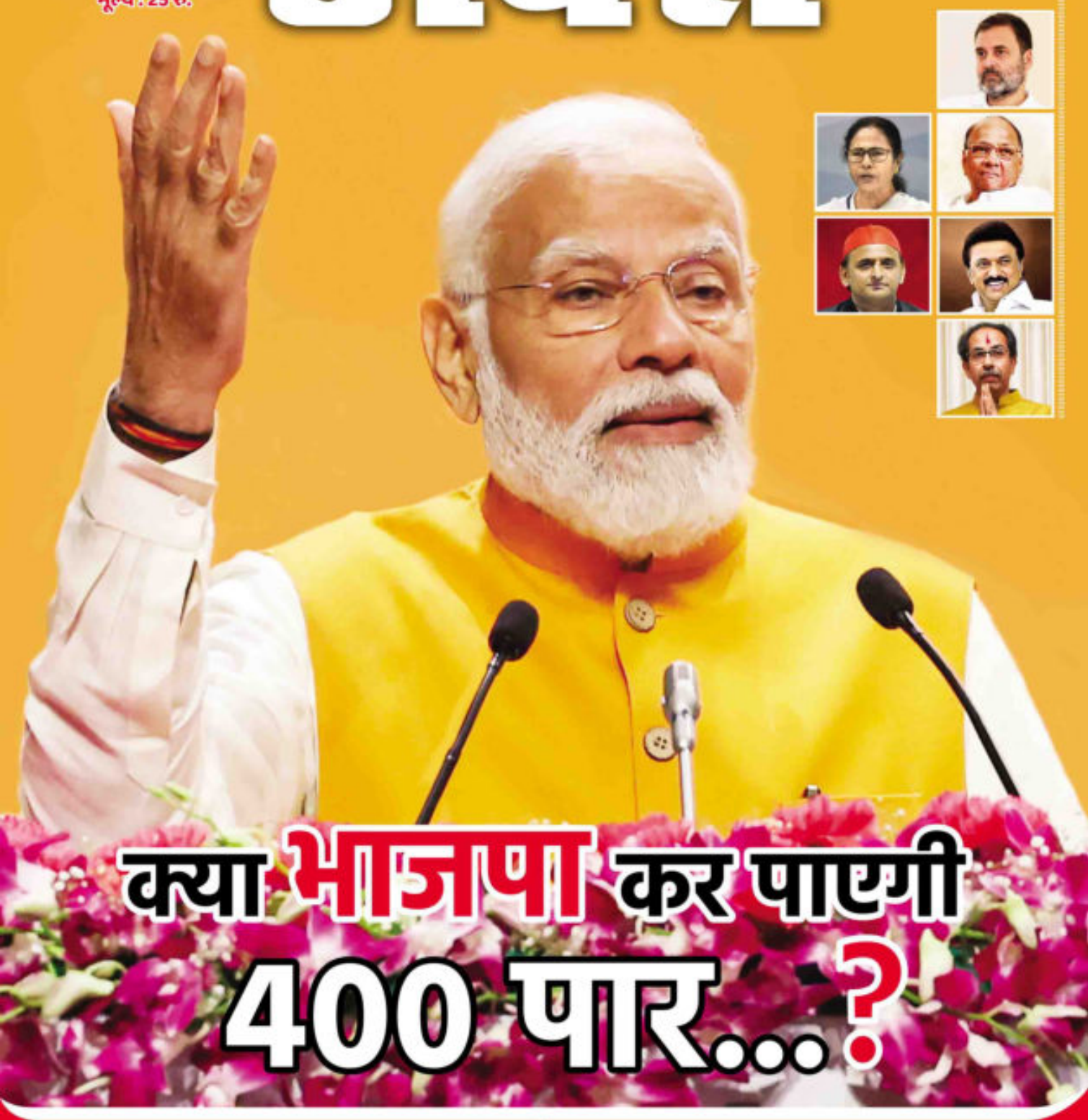

क्या भाजपा कर पाएगी 400 पार...?

दक्षिण की लक्ष्मण रेखा को कैसे पार कर पाएगी भाजपा?

क्या इंडिया गठबंधन का रणनीतिक मुकाबला होगा फेल?

ANU SALES CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
1 2 3 • 17 18 19 20 • 33 34 35 36 37 • 45 46
R1+S L1 R2 L2 WS1 WS2
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology & Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

योजना

9 | परियोजनाओं के सहारे...

जल्द लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है। इससे पहले मप्र सरकार उन लाखों किसानों को साधने में जुट गई है, जो केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना के जरिए...

राजकाज

10-11 | राजनीतिक भगदड़...

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देशभर में नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोलने का उपक्रम कर रहे हैं, किंतु मप्र में उनकी मोहब्बत की दुकान में ताला लगने की नौबत आती जा रही है। अनुमानत...

आर्थिकी

13 | चमकदार आंकड़ों...

जीडीपी में देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में तेजी से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी तिमाही के लिए 6.5 प्रतिशत और एसबीआई रिसर्च में 6.7 से 6.9 प्रतिशत तक रहने का अनुमान...

लापरवाही

15 | बिजली घरों की राख बनी खतरा

कोयला संकट के बीच बिजली उत्पादन प्रभावित होने के बीच एक नया संकट भी तेजी से बढ़ा है। प्रदेश के ताप बिजली घरों से बड़ी मात्रा में निकलने वाली फ्लाई ऐश (राख) के निपटान में गंभीर कोताही बरती जा रही है। यहां से निकली खतरनाक राख हवा-पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा खासी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा ने अबकी बार 400 पार का नारा दिया है और उसे उम्मीद है कि इस बार पार्टी पिछले दो आम चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य को लेकर अलग-अलग बिसात बिछाई है। कई जगह से उसे सीटें बढ़ने की उम्मीद है। उधर, इंडिया गठबंधन भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी मैजिक के सहारे वह लक्ष्य हासिल कर लेगी।

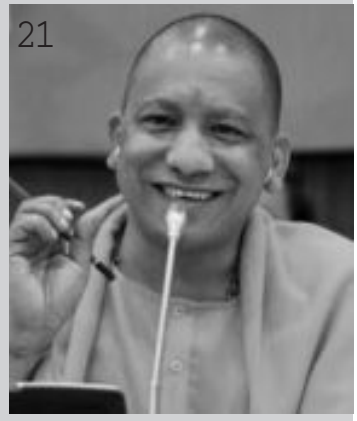

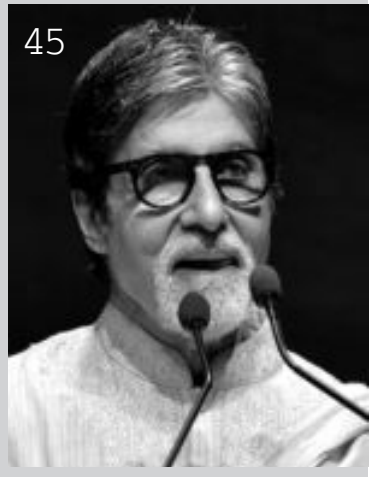

राजनीति

30-31 | टारगेट के साथ...

लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए)...

महाराष्ट्र

35 | टिकट बंटवारे का महासंकट

उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में जुटी भाजपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसके सहयोगी दल बन रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहली सूची जारी करते समय उसे उम्मीदवार चयन करने के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहना था। बिहार में नीतीश 2019 की तरह 17...

बिहार

38 | लालू का परिवार...

पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने तरीके से राजनीतिक वापसी की। अपने तीखे और चुटीले भाषण के लिए विख्यात लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाया तो पूरी भाजपा बचाव में उतर आई। मोदी के बचाव में भाजपा...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

सूखे की राह पर पानी वाली धरती...

भारत को पानी वाली धरती कहा जाता है। क्योंकि यहां नदियों, झीलों, तालाब, कुओं, नहरों, झरनों की लंबी श्रृंखला है। लेकिन हमारी गलतियों के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से पानी वाली धरती सूखे की राह पर आगे बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अभी गर्मी शुरू ही हो रही है कि देश में सूखे ने दस्तक दे दी है। वर्तमान स्थिति पर ये पंक्तियां सटीक बैठ रही हैं...

सूखी नदियां, झील पियासी...पानी मांगे ताल
मौसम के सिर चढ़कर नाचे... फिर अगिया बेताल

देश के कई शहर भीषण जलसंकट झेल रहे हैं। देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरू में जलसंकट गहरा गया है। इस कारण यहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है। कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। बेंगलुरू वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। बोर्ड ने कहा कि नियम का पालन नहीं करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तेमाल कार धोने, कपड़े धोने या पौधों में डालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे न मानने पर 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल, पेयजल के स्रोत सूख गए हैं, गली-गली में पानी के टैंकर दौड़ रहे हैं। भारत के एक तिहाई भाग में 750 मिलीमीटर से कम बारिश, दूसरे एक-तिहाई भाग में मात्र 750-1125 मिलीमीटर बारिश होती है। कुल बारिश की तीन चौथाई मात्र 80 दिन में ही हो जाती है। पानी की असमान उपलब्धता, चरम मौसमी परिस्थितियां और अनियमित मानसून के कारण मिट्टी की नमी में लंबे समय तक कमी खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों में सुखाड़ का कारण बन रही है। दूसरी तरफ खाद्यान्न सुरक्षा के मद्देनजर पिछले पांच दशक में फसलों के प्राकृतिक चक्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है, साथ ही अत्यधिक रसायन और सिंचाई आधारित कृषि चलन में है, खासकर पश्चिमोत्तर भारत में तो भूमिगत जल अब खत्म होने के कगार पर है। भारत में मानसून के कुछ दशक के आंकड़ों पर ध्यान दें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरे दक्षिण एशिया में इसके विन्यास में व्यापक बदलाव देखा जा रहा है। कुछ दिनों की अतिवृष्टि के बाद लंबे समय तक गायब बरसात अब मानसून की पहचान हो गई है। मानसून में भी सूखे दिनों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और बरसात वाले दिनों की संख्या सिकुड़ती जा रही है, जिससे न सिर्फ बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है बल्कि भूमिगत जल का पुनर्भरण भी कम हो रहा है। शहरीकरण, रहवास के बढ़ते दायरे और भूमि के कांक्रीटीकरण से भूमिगत जल के पुनर्भरण में लगातार कमी आ रही है। साथ-साथ सतही जल के स्रोत जैसे पोखर, तालाब और छोटी-छोटी नदियां जो मानसून के आगमन तक भूमि में आवश्यक नमी बरकरार रखती थी, अब जाड़े के मौसम के बाद ही सूखने लगी हैं। अकेले कृषि के लिए तीन-चौथाई ज्यादा जंगल कटे हैं, वहीं अवैज्ञानिक आधुनिक और लाभ आधारित कृषि कार्य में दो-तिहाई से ज्यादा मीठा पानी खप रहा है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या के लिए कृषि-भूमि, खनन, अधिवास, यातायात और अन्य जरूरतों के लिए जरूरी ढांचागत विकास के कारण जंगल, घास के मैदान, यहां तक कि वेटलैंड सहित अन्य प्राकृतिक भूमि के उपयोग में हो रहे व्यापक स्तर के बदलाव ने भू-क्षरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पानी की धरती अब सूखे की राह पर चल पड़ी है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 12, पृष्ठ-48, 16 से 31 मार्च, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

विदेशी पर्यटकों का इंतजार

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से केवल उप्र ही नहीं बल्कि देशभर में विदेशी पर्यटकों का आना-जाना तेज होगा। उप्र में कांग्रेसियों, समाजवादियों और बहुजनवादियों के शासन में जिस धर्म को राज्य से दूर रखा गया, वही धर्म अब उप्र की आर्थिक समृद्धि का वाहक बन गया है।

● **योगेश शिवहरे,** छतरपुर (म.प्र.)

ध्यान दे सरकार

जब भी कोई बड़ी घटना-दुर्घटना होती है सरकार न्यायायिक जांच आयोग का गठन कर देती है। 15 साल में राज्य में चार सरकारें सत्ता में रहीं। इसमें तीन बार भाजपा और डेढ़ साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **अभिनव साहू,** इंदौर (म.प्र.)

मास्टर प्लान का इंतजार

भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 1995 में जारी किया गया था, जो 2005 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, बीच में तीन बार मास्टर प्लान को लेकर कवायदें होती रहीं। सरकार को अब नया मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए।

● **ब्रजेश तिवारी,** भोपाल (म.प्र.)

क्या कमाल दिखा पाएगी राहुल की यात्रा?

राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा को उनकी दक्षिण से उत्तर यात्रा के बाद के कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका असली मकसद हिंदी पट्टी में जीत के बाद माहौल को और मजबूत करना था। पिछली यात्रा काफी सफल रही थी, राहुल के रास्ते में भारी भीड़ जुटी थी और उन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया था और मोदी सरकार पर हमला बोला था। लेकिन इस बार की यात्रा, जो हार के बाद हुई है, जिसने कर्नाटक की जीत को भी फीका कर दिया है। यह यात्रा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। यह उन इलाकों से होकर गुजरी है, जहां कांग्रेस को अब भी उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस में असली चिंता लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनावी रणनीति को लेकर है।

● **धीरेंद्र सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

आत्मनिर्भर बन विकास कर रहा भारत

केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बूते आत्मनिर्भर बनने की राह पर दौड़ रहा है। स्वावलंबी भारत अभियान के जरिए स्वदेशी सोच को मिली तरजीह के कारण ही स्वदेशी हथियारों, मिसाइल, हल्के फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम में दुनिया अब दिलचस्पी दिखा रही है। आज भारत 85 से अधिक देशों को स्वदेशी हथियार और उपकरण, कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत अभियान की बदौलत हथियारों के आयात पर होने वाले खर्च में भी गिरावट आई है।

● **विवेक यादव,** सीहोर (म.प्र.)

चुनावी बॉन्ड चर्चा में...

चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद से, भाजपा की आय में वृद्धि हुई है और यह अपने प्रतिद्वंद्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पछाड़कर भारत की सबसे धनी पार्टी बन गई है। जिसकी किस्मत में कुछ सालों को छोड़कर गिरावट देखी गई है। चुनावी बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय भले ही रोक लगा दे, गैर भाजपा दल भाजपा की चाहे जितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन यह तय है कि चुनावी रण के खर्च के लिए धन जुटाने की कोई और राह जरूर खोज ली जाएगी।

● **आनंद शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बसपा बढ़ाएगी गठबंधन की मुश्किलें!

कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात की हो रही थीं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगी। गत दिनों कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के माध्यम से संपर्क कर गठबंधन में आने की बात की थी लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया कि वह बगैर गठबंधन के ही आगामी आम चुनाव के सियासी मैदान में उतरने जा रहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ने वाली हैं। क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस के सियासी गठबंधन को चुनावी नजरिए से बेहद मजबूत माना जा रहा था। जिस पर मायावती ने पानी फेर दिया है। फिलहाल अब इस फैसले के बाद मायावती जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस समूह में शामिल हो जाती है, तो मुस्लिम और दलितों के बड़े बिखराव को रोका जा सकता है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर उप्र में सियासत की एक दूसरी तस्वीर सामने आ सकती है। अगर सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में उतरती, तो बसपा के 19 फीसदी वोटों से कई सियासी समीकरण साधे जा सकते थे।

रायबरेली-अमेठी पर सस्पेंस बरकरार

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। लेकिन अभी तक पार्टी का गढ़ कही जाने वाली उप्र के रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रायबरेली और अमेठी की जनता से राहुल, प्रियंका का मोहभंग हो गया है? अमेठी के लोगों को निराशा तब हाथ लगी जब पहली सूची में राहुल गांधी का नाम वायनाड से घोषित हुआ। यह नाम आते ही अमेठी के लोगों में निराशा छा गई। पहली और दूसरी सूची में रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का भी नाम नहीं था, जिसके कारण रायबरेली की भी जनता मायूस हुई। सूत्रों के अंदर खाने से बड़ी खबर यह भी है कि रायबरेली की जिला कांग्रेस कमेटी सहित पूर्व विधायक और रायबरेली के कार्यकर्ता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। यह अटकलें हैं कि राहुल, प्रियंका और सोनिया का अमेठी रायबरेली की जनता से विश्वास उठ गया है। गौरतलब है कि सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा चुनी गई हैं। राहुल गांधी 2019 में अमेठी हार चुके हैं। इस बार भी उन्होंने अपना नाम वायनाड से ही घोषित कराया है, जिससे कहा जा सकता है कि दशकों पुराना घर का रिश्ता अब दूरी में बदल गया है।

आरसीपी की हो सकती है घर वापसी

बिहार की राजनीति के गलियारों में एक बार फिर भाजपा नेता आरसीपी सिंह की घर वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से उदासीन हो चुके आरसीपी अब अपनी राजनीति को नया रंग देना चाहते हैं। नीतीश कुमार का विरोध कर भाजपा में आए आरसीपी को निराशा तब हुई जब नीतीश फिर से एनडीए का हिस्सा बने। जब आरसीपी सिंह भाजपा में शामिल हुए तब कहा जा रहा था कि वे नीतीश के विरूद्ध अपनी राजनीति को अंजाम देना चाहते हैं और उम्मीद लिए भाजपा में आए थे। आरसीपी की पहली उम्मीद थी कि उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन भाजपा ने इस बार भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेजकर आरसीपी की नाराजगी बढ़ा दी है। एक उम्मीद यह भी थी कि भाजपा उन्हें नालंदा लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। मगर एनडीए में जदयू के आ जाने के बाद यह बची खुची उम्मीद भी चली गई। ऐसा इसलिए कि नालंदा जदयू की सिटिंग सीट तो है ही साथ ही नीतीश का गृह क्षेत्र भी है। गौरतलब है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर राजनीतिक गलियारों में आई तभी से वह घर वापसी की राह देखने लगे थे।

राज्यसभा जाएंगे सिंघवी?

देश के जाने-माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने अपने हिसाब से सबसे सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 40 विधायकों का बहुमत है। लेकिन कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे सिंघवी और भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले। अंत में लॉटरी से फैसला हुआ, जिसमें सिंघवी हार गए और वे राज्यसभा जाते-जाते रह गए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिंघवी दो साल और इंतजार करेंगे या फिर वे झारखंड से राज्यसभा में जाएंगे? असल में इसी महीने 21 मार्च को झारखंड की दो और केरल की तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें केरल की एक सीट कांग्रेस को मिलेगी और झारखंड की एक सीट पर भी कांग्रेस का दावा है। पिछले दो चुनावों से राज्यसभा की सीट जेएमएम को मिल रही है। पहले 2020 में शिबू सोरेन राज्यसभा गए और फिर 2022 में महुआ मांझी को हेमंत सोरेन ने राज्यसभा भेजा।

एनडीए का बढ़ेगा कुनबा!

आम चुनाव 2024 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए का कुनबा बढ़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि उड़ीसा में भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। ऐसे में अटकलें हैं कि जल्द ही दोनों दलों में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। असल में उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में भाजपा और बीजेडी एक साथ आ सकते हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। इसको लेकर दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर तेज हो गया है। बीते दिनों दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा संग बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम शामिल हुए। बैठक के बाद ओराम ने कहा कि एलायंस समेत कई मसलों पर बातचीत हुई लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

बड़े घर मिलकर आईए...

प्रदेश में अपना एक अलग रसूख रखने वाले माइनिंग के एक कारोबारी उस समय असमंजस में फंस गए, जब अफसरों ने उन्हें दो टूक शब्दों में कह दिया कि आपका काम तभी आगे बढ़ेगा, जब आप बड़े घर से मिलकर आएंगे। दरअसल, कारोबारी प्रदेश में वर्षों से माइनिंग का काम कर रहे हैं। इस कारण उनका विभाग और अफसरों के बीच आना-जाना बना रहता है। कहा तो यहां तक जाता है कि अफसर अक्सर उनका इंतजार करते हैं कि कब वे उनसे मिलने आएंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद विभाग में कामकाज की प्रणाली भी बदल गई है। शायद यही वजह है कि विगत दिनों जब माइनिंग का काम करने वाले कारोबारी अपने रुके हुए काम के संबंध में अफसरों से मिलने गए तो अफसरों का व्यवहार उनसे पहले की तरह मिलनसार नहीं था। अफसर भी उनसे रूखा-सूखा व्यवहार कर रहे थे। मौके की नजाकत को भांपते हुए कारोबारी ने भी अफसरों से पूछ लिया कि आखिर क्या बात है कि आप लोग हमारे काम को रोक रखे हो। उनके इस सवाल पर एक अफसर ने उनसे साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि अब यहां की स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल गई हैं। विभाग में आपका काम अब तभी आगे बढ़ेगा, जब आप बड़े घर मिलकर आएंगे। सूत्रों का कहना है कि पहले तो साहब बड़े घर का नाम सुनकर हकबकाए, फिर माजरा समझकर मुस्कुराए और चल दिए जुगाड़ लगाने।

चर्चा में मैडम की चिट्ठी

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि जो चिट्ठी चर्चा में बनी हुई है, उसको पहली बार मंत्री बनी एक नेत्री ने लिखा है। दरअसल, मैडम ने अपनी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है और मांग की है कि सीपीए को फिर से चालू किया जाए। मैडम ने चिट्ठी में लिखा है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि से सलाह नहीं ली गई। एक अफसर की जिद के कारण इस विभाग को बंद कर दिया गया। मैडम की बात यहां तक सही है, लेकिन उस चिट्ठी में जिस तरह की तकनीकी बातें लिखी गई हैं, उसकी समझ निसंदेह मैडम को नहीं है। जब इस मामले में पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि एक अधिकारी ने मैडम को मोहरा बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है। हालांकि स्वजातीय मंत्री से चिट्ठी मिलते ही सीएम ने सीएस को निर्देशित करते हुए लिखा है कि इस पर ध्यान केंद्रित करें। सीएस ने भी संबंधित विभाग को इस दिशा में कार्यवाही करने का निर्देश दिया और उक्त विभाग ने आव देखा न ताव और मैडम की चिट्ठी पर कार्यवाही शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि मैडम की यह चिट्ठी क्या गुल खिलाती है।

बड़ी मैडम को आखिर इतनी रूचि क्यों ?

मप्र में कुछ सालों से सरकारी विभागों की अनुपयोगी और खाली पड़ी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 600 करोड़ से अधिक की संपत्तियां बेची जा चुकी हैं। इन संपत्तियों को बेचने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग भी बना दिया है। इस विभाग पर अनुपयोगी संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, फिर उनकी नीलामी की जाती है। सूत्रों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया पर बड़ी मैडम यानी मुख्य सचिव ने इंटरेस्ट दिखाया है और मामले को गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दी है। बड़ी मैडम की इस कवायद को लेकर प्रशासनिक वीथिका में तहकीकात की जा रही है कि आखिर मैडम को इसमें इतनी रूचि क्यों है। दरअसल, मैडम को यह जानकारी कोई दिलजला दे गया है। इस मामले में सूत्रों का कहना है कि मैडम का ध्यान इस ओर इसलिए गया है कि अच्छी लोकेशन और शहरों के बीचोंबीच होने के बाद भी इन संपत्तियों को बाजार दर से 60 फीसदी तक कम दामों पर बेचा जा रहा है। प्रदेश सरकार की आर्थिक तंगी को दूर करने के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचने के इस अभियान में बड़े घालमेल की आशंका भी जताई जा रही है। जब भी कोई परिसंपत्ति की नीलामी होती है तो प्रशासनिक वीथिका में उसकी राशि को लेकर चर्चा होने लगती है। शायद यही वजह है कि बड़ी मैडम का ध्यान इस ओर गया है। अब देखना यह है कि मैडम की यह रूचि क्या गुल खिलाती है।

गाड़ियों की जंग, मंत्री तंग

प्रदेश के एक बड़े महकमें में मंत्रियों के बीच कार को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आलम यह है कि विभाग के बड़े मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री को 5 वाहन मिले हैं, वहीं छोटे मंत्री यानी राज्यमंत्री को मात्र एक ही वाहन मिला है। यानी एक मंत्री पर अफसर पूरी तरह मेहरबान हैं और दूसरे को भाव नहीं दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों छोटे मंत्री ने विभाग से एक गाड़ी मांगी तो अफसरों ने कहा कि आपको स्विफ्ट डिजायर कार ही दे सकते हैं। अफसरों की यह शर्त सुनकर छोटे मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि बड़े मंत्री को बिन मांगे पांच वाहन मिल गए हैं, जबकि छोटे मंत्री के पास स्टेट गैरेज से मिली एक इनोवा ही है। ऐसे मंत्री जी ने अफसरों से वाहनों के साथ ही अन्य खर्चों का हिसाब मांग लिया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है और अफसर परेशान हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि छोटे मंत्री द्वारा खर्चों के हिसाब मांगे जाने के बाद विभाग के अफसर इस कोशिश में लगे हैं कि जैसे भी हो, मंत्रीजी को मना लिया जाए, क्योंकि अगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे तो पूरे विभाग की भर्राशाही खुलकर सामने आ जाएगी। ये वही मंत्री हैं, जिनकी पत्नी को मालवा क्षेत्र की एक सीट से लोकसभा का टिकट मिला है।

यह तो चिरकुट प्राधिकरण...

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। वजह भी है। दरअसल, मामला सरकार द्वारा हाल ही में घोषित चित्रकूट विकास प्राधिकरण का है। सूत्रों के अनुसार विगत दिनों कैबिनेट की बैठक में जब चित्रकूट साडा को भंग कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई, तो उसके संसाधनों को लेकर सवाल खड़े किए गए। दरअसल, जब चित्रकूट साडा का गठन किया गया था तो उसके लिए एक कमरे का दफ्तर बनाया गया था। उस दफ्तर में स्टाफ के नाम पर बस एक चपरासी था। कमरे में पंखा भी नहीं था। स्थिति यह थी कि साडा के पास बिजली का बिल जमा करने के लिए पैसा भी नहीं था। ऐसे में जब विकास प्राधिकरण की घोषणा की गई तो कहा गया कि आगे देखा जाएगा, अभी तो साडा जैसी स्थिति में था, वैसी ही स्थिति में प्राधिकरण को शुरू किया जाए। यह जवाब सुनकर बैठक में शामिल अधिकांश लोग अचंभित रह गए। इस बीच किसी ने फुस-फुसाकर कहा कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण चिरकुट प्राधिकरण तो नहीं बनकर रह जाएगा। यह बात अब सब जगह गूंज रही है।

पदोन्नति मिली पदस्थापना नहीं

मप्र में इन दिनों कई आईपीएस अफसरों को पदोन्नति के बाद पदस्थापना नहीं होने से पुराने पदों पर ही काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह अफसर वैसे तो अब डीआईजी बन चुके हैं, लेकिन काम उनसे पुलिस कप्तान का ही कराया जा रहा है। दरअसल करीब दो माह पहले सरकार ने प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन आईपीएस अफसरों को पदोन्नत कर डीआईजी बना दिया था। इसके बाद उनकी पदस्थापना करना ही भूल गई। इसकी वजह से जूनियर अफसरों को जिले की कप्तानी मिलने का इंतजार करना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि पदोन्नत हुए अफसर भी चाहते हैं, कि उनकी पदोन्नति में जितनी देरी हो उतना ही अच्छा है। इसकी वजह है डीआईजी का पद एक सामान्य पद माना जाता है, जबकि पुलिस कप्तान का पद बेहद महत्वपूर्ण और मलाईदार माना जाता है। यही वजह है कि जूनियर अफसर चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द पदोन्नत होने वाले अफसरों की नए सिरे से पदस्थापना करे, जिससे रिक्त होने वाले पदों पर उनकी पदस्थापना हो सके।

राज्य सरकार ने 29 दिसंबर को 2009 और 2010 बैच के 18 आईपीएस अफसरों को एसपी से डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया था, इनमें से कई अफसर पीएचक्यू में पदस्थ थे, तो वे वहीं के वहीं एडजस्ट हो गए, लेकिन जिलों में पदस्थ एसपी और बटालियन में पदस्थ कमांडेंट के डीआईजी बनते ही उन्हें अन्यत्र पदस्थ किया जाना था, जो कि सरकार दो माह बाद भी नहीं कर पाई। इनमें अमित सांघी एसपी छतरपुर, वीरेंद्र कुमार सिंह एसपी खंडवा, मोहम्मद युसुफ कुरैशी एसपी सिंगरौली, प्रशांत खरे एसएसपी रेडियो, अतुल सिंह कमांडेंट 7वीं बटालियन भोपाल, मनीष कुमार अग्रवाल डीसीपी ट्रैफिक इंदौर, निमिष अग्रवाल डीसीपी क्राईम इंदौर, पंकज श्रीवास्तव कमांडेंट 15वीं बटालियन इंदौर, राजेश कुमार सिंह डीसीपी जोन-4 इंदौर, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया कमांडेंट आरएपीसीसी इंदौर के नाम शामिल हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से 19 डीआईजी रेंज बनाए गए हैं, जिससे आसपास के जिलों में एसपी के ऊपर कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से देख सकें। लेकिन इसके बावजूद 19 में से 7 डीआईजी रेंज खाली हैं। इंदौर शहर में डीआईजी के दो पद हैं, इनमें से एक पद खाली है। इसी तरह भोपाल में भी डीआईजी के दो पद हैं, यहां भी एक पद खाली है। इसी तरह खरगौन, उज्जैन, रीवा और नर्मदापुरम में डीआईजी के पद खाली हैं। इन रेंज को प्रभारी डीआईजी देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में अफसर नहीं हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो प्रदेश में 40 डीआईजी रेंज के अफसर हैं। जिन जिलों के पुलिस कप्तान बदले जाने हैं, उनमें सिंगरौली, छतरपुर, खरगोन, रतलाम, खंडवा, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, शहडोल, उमरिया, कटनी आदि जिले शामिल हैं। इसके अलावा डीआईजी भोपाल देहात मोनिका शुक्ला को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर बदला जाएगा। डीआईजी देहात इंदौर, एडिशनल सीपी भोपाल, इंदौर के साथ ही कुछ डीसीपी भी बदले जाएंगे। डीआईजी ग्वालियर कृष्णा वेनी देशावातू अपने पति के कारण भोपाल में पदस्थापना चाह रही हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय से अनुरोध भी किया है।

उम्मीद थी मिलेगा बैच

डिप्टी कलेक्टर के बजाय प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का पदनाम पाने वाले इन अधिकारियों को उम्मीद थी कि जीएडी उन्हें बैच अलाट करेगा और उसके आधार पर उन्हें आने वाले समय में प्रभारी पदोन्नति ही मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा लेकिन जीएडी ने इन्हें बैच अलाट करने से मना कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि जीएडी ने इस आधार पर बैच अलाट करने से मना किया है कि इन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद प्रभारी के रूप में मिला है। इसलिए बैच अलाट नहीं हो सकता। हालांकि अफसर यह स्वीकार कर रहे हैं कि पदोन्नति नहीं किए जाने से इनके बाद पीएससी परीक्षा में सिलेक्ट हुए डिप्टी कलेक्टर इसी कारण सीनियरिटी में उनसे आगे हो गए हैं। इस मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अफसरों की एक टीम ने पिछले माह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें ज्ञापन देकर कहा गया था कि प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों को बैच अलाट किया जाए ताकि नए चयनित डिप्टी कलेक्टरों को अलाट ईयर के मुकाबले उनकी सीनियरिटी कम न हो जाए। अब जबकि चयनित डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनकर एसडीएम का काम देख रहे तहसीलदारों को फिर सीनियरिटी खोना पड़ रही है और इसको लेकर उनमें आक्रोश भी है।

लोकायुक्त व ईओडब्ल्यू एसपी के कई पद रिक्त है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के साथ ही वर्षों से जमे अधिकारियों को इधर-उधर भी किया जा सकता है। उधर, राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और प्रमोशन रोकने की नीति 6 माह पहले प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनने वाले तहसीलदारों पर भारी पड़ रही है। 2023 में प्रभारी डिप्टी कलेक्टर घोषित कर इन तहसीलदारों को सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने संवर्ग के अधीन भले ही कर लिया है और जिलों में उनकी पदस्थापना कर एसडीएम बना दिया गया है लेकिन जीएडी अब तक तय नहीं कर पा रहा है कि इन्हें कोई बैच अलाट किया जाए या नहीं किया जाए। उधर, 2019 में सिलेक्ट 24 और 2020 की पीएससी की परीक्षा में सिलेक्ट 24 समेत कुल 48 डिप्टी कलेक्टर जनवरी 2024 का बैच पाकर इन प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों से सीनियर हो गए हैं।

एक अप्रैल 2016 को जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर दिग्विजय सरकार में लागू व्यवस्था को रिवर्ट करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसी माह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी थी और तब से लेकर आठ साल बीत गए हैं, किसी भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को नियमित पदोन्नति नहीं मिल सकी है। राजस्व विभाग के तहसीलदार भी सरकार की गलती की इस सजा को भुगतने को मजबूर हैं। इन तहसीलदारों को लंबी लड़ाई के बाद जीएडी और राजस्व विभाग के समन्वय और बैठकों में हुए निर्णय के आधार पर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले प्रभारी डिप्टी कलेक्टर का पद सौंपा गया है। जीएडी द्वारा पहले 181 तहसीलदारों को और बाद में 24 अन्य तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है।

● सुनील सिंह

जंगल, जंगल बात चली है...

हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक के टाइटिल ट्रैक-जंगल, जंगल बात चली है पता चला है...आपने सुना ही होगा। वर्तमान समय में जंगल महकमे में बात चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि यह विभाग दलालों से भरा पड़ा है। दरअसल, प्रदेश का जंगल महकमा ऐसा है, जिसके बारे में अगर यह कहा जाए कि यह ठेके पर चलता है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि विभाग में मंत्री कोई भी रहे, उसे दलाल और ठेकेदार ही चलाते हैं। वर्तमान समय में जिस माननीय को मंत्री बनाया गया है, वे भी दलालों के चंगुल में फंस गए हैं। इनके आसपास तो दलालों के गैंग ने घेरा मार लिया है। इनमें एक साहब वित्त सेवा के अधिकारी हैं, जो अपर संचालक के पद पर हैं। वर्तमान में वे एक निगम में कार्यरत हैं, परंतु पिछले दो माह से जंगल के मुखिया के यहां सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे हैं एक माइनिंग किंग के भाई और तीसरे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले महाशय। इनमें से दो तो हमेशा से बदनाम रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि मंत्री जी के नाम पर ये लोग जमकर लक्ष्मी बटोर रहे हैं। इनमें माइनिंग किंग के भाई तो मंत्रीजी के साथ इसलिए चिपक गए हैं कि उनके ही क्षेत्र में उनका खनन का काम चल रहा है। यही नहीं ये महाशय आचार संहिता से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लगे रहे। हद तो यह है कि यह अधिकारियों को चमकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दलाली का यह पूरा नेटवर्क फोरेस्ट गेस्ट हाउस से चल रहा है। दरअसल, वन महकमे में जंगलराज चलता है। इस विभाग में मंत्री, अधिकारियों से सांठगांठ कर ठेकेदार और दलाल पूरे विभाग को कब्जा लेते हैं। फिर चलता है काली कमाई का खेल। इस खेल की पोल भी जल्दी सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि सारा खेल जंगल में होता है। वहां न तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं और न ही कोई देखने वाला। सप्लाई, तार फेंसिंग, पौधारोपण, नाली खुदाई, बंधान आदि न जाने कितने तरह के काम होते हैं। जिनकी जरूरत हो या न हो लेकिन ऐसे काम सालभर चलते हैं।

सूत्रों का कहना है कि वर्तमान समय में जो नेताजी विभाग के मंत्री हैं, उन्हें तो दलालों ने इस तरह घेर लिया है कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। आज स्थिति यह है कि वन विभाग में अधिकारी अपनी सहूलियत और मनमर्जी का काम कर रहे हैं। सरकार भले ही भाजपा की है, लेकिन अफसर कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों की फर्म पर मेहरबान है। इसी कड़ी में जंगल महकमे में एक दर्जन से अधिक डीएफओ ने चैन लिंक और वायरबेड खरीदी की निविदा में ऐसी शर्त जोड़ दी, जिसे केवल कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की फर्म को ही वर्क आर्डर मिल सके। सूत्रों का कहना है कि वन मंत्री के यहां अनाधिकृत तौर पर ओएसडी का काम करने वाले वित्तीय सेवा के एक अधिकारी और एक माइनिंग सप्लायर लगातार डीएफओ को फोन करके अपने चहेते फर्म को ठेका दिलवाने के लिए नई-नई शर्तें जुड़वा रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिकारी अवैधानिक रूप से मंत्री के यहां पदस्थ हैं और मंत्री के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेका दिलाने के काम में लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार दक्षिण सागर, बैतूल और बालाघाट समेत एक दर्जन डीएफओ ने चैन लिंक और वायरबेड खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित बुलाई गई। इस निविदा में 3 करोड़ के टर्न-ओवर के साथ यह शर्त भी जोड़ दी कि भारत मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त फर्म ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगी। यह शर्त पहली बार जोड़ी गई। इस शर्त के कारण तीन दर्जन से अधिक संस्थाएं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई। मप्र में भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त दो फर्म ही रजिस्टर्ड हैं। यह दोनों फर्म ही कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की हैं। यानी कांग्रेस नेता के रिश्तेदार को उपकृत करने के लिए प्रदेश के एक दर्जन डीएफओ ने पहली बार यह शर्त निविदा में जोड़ दी है। यह बात अलग है कि प्रतिस्पर्धा से बाहर हुई संस्थाओं ने शिकवे-शिकायतें शुरू कर दी हैं। जानकारों का कहना है कि मंत्री के यहां अनाधिकृत रूप से सक्रिय अपर संचालक स्तर के एक अधिकारी के कहने पर फील्ड के अफसरों ने निविदा में भारतीय मानक ब्यूरो की शर्त जोड़ी है। बताया जाता है कि अफसर पर दबाव बनाने वाले अनाधिकृत काम देख रहे अधिकारी के कांग्रेस नेताओं से पुराने संबंध रहे हैं।

उधर, इंदौर के चोरल फील्ड फायरिंग के बदले कम्पेल में वन विभाग की जमीन पर हुए पौधारोपण को लेकर भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां 79 हजार पौधे लहलहाने थे, लेकिन जमीन पर सिर्फ पांच से लेकर आठ फीट ऊंची घास नजर आती है। कागजों में दो करोड़ रुपये खर्च हो चुके है। विभाग में इस तरह के घपले-घोटाले लगातार हो रहे हैं, लेकिन मंत्रीजी चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्री के आसपास रहने वाले दलालों का जंगल में हो रहे घपले-घोटालों में हाथ है।

● **कुमार राजेंद्र**

पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खोल दी विभाग की पोल

वन विभाग के मंत्री सहज हैं, सरल हैं या फिर चालाक हैं, यह तो आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया है। लेकिन उनकी करनी देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वे न तो अपने विभाग को समझ पाए हैं और न ही अपनी डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कूनो अभयारण्य में चल रहे चीता प्रोजेक्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। बिना जाने-बूझे उन्होंने कह दिया कि कूनो चीतों के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि आज स्थिति यह है कि कूनों में चीतों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि कूनो अभयारण्य में चीतों को बसाने की बहुप्रतीक्षित योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने अफ्रीकी विशेषज्ञों से अभयारण्य का सर्वे कराया था, उसके बाद इसे चीतों के लिए उपयुक्त बताए जाने के बाद ही यहां चीतों को बसाने का काम शुरू हुआ। लेकिन मंत्रीजी ने बिना सोचे-समझे ही पूरी योजना पर सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं मंत्रीजी ने तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भी लाइन में लगा दिया। दरअसल, इतना भारी भरकम गिफ्ट था, जिसके लिए पत्रकारों की लाइन लगवाई गई। इसको देखकर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति पत्रकारों को लाइन में लगा सकता है, वह औरों को क्या समझेगा।

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देशभर में नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोलने का उपक्रम कर रहे हैं, किंतु मप्र में उनकी मोहब्बत की दुकान में ताला लगने की नौबत आती जा रही है। अनुमानतः मप्र में करीब 6 हजार बड़े और छोटे नेता कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस भगदड़ को रोकना मुश्किल लग रहा है।

राजनीतिक भगदड़ रोकना मुश्किल...

प्रदेश स्तर पर दो और हर जिले में तीन-तीन नेताओं की टोली

मप्र में कांग्रेस, सपा, बसपा और आप समेत बाकी दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भाजपा में शामिल करवाने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर न्यू जॉइनिंग टोली का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय टोली के संयोजक पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और सह संयोजक पूर्व मंत्री संजय पाठक हैं। इसके अलावा हर जिले में तीन-तीन नेताओं की न्यू जॉइनिंग टोली बनाई गई है। इस टोली में जिला अध्यक्ष के साथ संगठन के दो पदाधिकारी शामिल हैं। दूसरी पार्टी का कोई नेता भाजपा जॉइन करना चाहता है तो उसे जिला स्तरीय टोली से संपर्क करना होता है। जिला स्तर पर बनी टोली इसकी जानकारी प्रदेश स्तरीय टोली को देती है। प्रदेश स्तर पर बनी टोली संबंधित नेता का पूरा फीडबैक जुटाकर उसे पार्टी जॉइन कराने की हरी झंडी देती है। इसके बाद जब किसी प्रदेश स्तरीय नेता का जिले में दौरा होता है तो कार्यक्रम का आयोजन कर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को शामिल कराया जाता है। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद जैसे बड़े नाम वाले नेताओं की जॉइनिंग प्रदेश स्तर पर या किसी बड़े कार्यक्रम में होती है।

लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 जनवरी से 9 मार्च तक करीब 5800 नेता भाजपा जॉइन कर चुके हैं। इनमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदों के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष, पार्षद समेत सामाजिक संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। दरअसल, दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा ने न्यू जॉइनिंग टोली का गठन किया है। पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को इस टोली का संयोजक बनाया है। पूर्व मंत्री संजय पाठक को सह संयोजक बनाया है। न्यू जॉइनिंग टोली दूसरे दलों के नेताओं का फीडबैक जुटाकर उन्हें पार्टी में शामिल करती है।

भाजपा की जॉइनिंग टोली जनवरी से लेकर अब तक दूसरे दलों से आने वाले करीब 6 हजार नेताओं को भाजपा में शामिल करवा चुकी है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने भाजपा जॉइन की उन्होंने कांग्रेस की रीति-नीति पर सवाल खड़े किए। भाजपा जॉइन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि मेरा ध्येय समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का है। उन्होंने कहा- कांग्रेस में एक नारा लगा था, न जात का न पात का, लेकिन कांग्रेस में ये नारा दरकिनार कर दिया गया है। आज जाति की बात हो रही है। इससे जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। कुछ दिनों से जो राजनीतिक और धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो दुखी करने वाले हो रहे हैं। इससे पहले जबलपुर के मेयर जगत बहादुर अन्नू ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने को आधार बनाकर पार्टी छोड़ी थी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि दूसरी पार्टी से आए लोग चाहते हैं कि वे देश के लिए बेहतर काम करें, इसलिए भाजपा के साथ आ रहे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस समेत दूसरे दलों का कोई भविष्य नहीं है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति ये जनता का विश्वास है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों से आए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

राहुल गांधी की न्याय यात्रा की मप्र से रुखसती के तीसरे दिन इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी ने अपने समर्थक दल-बल के साथ कांग्रेस को बाय-बाय कह दिया। सुरेश पचौरी के साथ इंदौर लोकसभा क्षेत्र से संजय शुक्ला और देपालपुर से विशाल पटेल सहित भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी व अन्य ने कांग्रेस को 2020 की ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद सबसे बड़ा झटका दिया है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने से देशभर में चर्चा के केंद्र में आए संजय शुक्ला का नाम इंदौर लोकसभा से कांग्रेस के पैनल में सबसे ऊपर था, वहीं सुरेश पचौरी को भी पार्टी भोपाल या होशंगाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ाने के मूड में थी। किस्मत तो गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की भी चमक सकती थी क्योंकि धार से कांग्रेस को कोई सशक्त चेहरा नहीं मिल रहा था। अब स्थिति यह है कि इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और धार से कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा के मजबूत प्रत्याशी के सामने लड़ सके।

सूत्रों के अनुसार धार से गजेंद्र सिंह तो होशंगाबाद से सुरेश पचौरी भाजपा के टिकट पर

लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भाजपा ने होशंगाबाद लोकसभा सीट से दर्शन सिंह चौधरी को टिकट दे दिया है किंतु पार्टी यहां बदलाव भी कर सकती है। यदि टिकट न भी बदला तो 24 वर्षों तक राज्यसभा सांसद रहे सुरेश पचौरी को पार्टी राज्यसभा में एडजस्ट कर उनके अनुभव का लाभ उठा सकती है। हालांकि अब भाजपाई हलकों में यह प्रश्न मुखर होता जा रहा है कि वर्तमान भाजपा तो पहले से अधिक कांग्रेसी होती जा रही है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? क्या भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता इन आयातित नेताओं को दिल से स्वीकार कर पाएंगे? इन सब में यह भी बड़ा प्रश्न है कि इन सभी नेताओं का पुनर्वास कैसे और कब होगा?

राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मप्र आगमन के समय ग्वालियर-चंबल संभाग में कार्यकर्ताओं के नाश्ते-भोजन की व्यवस्था का अपने खर्चे पर प्रबंध करने वाले संजय शुक्ला 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। पार्षद, विधायक रहते हुए अपने खर्च से क्षेत्र की जनता को तीर्थयात्रा करवाने और भंडारे की राजनीति से इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के समकक्ष खड़े होने से संजय शुक्ला कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके बढ़ते कद को देखते हुए भाजपा ने अपने कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला के सामने इंदौर विधानसभा क्रमांक-1 से उतारकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इंदौर में जनसंघ और भाजपा के शिल्पकार रहे स्व. विष्णुप्रसाद शुक्ला के बेटे संजय शुक्ला को पूरे चुनाव प्रचार में कैलाश विजयवर्गीय अपना बच्चा बताते रहे किंतु संजय शुक्ला ने उन पर गंभीर एवं चारित्रिक आरोपों की झड़ी लगा दी।

हालांकि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए किंतु इंदौर शहर की जनता के मन में यह बात घर कर गई कि भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है तो वह संजय शुक्ला ही है। अब जबकि संजय शुक्ला स्वयं कैलाश विजयवर्गीय के हाथों से भगवा गमछा पहन चुके हैं तो इंदौर की राजनीति के समीकरण ही बदल गए हैं। समीकरण तो शुक्ला परिवार में भी बदलेंगे क्योंकि इन्हीं संजय शुक्ला के चचेरे भाई गोलू शुक्ला कांग्रेस के गढ़ रहे विधानसभा क्रमांक-3 से कमल खिला चुके हैं। अब एक ही परिवार के दो कद्दावर भाइयों की राजनीतिक उड़ान को भाजपा कितनी ढील देगी, यह भविष्य बताएगा। इसी प्रकार देपालपुर से धनाढ्य विशाल पटेल को भाजपा में शामिल करवाकर पार्टी ने स्व. निर्भयसिंह पटेल की राजनीतिक विरासत के भी दो टुकड़े कर दिए हैं जिसका दूसरा टुकड़ा विधायक मनोज पटेल होंगे। विशाल और मनोज की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के वरदहस्त के चलते मनोज पटेल अब तक विशाल पटेल से जमकर लोहा लेते थे किंतु अब न तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है और न ही उनका हस्तक्षेप वर्तमान शासन बर्दाश्त करेगा। ऐसे में विशाल पटेल के भाजपा में आने और संजय शुक्ला के मित्र होने का लाभ तो उनको मिलेगा।

जहां तक सुरेश पचौरी की बात है तो वे कभी जननेता नहीं रहे। यहां तक कि अपने जीवन में दो चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, वे बुरी तरह हारे हैं। मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए उन पर टिकट के बदले धन लेने के भी आरोप लगे थे किंतु गांधी-नेहरू परिवार से नजदीकी उनको बचा ले गई। हालांकि यह भी सच है कि प्रदेश में कांग्रेस की सर्वाधिक दुर्गति भी उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुई। उन्हें कांग्रेस ने हमेशा ब्राह्मण नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है किंतु वे कभी प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता नहीं बन पाए। भाजपा ने पचौरी का आगमन मात्र कांग्रेस का मनोबल तोड़ने हेतु किया है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के भाजपा में आने से धार में रंजना बघेल परिवार को परेशान होना स्वाभाविक है क्योंकि अब तक परिवार के नखरे झेलती रही भाजपा में अब एक सशक्त चहेरा है जो धार में पार्टी की राजनीति को धार दे सकता है। भोपाल से कैलाश मिश्रा का हित सुरेश पचौरी तय करेंगे क्योंकि राजधानी में भाजपा में एक अनार सौ बीमार वाले हाल हैं और कई कद्दावर नेता पद की लालसा में पार्टी की ओर ताक रहे हैं। खैर, ये सभी तो देर-सवेर कुछ न कुछ पा ही लेंगे, किंतु खोया तो जनता का विश्वास है कि जो एक-दूसरे के खिलाफ खड़े थे, आज साथ-साथ खड़े हैं।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने राहुल गांधी के करीबी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का मुखिया यह सोचकर बनाया था कि वे वरिष्ठ एवं युवा नेताओं के बीच समन्वय स्थापित कर पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे किंतु उनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी नेताओं में अजीब सी बेचैनी दिख रही है। वरिष्ठ उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं तो युवाओं को उनका बॉस रूप अधिक पसंद नहीं आ रहा। स्थिति यह हो गई है कि इंदौर के होने के बाद भी उन्हें इंदौर के दो बड़े कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की भनक तक नहीं लगी। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह तो पहले से ही पार्टी को आंखें दिखाने लगे थे। भाजपा अरुण यादव पर भी डोरे डाल रही है। अभी स्थिति यह है कि कांग्रेसी प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें जीतने और 6 पर कड़ी टक्कर देने का दंभ भर रहे हैं किंतु लड़कर जीतेगा कौन, इस पर मौन साधे हुए हैं।

● **कुमार विनोद**

हर बूथ पर 51 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने का टारगेट

भाजपा ने हर बूथ पर 51 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने का टारगेट तय किया है। पूरे मप्र के वोट शेयर की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव (2024) में भाजपा ने 68 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मप्र में 58 प्रतिशत वोट मिले थे। इस वोट शेयर को 10 प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा दूसरे दलों के प्रभावशाली नेताओं से लेकर बूथ स्तर पर तक वोटर्स को जोड़ने में जुटी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का अटूट विश्वास है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता भाजपा जॉइन कर रहे हैं। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं में उन्हीं को लिया जाता है जो पहली बार भाजपा जॉइन कर रहे हों। यानी दूसरे दल के ऐसे नेता जो एक बार भाजपा जॉइन कर उसे छोड़ चुके हैं, उनको पार्टी में दोबारा नहीं लिया जाता है। भाजपा की जॉइनिंग टोली भाजपा के ऐसे नेताओं की भी घरवापसी करवा रही है जो पहले भाजपा में रह चुके हैं, लेकिन नाराजगी या टिकट ना मिलने की वजह से दूसरी पार्टी में चले गए थे।

असर दिखाएगी न्याय यात्रा?

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गत दिनों राजस्थान में प्रवेश कर गई। इससे पहले यह यात्रा मप्र में थी। राहुल गांधी ने मप्र और केंद्र सरकार को लेकर खूब आरोप-प्रत्यारोप लगाए। हालांकि दूसरे चरण में यह यात्रा चंबल और मालवा की 7 लोकसभा सीटों तक ही सिमट गई। अब देखना यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस का कितना प्रतिशत वोट बैंक बढ़ता है।

मप्र में 2 मार्च से शुरू हुई न्याय यात्रा में विशेष फोकस चंबल और मालवा पर रखा गया। चंबल की बड़ी सीटों को देखें तो राहुल गांधी मुरैना से प्रदेश में आए थे और उन्होंने ग्वालियर तथा गुना लोकसभा सीट पर रोड शो करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सके। ये सभी सीटें भाजपा के बड़े नेताओं के कब्जे में हैं और लगता नहीं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में यहां कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी। फिर भी राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस का दावा है कि उसका वोट प्रतिशत यहां बढ़ेगा। इसके बाद राहुल शाजापुर से उज्जैन लोकसभा सीट पर आए और दो दिन इस सीट पर बिताए। अगले दिन उन्होंने धार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बदनावर विधानसभा में सभा की। यहां से भाजपा से गए कद्दावर नेता भंवरसिंह शेखावत विधायक हैं। शेखावत को इंदौर लोकसभा से लड़ाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रतलाम लोकसभा सीट के सैलाना में भी एक बड़ी सभा की। चंबल की 3 और मालवा की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कितना दम मारती है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा का क्या असर होता है, यह तो वक्त ही बताएगा।

मप्र में राहुल गांधी की यात्रा 5 दिनों में 9 जिले और 7 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी के अलग-अलग रंग नजर आए। वे सेना में भर्ती की चाहत रखने वाले युवाओं से मिले, तो किसानों के साथ खाट पंचायत की। भगवान महाकाल की शरण में गए तो यात्रा के रूट में हो रही एक शादी में शामिल हो गए। एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को अमरूद भेंट किए तो वे अमरूद के बगीचे में पहुंच गए। पहले दिन राजस्थान के धौलपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना जिले की सीमा में पहुंची। डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में राहुल ने कहा- भाजपा और आरएसएस देश में नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा- देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई हो रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में जाति जनगणना की बात कही। राहुल ने नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी को भी दोहराया।

दूसरे दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कहा- आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह पाकिस्तान की तुलना में दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश-भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा हैं। उन्होंने कहा- अगर मोदी सरकार अरबपतियों के लाखों-करोड़ों का कर्ज माफ कर सकती है, तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती? राहुल ने कहा- भाजपा सरकार ने बड़े-बड़े अरबपतियों का लाखों-करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। ये जो कर्ज का पैसा था, वो देश के लोगों का था, जिसे टैक्स से जुटाया गया था। इससे पहले, राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से संवाद किया। उन्होंने मोहना में रोड शो किया।

तीसरे दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुना और राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंची। इससे पहले, राघौगढ़ में रोड शो किया। राघौगढ़ से ब्यावरा जाते समय एक शादी में भी शामिल हुए। संयोग से दूल्हे का नाम भी राहुल निकला। ब्यावरा के भाटखेड़ी में किसानों के साथ खाट पंचायत की। उन्होंने खाट पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनीं। यहां हाईवे के पास टेंट लगाया था, जिसमें करीब 100 खाट लगाई गई थीं। राहुल गांधी ने रोड शो और नुक्कड़ सभाएं भी कीं। चौथे दिन यात्रा ने शाजापुर से मक्सी होते हुए उज्जैन में प्रवेश किया। यहां राहुल ने महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान गणेश मंडपम में राहुल के सामने मोदी-मोदी के नारे लगे। इसके बाद खुली जीप में रोड शो किया। सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा- जो डरते हैं, नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। यात्रा के दौरान एक भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर कहा- सोना बनाओ। राहुल बोले- धन्यवाद, अगली बार सोना लेकर आऊंगा।

● **रजनीकांत पारे**

न्याय यात्रा से कमलनाथ के विधायक लापता

मप्र में गत दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे थे। राहुल की न्याया यात्रा उज्जैन भी पहुंची थी। राहुल की यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन इस यात्रा से कमलनाथ और उनके बेटे समेत छिंदवाड़ा के सातों कांग्रेस विधायक गायब दिखाई दिए। बताया गया कि कमलनाथ सीईसी की बैठक के लिए गए थे। राहुल की यात्रा से पिता-पुत्र और 7 विधायकों के गायब होने को लेकर फिर से दोनों के भाजपा में जाने की अटकलों को हवा मिल गई है। हालांकि नकुलनाथ छिंदवाड़ा में कह चुके हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे हैं, वह कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन राहुल की यात्रा से कमलनाथ की दूरी बनाने से राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। क्योंकि उज्जैन ही नहीं बल्कि कमलनाथ मप्र में राहुल की पहली यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि बदनावर रैली में कई विधायक मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस ने सभी नेताओं और विधायकों को राहुल गांधी की मप्र में अंतिम न्याय यात्रा में शामिल होने को कहा था, लेकिन कमलनाथ-नकुलनाथ समेत छिंदवाडा जिले के सभी 7 विधायक राहुल की अंतिम न्याय यात्रा से नदारत दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ी सेंधमारी कर 7 पार्षदों को भाजपा में शामिल करा लिया। राहुल गांधी की यात्रा से कमलनाथ के गायब रहने को लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर लिखा कि कमलनाथ जी उड़ गए। कहा गया था कि वह पूरे मार्च में न्याय यात्रा के साथ रहेंगे। सच्चाई यह है कि वह पहले दिन आए, अगले दो दिन गायब रहे। वह राहुल गांधी के साथ महाकाल मंदिर गए और फिर गायब हो गए। नकुलनाथ को पहले दिन के बाद से यात्रा में नहीं देखा गया है।

चमकदार आंकड़ों के बीच उभरती चिंताएं

जीडीपी में देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में तेजी से बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी तिमाही के लिए 6.5 प्रतिशत और एसबीआई रिसर्च में 6.7 से 6.9 प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया था। लेकिन एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के ताजा आंकड़ों में अनुमान से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है जिसका श्रेय विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इंफ्रा सेक्टर की ग्रोथ पिछले 15 महीने में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी में कोर सेक्टर की वृद्धि दर सालभर पहले के मुकाबले 3.6 प्रतिशत रही है। कोर सेक्टर में शामिल 8 प्रमुख बुनियादी क्षेत्र में से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी में कमजोरी का असर ओवरऑल ग्रोथ पर पड़ा है।

मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक कोर सेक्टर की ग्रोथ 7.7 प्रतिशत रही है। इसी तरह जीडीपी के चमकदार आंकड़ों के बीच खेती और खपत का हाल अब भी बेहाल है। ग्रामीण मांग बहुत कमजोर है, शहरों में भी कोई तेजी नहीं है। जब तक खपत की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, निजी निवेश में भी तेजी नहीं आएगी। सुखद है कि खुदरा महंगाई दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम घटने से निचले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि मूल्य सूचकांक का बढ़ना घटना अगर खाद्य उत्पादों पर ही निर्भर रहता है तो यह संतोषजनक नहीं है। असली मामला औद्योगिक उत्पादन की दर का है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सालाना आधार पर पिछले वर्ष 3.8 प्रतिशत रह गई, इसका कारण था खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। मालूम हो कि वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दुर्बल आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक उदारीकरण शुरू करने की वकालत की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक सुधारों के कारण ही आज भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्हीं सुधारों के कारण तब के 270 अरब अमेरिकी डॉलर से चलते-चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था (जीडीपी) चार खरब अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है।

यद्यपि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में जीडीपी को आधार बनाया गया है जबकि दूसरा पक्ष यह है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विकसित होने में हमने खुद ही 2047 तक का समय सोचा है। जिस इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत उससे बहुत नीचे है। अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग 2100 डॉलर है जबकि आज उच्च आय वाला देश उसे माना जाता है जहां प्रति व्यक्ति आय 12000 डॉलर से अधिक हो। यानी अभी हम उच्च आय वाले देश के छठवें हिस्से के बराबर हैं। विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के 197 देशों की सूची में भारत का स्थान 142वें पायदान पर है।

आर्थिक सुधार और विकास की तेज रफ्तार के जरिए भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को आज से 10 गुना अधिक का बनाना है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक इसके लिए हमें 8 प्रतिशत से ऊपर की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में यह लक्ष्य देश ने हासिल किया है, मगर जब हम वित्तीय वर्ष की आर्थिकी का लेखा-जोखा करते हैं और इसकी संभावनाओं को टटोलते हैं तो कुछ विलोम स्थितियां न सिर्फ सचेत करती हैं बल्कि नित नए आंकड़े चौंकाते भी हैं। मोटे तौर पर विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल रही हो और नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132वीं है, जबकि दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के मामले में भारत 149वें स्थान पर है। विज्ञान की पढ़ाई में भारत की युवा पीढ़ी लगातार पिछड़ रही है। शोध में पैसे की कमी से प्रतिभा पलायन बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। डिजिटल भारत के साथ-साथ स्टार्टअप और स्वरोजगार के नारों के बावजूद देश में बेरोजगारी और महंगाई बदस्तूर कायम है। आर्थिक विषमता की खाई भी लगातार चौड़ी हो रही है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

कृत्रिम मेधा के बल पर समस्याओं को दूर करने की क्षमता

गिनती के समृद्ध लोगों के साथ देश में 5 किलो राशन प्राप्त कर रही लगभग 81 करोड़ की बड़ी आबादी की तुलना नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और इंडियन एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि देश की शीर्ष 500 निजी कंपनियों का कारोबार 2023 में 231 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि देश पूरे वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पादन करता है यह उसका 71 प्रतिशत बैठता है। ऐसे में जब एक बड़ा हिस्सा कुछ गिनी-चुनी बड़ी कंपनियों को ही चला जाएगा तो देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले लघु और कुटीर उद्योगों का विकास कैसे होगा? देश में मेधावी लोगों की कमी नहीं है। डिजिटल भारत में कृत्रिम मेधा के बल पर समस्याओं को दूर करने की क्षमता है। हमें आंकड़ों के स्वप्नजीवी माहौल से बाहर निकालकर सच को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी का भला नहीं होने वाला है। अब जबकि आम चुनाव की दुंदुभी बजने को है, जरूरी आर्थिक मुद्दों को भी राजनीतिक चाशनी में लपेटकर परोसा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि मौजूदा सरकार जहां आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो आर्थिक सुधारों की व्यवस्था करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कामकाज पर श्वेत पत्र लाकर न सिर्फ उंगली उठाती है बल्कि आर्थिक प्रगति में बाधा डालने का ठीकरा भी उन्हीं के कार्यकाल पर फोड़ती है?

कब मिलेगा मंत्रियों को जिलों का प्रभार!

राज्य मंत्रियों के पास कोई काम नहीं

दो माह में राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों ने काम का बंटवारा तक नहीं किया है। इसकी वजह से राज्य मंत्री बेकाम बैठे हुए हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। वे सिर्फ स्वतंत्र प्रभार वाले विभाग तक सीमित हैं। जो विभाग कैबिनेट मंत्रियों के पास हैं, उनका कोई काम भी उन्हें अब तक नहीं दिया गया है। इसकी वजह से उनके पास भी अन्य विभागों की कोई फाइल नहीं आ रही है। सरकार में दो उपमुख्यमंत्री समेत 20 कैबिनेट मंत्री हैं। 6 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। जबकि 4 राज्य मंत्री हैं। राज्यमंत्रियों को अभी तक कैबिनेट मंत्रियों ने काम का बंटवारा भी नहीं किया है। राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल इस विभाग के मंत्री हैं। अभी तक शुक्ल ने पटेल को कोई अधिकृत काम नहीं सौंपा है। इसी तरह प्रतिमा बागरी को नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग का कोई काम नहीं मिला है। दिलीप अहिरवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी कोई काम नहीं दिया है। राज्यमंत्री राधा सिंह को भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने काम का बंटवारा नहीं किया है। इसकी वजह से उनके पास संबंधित विभागों की फाइलें तक नहीं आ रही हैं।

मप्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सत्ताधारी भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। चुनाव को लेकर सत्ता और संगठन की बैठकें हो रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं। इसी के चलते अब लोकसभा चुनाव तक मंत्रियों के जिलों के प्रभार के मामले अटक सकते हैं। सत्ता-संगठन के चुनाव में जुटने से ऐसे आसार बने हैं। दो महीने बाद भी मंत्रियों को जिलों के प्रभार नहीं बंटे हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों की जिम्मेदारी तय होना है। प्रभार नहीं बंटने से मंत्रियों का फोकस अपने गृह जिलों पर ज्यादा है। जिन जिलों से मंत्री नहीं वहां मॉनीटरिंग में कमी है।

अब प्रदेश में नई सरकार बने हुए दो माह होने को हैं, लेकिन अब तक जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं मिल सके हैं। जिस तरह से जिलों में संपर्क निधि की राशि जारी करने के अधिकार हाल ही में कलेक्टरों को दिए गए हैं, उससे साफ हो गया है कि फिलहाल सरकार अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने की जल्दबाजी में नहीं है। इसकी वजह से अब प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जिलों के प्रभार के लिए अभी इंतजार और करना होगा। माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही जिलों के प्रभार के मामले में फैसला किया जाएगा। इसकी वजह बताई जा रही है कि सरकार फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी को नाराज करने के मूड में नहीं है। उधर, सरकार का भी पूरा फोकस अब लोकसभा चुनाव पर हो गया है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, अगले पखवाड़े में चुनावी तारीखों की घोषणा होने की संभावनाएं हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके 6 दिन बाद 31 दिसंबर 2023 को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया था। विभाग मिलने के बाद से ही मंत्री जिलों के प्रभार के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी मंत्री को किसी भी जिले का प्रभार नहीं सौंपा है। हालांकि कद्दावर मंत्रियों के नाम बड़े जिलों के प्रभार के लिए चर्चा में जरूर बने हुए हैं, लेकिन इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रक्रिया शुरू करने के किसी को निर्देश नहीं दिए हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले जिलों का प्रभार मिलने की उम्मीद पाले बैठे मंत्रियों को फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सरकार में प्रदेश के चारों प्रमुख नगरों से पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इन सभी मंत्रियों को उनके कद के हिसाब से जिलों के प्रभार देने होंगे, हालांकि यह मंत्री अपने-अपने जिलों के प्रभार पाने की अधिक इच्छा रखते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें एक से अधिक जिलों के प्रभार दिए जाएंगे, जिनमें उनके गृह जिले शामिल नहीं होंगे। जिलों का प्रभार मंत्रियों को नहीं मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं के जिले स्तर के भी काम नहीं हो पा रहे हैं। जिन जिलों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है, उन जिलों में तो फिर भी कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो रही है, लेकिन जिन जिलों से कोई मंत्री नहीं हैं उन जिलों में कार्यकर्ता अपने काम के लिए परेशान हैं। उन्हें अपने कामकाज को लेकर भोपाल तक दौड़ लगानी पड़ रही है।

31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष के पहले सांसदों और विधायकों को मिलने वाली जनसंपर्क निधि के उपयोग को लेकर नया आदेश हुआ है। इसके लिए प्रभारी मंत्री की ओर से राशि जारी किए जाने का प्रावधान है। लेकिन, अब प्रभारी मंत्री के पावर कलेक्टरों को ट्रांसफर किए गए हैं। हर विधानसभा के लिए सांसदों और विधायकों को मिलने वाली जनसंपर्क निधि की राशि के वितरण के पावर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा कलेक्टरों को दिए गए हैं। जीएडी ने इसको लेकर जारी आदेश में कहा है कि वर्ष 2023-24 के जनसंपर्क निधि की राशि वितरण के अधिकार कलेक्टरों को दिए जाते हैं। आदेश के बाद अब कलेक्टर सांसदों और विधायकों की ओर से जनसंपर्क निधि के अंतर्गत राशि आवंटित करने को लेकर की जाने वाली अनुशंसा के आधार पर राशि वितरण का निर्णय ले सकेंगे।

जिला स्तर पर डीएमएफ, जिला योजना समिति समेत अन्य जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है। इसके साथ ही जिला स्तर पर किए जाने वाले तबादले, कानून-व्यवस्था और बड़े निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय बैठकों में किया जाता है। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठकों में भी प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता महत्वपूर्ण रहती है। प्रभारी मंत्री पर ही जिला स्तर पर आम जनजीवन से जुड़ी हर एक्टिविटी का ध्यान रखने और उसमें सरकार की भागीदारी करने की जिम्मेदारी होती है।

● **विकास दुबे**

बिजली घरों की राख बनी खतरा

कोयला संकट के बीच बिजली उत्पादन प्रभावित होने के बीच एक नया संकट भी तेजी से बढ़ा है। प्रदेश के ताप बिजली घरों से बड़ी मात्रा में निकलने वाली फ्लाई ऐश (राख) के निपटान में गंभीर कोताही बरती जा रही है। यहां से निकली खतरनाक राख हवा-पानी और मिट्टी को प्रदूषित करने के अलावा प्लांट के आसपास के क्षेत्र में तबाही का कारण भी बनती है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें, तो फ्लाई ऐश के इस्तेमाल के मामले में प्रदेश औसत रूप से काफी पीछे है।

प्रदेश के कोयला आधारित 50 प्रतिशत सरकारी पावर प्लांट फ्लाई ऐश का भंडार खत्म नहीं कर पा रहे हैं। यही फ्लाई ऐश बारिश के दिनों में बहकर नदी, नालों, तालाबों, खेतों तक पहुंच रही है, जो उन्हें उथला कर रही है। पीसीची के वैज्ञानिक और पर्यावरण मामलों के जानकार लगातार चिंता जता रहे हैं कि फ्लाई ऐश के स्टॉक को खत्म नहीं किया तो पर्यावरण पर खतरा और बढ़ेगा। बांधों, नदियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उल्लेखनीय है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्व में गाइडलाइन जारी कर कह चुका है जितनी फ्लाई ऐश उत्पन्न हो रही है, उसका शत-प्रतिशत उपयोग करें। उसे पर्यावरण में बिल्कुल भी न मिलने दें।

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिलने वाले कोयले में राख की मात्रा 30 से 40 प्रतिशत तक होती है। ताप बिजली घरों में कोयले के जलने से निकलने वाली राख में ब्लैक कार्बन, आर्सेनिक, पीएम 2.5, बोरान, क्रोमियम और सीसा होता है। इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा भी होती है। यदि यह राख उड़ती है तो इसके कण पानी और दूसरी सतहों पर जम जाते हैं। इसी कारण जल, वायु और मृदा प्रदूषण बढ़ता है। सिंगरौली क्षेत्र फ्लाई ऐश का दुष्प्रभाव झेलता रहा है। यहां थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख को डम्प करने के लिए बनाए बांधों के टूटने की घटनाओं से जानमाल सहित कई तरह के नुकसान हो चुके हैं। अप्रैल 2020 में निजी थर्मल पावर प्लांट का राखड़ डैम टूटने से पांच ग्रामीणों की मौत हो गई थी। कई मकान ढह गए थे। कई एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा था। इसके बावजूद प्रशासन राख के सुरक्षित निपटान के लिए समुचित व्यवस्था करने में नाकाम है। इससे पहले सिंगरौली में ही एनटीपीसी और एस्सार पावर प्लांट के राख के डैम ढह चुके हैं। रिहंद नदी के बांध में राख की बड़ी मात्रा मिलने से संकट गहरा गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार इस गंभीर संकट से आंखें फेरे हुए हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सरकारी, निजी पावर प्लांट ने शत-प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग कर लिया है। इसका उपयोग ईंट, पेवर ब्लॉक, टाइल्स निर्माण समेत सीमेंट कारखानों में किया जाता है। एनटीपीसी सिंगरौली ताप विद्युत गृह की बिजली उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है और यहां फ्लाई ऐश 76,63,620 मीट्रिक टन उत्पन्न होती है, लेकिन उसका केवल 37 फीसदी ही उपयोग हो पा रहा है। इसी तरह श्री सिंगाजी खंडवा में 37,90,190.278 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है और 42 फीसदी का ही उपयोग होता है। अमरकंटक प्लांट चचाई में फ्लाई ऐश 3,15,207.28 मीट्रिक टन में से 54 फीसदी, संजय गांधी, शहडोल में फ्लाई ऐश 21,93,518 मीट्रिक टन में से 55 फीसदी, हिंडालको इंडस्ट्रीज, सिंगरौली में फ्लाई ऐश 11,82,016 मीट्रिक टन में से 79 फीसदी, एनटीपीसी, गाडरवारा में फ्लाई ऐश 18,34,836 मीट्रिक टन में से 80 फीसदी, झाबुआ पावर, सिवनी में फ्लाई ऐश 10,82,349 मीट्रिक टन में से 92 फीसदी और बीएलए पावर, नरसिंहपुर में फ्लाई ऐश 1,29,664 मीट्रिक टन में से 96 फीसदी का उपयोग हो रहा है।

वहीं जेपी निगरी, सिंगरौली के 14,54,697 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 100 फीसदी, महान एनरजेन, सिंगरौली के 9,08,471 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 100 फीसदी, जेपी बीना के 8,00,707 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 100 फीसदी, एनटीपीसी खरगोन के 13,09,698 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 102 फीसदी, एमबी पावर, अनूपपुर के 2,11,747 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 102 फीसदी, सासन पावर, सिंगरौली के45,99,580 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 109 फीसदी और सतपुड़ा, सारणी के 9,27,613 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश में से 136 फीसदी का उपयोग हो रहा है। बीते एक वर्ष में देशभर के 179 बिजली घरों से 222.8 मिलियन टन फ्लाई ऐश निकली। विभागीय दावा है कि इसका 92 प्रतिशत का निपटान कर लिया गया। हैरानी की बात है कि पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश के अवैज्ञानिक निपटान से वायु, जल और मृदा प्रदूषण के संबंध में सरकार के पास कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

● **लोकेश शर्मा**

जानमाल का नुकसान

प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख आम लोगों के जीवन में जहर घोल रही है। क्षेत्र में विकास और रोजगार का वादा करने वाले ये पावर प्लांट अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। झाबुआ पावर प्लांट से प्रभावित गांव बिनेकी के किसान बताते हैं कि पावर प्लांट के आसपास अधिक मात्रा में चारागाह की जमीन है। इस जमीन पर उगी घास और पेड़-पौधों पर भी राख उड़कर जमा होती है, राख वाली घास खाने से कई पशुओं की मौत हो रही है। शर्तों को ताक पर रखकर झाबुआ थर्मल पावर प्लांट की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एवी करियर फ्लाईऐश को गलत जगह पर डंप कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान करते समय भूमि का सीमांकन कराकर फील्ड बुक तैयार करने एवं मुनारे लगवाने पर ही अनुमति दी गई, लेकिन इस शर्त का पालन प्लांट प्रबंधन नहीं कर रहा है। माना जाता है कि भारत में मिलने वाले कोयले में 30-40 प्रतिशत तक राख की मात्रा होती है। कोयले के जलने से निकलने वाली इस राख में पीएम 2.5, ब्लैक कार्बन, आर्सेनिक, बोरान, क्रोमियम तथा सीसा तो होता ही है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा भी बहुत होती है। हवा में कई किलोमीटर तक उड़ते हुए इस राख के कण पानी और दूसरी सतहों पर जम जाते हैं।

औद्योगिक हब बनेगा मप्र

देश का हृदय प्रदेश आज कई राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मप्र को औद्योगिक हब बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से 1 और 2 मार्च को उज्जैन में इन्वेस्टर समिट (रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव) का आयोजन किया गया। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य है कि मप्र को रोजगार प्रदेश बनाया जाए ताकि प्रदेश के साथ ही देशभर के लोगों को यहां काम-धंधा मिल सके।

इस बात को लगभग सभी लोग जानते हैं कि उद्योग को प्रोत्साहित करना मप्र सरकार का घोषित उद्देश्य है और इसके कुछ आशाजनक परिणाम भी मिले हैं। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान ऐसा रहे कि प्रदेश पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाए। इस दिशा में मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पहले ही दिन एक लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी और 17 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद भी जगी है। गौरतलब है कि मप्र में नए उद्योगों को लेकर सरकार काफी चिंता रख रही है। मप्र में उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का सरलीकरण कर दिया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि उद्योगों के हब से मप्र का कर्ज उतरेगा।

उज्जैन के भाजपा विधायक अनिल जैन के मुताबिक जिस प्रदेश का औद्योगिक विकास होता है वहां पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होते हैं और प्रदेश के विकास की गति भी तेज हो जाती है। निश्चित रूप से मप्र का औद्योगिक विकास होने से यहां पर स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी। सरकार जिस प्रकार से इन्वेस्टर समेत और उद्योगों को खोलने के लिए अन्य आयोजन कर रही है, वह निश्चित ही सफल होंगे। औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी राजेश राठौर के मुताबिक मप्र में इन्वेस्टर समिट के जरिए नए उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बड़े कदम उठाए जा रहे है। यहां पर उद्योग खोलने की अनुमति लेने के लिए अधिक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योगों को अनुमति मिलेगी। इसके अलावा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 40 फीसदी तक की सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जा रही है। औद्योगिक विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट होना भी बेहद आवश्यक है। इसी दृष्टि से मप्र में 1 लाख इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं जो कि औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मप्र में मजदूर और मालिक के बीच कोई ज्यादा विवादित स्थितियां भी नहीं बनती है। इस दृष्टि से भी मप्र में उद्योगों की संभावनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से नए उद्योग लगाने को लेकर भी पूरी पारदर्शिता के साथ नई नीति के तहत काम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों की भूमिका मामला रहता है। सरकार की ओर से इसे पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। उद्योगपतियों को सारी औपचारिकता निभाने के बाद 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन

इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण

कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के लिए आवंटन-पत्र प्रदान किए। इन इकाइयों द्वारा कुल 12 हजार 170 करोड रुपए से अधिक का निवेश कर 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों को प्रतीक स्वरूप भूमि आवंटन-पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पीएम कुसुम योजना में भी उद्योगपतियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। यह योजना नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुल 10 हजार 64 करोड़ रुपए लागत की 61 इकाइयों का सिंगल क्लिक से भूमिपूजन और लोकार्पण किया। ये इकाइयां प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित की गई हैं। साथ ही नई इकाइयां भी प्रारंभ हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में भी नई इकाइयों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद प्रदेश में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की जाएंगी। कॉन्क्लेव के दौरान ही औद्योगिक इकाईयों के लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनेक देशों को आश्चर्यचकित कर रही है।

अलॉटमेंट हो सकता है। इसके बाद में नए उद्योग का कार्य शुरू कर सकते हैं। यह सुविधा मप्र सरकार की ओर से काफी सरलीकरण के साथ उद्योगपतियों के बीच प्रस्तुत की जा रही है।

उज्जैन के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में औद्योगिक घरानों ने निवेश का पिटारा खोल दिया। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे बिजनेसमैन से वन टू वन चर्चा की और उन्हें मप्र में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया। इस कॉन्क्लेव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएमश्री एयर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। यह एयर एम्बुलेंस दूर-दराज के इलाकों से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा लोगों ने किया पार्टिसिपेट किया। यूके, फिजी, जर्मनी, जापान, जामिया, मलेशिया समेत 12 से अधिक देशों के लोग इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में अडाणी और पेप्सीका समूह बड़े निवेशक साबित हुए। अडाणी एंटरप्राइजेज डायरेक्टर प्रणव अडाणी ने मप्र में 75 हजार करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। प्रणव अडाणी ने कहा कि वे 5 हजार करोड़ की लागत से उज्जैन, इंदौर और भोपाल को मिलाकर महाकाल एक्सप्रेस बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि इंवेस्टर्स यहां आएं, महाकाल के दर्शन करें और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित हों, लोगों को रोजगार भी दें। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री के 4.0 कालखंड में जी रहे हैं। जब बिजली से इंडस्ट्री चली तो उसे 2.0 कहा गया। आईटीआई, कम्प्यूटर का दौर शुरू हुआ तो एक्सपर्ट्स ने इसे 3.0 कहा। अब एआई और रोबोटिक्स, एआरवीआर का दौर है तो हम किसी भी मामले में पीछे नहीं गए, सभी आगे बढ़ते गए। मेघवाल ने कहा कि हमने मोदीजी के आने के बाद इंडस्ट्री के लिए कानून बनाए। कुछ कानूनों में बदलाव किए हैं। आजादी के पहले के कई कानून लोगों को और बिजनेसमैन को परेशान करते थे। हमने ऐसे साढ़े पंद्रह सौ से ज्यादा कानून खत्म कर दिए हैं। हम मीडिएशन लॉ लाए हैं। अब प्रयास है कि सभी मामले कोर्ट न जाएं। दो झगड़ने वाले भाई अपना मीडियाटर तय कर दें जो ये कहेगा वो हम मान लेंगे। इससे लोगों का समय बचेगा।

एमएसएमई के प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने कहा कि हम निवेशकों की समस्या का समाधान भी करेंगे। हमारी पॉलिसीज डायनेमिक डॉक्यूमेंट होंगी, जिन्हें समय-समय पर सुधारा जाएगा। युवा स्टार्टअप में रूचि दिखा रहे हैं। उज्जैन और रीवा में ही 2000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इस अवसर पर बिजनेसमैन ने अपने निवेश की जानकारी दी। इप्का लैबोरेटरी के एमडी अजीत कुमार ने कहा कि मप्र में हम चार दशकों से हैं। सात यूनिट में काम हो रहा है। अगले दो साल में 1100 करोड़ का निवेश करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के पदाधिकारियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में निवेश करने को लेकर उद्योगपतियों के अच्छे रूझान हैं। हमने उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। उज्जैन के साथ पूरा मप्र उद्योग नगरी बनेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉन्क्लेव के पहले ही दिन एक लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश राज्य में आया है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मप्र में 75000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5000 करोड़ से उज्जैन, इंदौर और भोपाल को मिलाकर महाकाल एक्सप्रेस बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने समिट में कई विकास कार्यों और निवेश के भूमिपूजन और लोकार्पण किए हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप सत्र में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में 10064 करोड़ निवेश से स्थापित होने वाली 61 इकाईयों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। यहां 17 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है।

● **अरविंद नारद**

इंदौर को मिला निवेश

उज्जैन में आयोजित समिट में हालांकि एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के दावे किए गए हैं, मगर पहले ही दिन 10 हजार करोड़ से अधिक की 61 इकाइयों का सिंगल क्लिक के जरिए भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया, वहीं 283 उद्योगों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन-पत्र सौंपे गए। इंदौर के 43 उद्योगों को भी 470 एकड़ जमीन के आवंटन-पत्र मुख्यमंत्री द्वारा सौंपे गए, जिनमें साढ़े 5 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं समापन अवसर पर 300 करोड़ रुपए से अधिक के 42 प्रोजेक्टों के भूमिपूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किए गए। समिट में सबसे अधिक 75 हजार करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा अडाणी समूह के निदेशक प्रणव अडाणी ने की, वहीं 10 हजार करोड़ से अधिक के लोकार्पण-भूमिपूजन भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते हो रहा है। बातें कम, काम ज्यादा के मंत्र का उपयोग करते हुए देश की प्रगति की यात्रा जारी है। उज्जैन कॉन्क्लेव से एक लाख करोड़ के व्यवसाय और उद्योग का इतिहास बन रहा है और 250 से अधिक उद्योगों को मौके पर ही जमीन का आवंटन किया गया, जिससे 20 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार हासिल हो रहा है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने औद्योगिक विकास के लिए प्रचुर संसाधन, व्यापक वन क्षेत्र और कृषि उत्पादनों में भी बेहतर निवेश संभावनाओं की जानकारी दी। वहीं प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने प्रजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरह प्रदेश में निवेश की बेहतर स्थिति है। मुख्यमंत्री ने कहा- उज्जैनी समिट में सबसे ज्यादा निवेश तत्कालिक रूप से इंदौर के हिस्से में ही आया। 43 उद्योगों में 5570 करोड़ के निवेश से 13200 रोजगार अवसर मिलेंगे, वहीं 470 एकड़ जमीन आवंटित भी की गई। इसके अलावा उज्जैन में 4740 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही दिन मिल गया।

महिलाएं चलाएंगी उपार्जन केंद्र

महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही मप्र सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए सक्षम और सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हैं। इसके अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों का गठन और प्रशिक्षण उपरांत उपक्रमी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए समाज की आर्थिक गतिविधियों की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास विशेष रूप से किया जा रहा है। इस कड़ी में इस बार भी महिलाओं को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य सौंपा जाएगा। यानी प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं व्यापारियों की जगह लेंगी और सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदकर अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ साल से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला स्वसहायता समूहों को गेहूं उपार्जन का काम दिया जा रहा है। इस बार भी उन्हें यह काम दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। समूहों को इस साल खरीदी का काम देने को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। पिछले दिनों संगठनों की महिलाओं ने खाद्य मंत्री को ज्ञापन दिए थे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने चार साल पहले निर्णय लिया था कि ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला समूहों को गेहूं और धान उपार्जन का काम दिया जाएगा।

बड़े पैमाने पर कृषि उपज की खरीद-फरोख्त में परंपरागत रूप से पुरुषों का दबदबा रहा है। इस काम में ज्यादातर धनी साहूकार और स्थानीय राजनीतिक नेता जुड़े होते थे, लेकिन प्रदेश सरकार की पहल पर व्यापारियों की जगह ग्रामीण महिलाएं ले रही हैं। खरीद केंद्रों के प्रबंधन से जुड़ने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। पिछले सालों से करीब 400 समूहों को विभिन्न जिलों में खरीदी की जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन इस साल समूहों के स्थान पर ग्राम संगठनों को काम दिए जाने का निर्णय लिया गया। ग्राम संगठन का गठन एक हजार महिलाओं से होता है जबकि समूहों में 15-20 महिलाएं होती हैं। आजीविका मिशन में पांच लाख स्वसहायता समूह हैं। हाल ही में खाद्य और पंचायत तथा ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों की बैठक बुलाई गई थी। इस मौके पर ग्रामीण आजीविका मिशन ने खरीदी के संबंध में अपना पक्ष रखा था कि महिला समूह गेहूं-धान की खरीदी का काम अच्छे से कर रही हैं, उन्हें गेहूं खरीदी का काम दिया जाना चाहिए। वहीं, खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने भी महिला समूहों को खरीदी केंद्र बनाने का आश्वासन दिया था। खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा है कि उन महिला समूहों को खरीदी की सहमति दी जाएगी जिन्होंने एक साल पहले एनआरएलएम में पंजीयन कराया हो। समूहों अथवा ग्राम संगठनों के खाते में कम से कम दो लाख रुपए जमा होने चाहिए। समूह में सभी सदस्य अथवा पदाधिकारी महिलाएं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल गेहूं और धान उपार्जन के नाम पर कुछ महिला समूहों की खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां मिली थीं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं घर से बाहर निकलकर न केवल परिवार चलाने में अपना योगदान दे रहीं हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं। वे छोटे-छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्वयं को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बना रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाने में महिला स्वसहायता समूह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ साल से महिला स्वसहायता समूह अनेक क्षेत्रों के साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन केंद्र का संचालन भी कर रहे हैं।

नारी तू नारायणी, इस जग का आधार... किसी रचना की इन पंक्तियों को सच साबित कर रही हैं मप्र की कुछ महिलाएं। हजारों की संख्या में इन महिलाओं की सक्रियता से पुरुषों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश के 52 जिलों की 4500 से अधिक महिलाओं ने सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदा है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ घर का खर्च भी चला रही हैं। खरीद के दौरान सरकार की ओर से निर्धारित, न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा ध्यान रखा जाता है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि महिलाओं के मोर्चा संभालने के बाद खरीद प्रक्रिया से करप्शन खत्म हो रहा है। सबसे उत्साहित करने वाली बात ये है कि स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। कृषि उत्पाद खरीदने में महिलाओं के जुड़ने से किसानों और बाजार के बीच बिचौलिए की भूमिका में मुनाफाखोरी करने वाले प्राइवेट व्यापारियों पर शिकंजा कस रहा है। साहूकारों की धौंस खत्म होने का ही परिणाम है कि पूरे मप्र में अब तक चार सैकड़ा से अधिक महिला समूह सीधा किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के काम में शामिल हो चुके हैं। मप्र में चल रहे इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण महिलाओं को सरकारी गोदामों के आसपास कृषि उत्पाद खरीदने के लिए परचेज सेंटर यानी खरीद केंद्र आवंटित किए जाते हैं। इन केंद्रों पर किसानों से गेहूं, चना और सरसों खरीदे जाते हैं। राज्य सरकार की मशीनरी महिलाओं की मदद करती है। सरकार का खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग किसानों की उपज ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाले वाहनों का इंतजाम करता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

सरकार गेंहू पर देगी प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस

उधर, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों को गेहूं पर 2275 रुपए समर्थन मूल्य के साथ ही प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। साथ ही किसानों को खाद और उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखकर फिर से मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है। उसमें 850 करोड़ रुपए की निशुल्क शासकीय प्रत्यावृति स्वीकृत की गई है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के लिए 30 हजार करोड़ की राशि शासन ने तय की है। इसको कैबिनेट ने मंजूर किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों के लिए गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया था। अभी किसानों का गेहूं का उपार्जन मूल्य 2275 है। इसमें 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे। इस तरह 2400 रुपए क्विंटल किसानों को मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसला किसानों को खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हुआ है।

अब चुनाव बाद लगेगा करंट

व्यवसायिक बिजली 15 प्रतिशत तक महंगी

अब बिजली औसत 3.86 प्रतिशत तक महंगी होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से नया टैरिफ प्लान तैयार किया गया है, जो कि 15 मार्च या उसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू हो जाएगा। इसमें व्यवसायिक बिजली पर 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी। मकान में दो या तीन कमरे का उपयोग होम-स्टे में बदला गया है और बाकी के हिस्से में परिवार रह रहा है, उसे भी व्यवसायिक मानकर बिलिंग की जा रही है। मकान को होम-स्टे में बदला गया है और कनेक्शन घरेलू है तो व्यवसायिक दर से एक साल तक की बिलिंग भी की जा रही है। औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो तरह का टैरिफ होगा, जिसमें शाम 5 बजे के बाद सामान्य से बढ़ी हुई दरों पर बिजली दी जाएगी। साथ ही नीयत प्रभार व ऊर्जा प्रभार में भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि 50 यूनिट खपत से लेकर 300 यूनिट या इससे अधिक खपत पर 427 रुपए से लेकर 680 रुपए तक चुकाना होंगे। बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री संजीव कुमरावत ने बताया कि मकान को होटल, रेस्टोरेंट या दुकान या होम-स्टे में बदलने वालों को कमर्शियल कनेक्शन लेना होगा, जिसके तहत ही बिलिंग होगी। विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित टैरिफ प्लान 15 मार्च से लागू हो जाएगा। इसमें मकान निर्माण के लिए एलवी अनुसूची में प्रायोज्य दर का 1.25 गुना रहेगा। सामाजिक, वैवाहिक व धार्मिक समारोह के दौरान लिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर 77 प्रति किलोवाट स्वीकृत भार प्रति 24 घंटे की अवधि के लिए रहेगा।

हर साल उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का भार डालने वाले नियामक आयोग ने चुनावी साल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने 2024-25 के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी किया है उसमें किसी भी तरह के टैरिफ को नहीं बढ़ाया है। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। कम से कम जुलाई-अगस्त तक उपभोक्ताओं को फिलहाल बिजली बिल के करंट से छुटकारा मिल गया है। मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने इस बार सिर्फ नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों की बिजली को महंगा किया है। इससे आम आदमी पर कोई बोझ नहीं आएगा। पहले नगर पंचायतों को 5.68 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिलती थी। इसे अब 5.86 रुपए प्रति यूनिट कर दिया है। वहीं ग्राम पंचायतों को 5.40 रुपए प्रति यूनिट में बिजली दी जाती थी। अब ग्राम पंचायतों को 5.55 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं इनके सरचार्ज में भी इजाफा किया गया है। सरचार्ज में 10 रुपए का इजाफा किया गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश की बिजली कंपनियां फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) के नाम पर हर महीने बिजली का टैरिफ बढ़ा रही हैं। प्रदेश में एफपीपीएएस पिछले साल अप्रैल से लागू हुआ है। पहली बार बिजली कंपनियों ने 8.41 फीसदी सरचार्ज वसूला था। केंद्र सरकार ने घाटे के आधार पर फ्यूल एंड पावर पर्चेस एडजेस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) वसूलने के अधिकार बिजली कंपनियों को दिए हैं। चुनावी साल खत्म होने के बाद टैरिफ में भारी-भरकम बढ़ोतरी होना भी तय है। लोकसभा चुनाव के बाद घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियां सरचार्ज बढ़ाएंगी। अभी दो से तीन महीने तो प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत रहेगी। इसके बाद हर महीने लगने वाले सरचार्ज में इजाफा होगा। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में बिजली के टैरिफ में 4 से 5 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।

प्रदेश की बिजली कंपनियों की याचिका की सुनवाई करते हुए मप्र विद्युत विनियामक आयोग ने 2024-25 के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी कर दिया है। नए टैरिफ में इस बार घरेलू, गैर घरेलू, कृषि सहित किसी भी तरह के टैरिफ को नहीं बढ़ाया है। चुनाव के चलते प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को यह राहत मिल गई, जबकि पिछले दो साल में बिजली कंपनियों की याचिका पर बिजली के टैरिफ में 4.29 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। चुनावी साल में हर बार बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल जाती है। पिछले साल मप्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होना था। चुनाव के चलते बिजली कंपनियों ने 1 पैसे का भी सरचार्ज नहीं लगाया है। इससे पहले भी प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते टैरिफ से राहत मिली है। साल 2018 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, तब प्रदेश की बिजली कंपनियों ने घाटा बताते ही बिजली के टैरिफ में 3.9 फीसदी का इजाफा करने की मांग थी, लेकिन विनियामक आयोग ने टैरिफ में इजाफा नहीं किया था। इसी तरह जब साल 2013 में विधानसभा चुनाव होने थे, तब बिजली कंपनियों ने 9.38 फीसदी तक बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की याचिका दायर की थी, लेकिन विनियामक आयोग ने सिर्फ 0.77 फीसदी का मामूली इजाफा किया था।

वहीं अब बिना बिजली जलाए आने वाला बिल नहीं आएगा। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ भी जारी कर दिया है। नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा और इसमें महज 0.07 फीसदी का इजाफा किया गया है। साथ ही आयोग ने बिलों पर लगने वाले मीटरिंग प्रभार और न्यूनतम प्रभार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। बता दें कि ये पहला मौका है जब न्यूनतम प्रभार पहली बार खत्म किया गया है। यानी आपने बिजली नहीं जलाई तो बिल भी नहीं आएगा। उधर टैरिफ में जो 0.07 फीसदी का इजाफा किया गया है वह भी सिर्फ स्ट्रीट लाइट वाली बिजली के लिए किया गया है। यानी आम घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा। घरेलू बिजली के अलावा गैर घरेलू औद्योगिक और कृषि की बिजली घरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी की गई नई दरों में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। अभी इनकी दरें 6.79 रुपए प्रति यूनिट थीं, जिसे बढ़ाकर 6.190 प्रति यूनिट कर दिया गया है। हालांकि, ऐसे चार्जिंग स्टेशन जिनका लोड 112 किलोवाट से ज्यादा है, उन्हें फायदा दिया गया है। ऐसे चार्जिंग स्टेशन को अब 6.96 प्रति यूनिट के स्थान पर 6.90 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

विकास का काम...भोपाल त्राहिमाम

राजधानी को स्मार्टसिटी बनाकर शहर को विदेशों की तर्ज पर हाईटेक सुविधाएं देने के दावे अब भी अधूरे हैं। आलम यह है की 8 साल में 8 सीईओ बदल चुके हैं और तकरीबन 1500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं लेकिन स्मार्ट सिटी अभी भी पाइपलाइन में है। जबकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा किया जाना था। भोपाल में स्मार्ट सिटी के पिछड़ने के पीछे साल दर साल सीईओ का तबादला मुख्य वजह बताया जा रहा है।

मिशन के पहले चरण में भोपाल, इंदौर और जबलपुर का चयन किया गया था। फिर दूसरे फेज में ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन भी शामिल हो गए। राजधानी में स्मार्ट सिटी के लिए पहले शिवाजी नगर में जमीन आवंटित की जा रही थी। इसका रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने काफी विरोध किया। ऐसे में मुख्यमंत्री के दखल के बाद टीटी नगर में स्मार्ट सिटी के लिए 342 एकड़ जमीन आवंटित की गई। यहां प्रोजेक्ट्स को आकार देने के लिए हजार से ज्यादा सरकारी मकानों को खाली कराने और तोड़ने में काफी समय लग गया। फिर टीटी नगर दशहरा मैदान के पास नाले पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर एनजीटी में याचिका लग गई। ट्रिब्यूनल ने कुछ महीने के लिए स्मार्ट सिटी के कार्यों पर रोक लगा दी। यह हटने के बाद दोबारा कार्य शुरू हुए तो फंड की कमी आने लगी। नतीजा, टीटी नगर स्थित स्मार्ट सिटी एरिया में ही कई प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। स्मार्टसिटी के तहत नवाबकालीन सदर मंजिल को बेहद निखार दिया गया, लेकिन टीटी नगर के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आकर स्मार्टसिटी उलझ गई। यहां से कैसे निकलें, फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। मौजूदा स्थिति ये है कि केंद्र और राज्य सरकार से सीधे तौर पर मिले 1500 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए।

जानकारी के अनुसार, 2015 में शुरू हुए स्मार्ट सिटी प्राजेक्ट को 2020 में पूरा किया जाना था। लेकिन स्मार्टसिटी का सपना 8 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। 8 सालों में 8 सीईओ आए और गए। अब अगले सीईओ के तौर पर गत दिनों किरोडीलाल मीना का नाम तय हुआ है। किसी ने 15 दिन काम किया तो कोई सालभर भी नहीं टिका। बीते छह माह से तो बिना सीईओ के ही स्मार्ट सिटी चल रही है। भोपाल स्मार्टसिटी में बीते 8 साल में 8 सीईओ बदल दिए गए। पहले सीईओ चंद्रमौली शुक्ला थे। इनके समय में शुरुआती योजनाओं पर काम हुआ। इसके बाद संजय कुमार, दीपक सिंह, आदित्य सिंह, अंकित अस्थाना, गौरव बैनल, फ्रैंक नोबल और रोशनसिंह को प्रभार मिला। अब किरोडीलाल मीना सीईओ बने है। सीईओ बदलने की अनुमति केंद्र से नहीं लेने पर इस पर भारत सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से आपत्ति भी जताई थी।

स्मार्टसिटी के तहत अंडरग्राउंड वायरिंग करनी थी, ताकि शहर से तारों का मकडजाल खत्म हो सके। भोपाल की नेचुरल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट लाने थे। भोपाल प्लस एप से मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को कारगर ढंग से लागू करना था, ताकि लोग इसकी सहूलियत को समझ सकें। लेकिन हुआ इसके उलट ही। स्ट्रीट लाइटें बंद हो गईं, फुटपाथ उखड़ गए, 5 करोड़ का डस्टबिन प्रोजेक्ट भी बंद हो गया। टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 342 एकड़ में करीब 4 हजार हरेभरे पेड़ों को काट दिया गया। इसमें 45 साल पुराने पेड़ भी थे। मौजूदा स्थिति ये है कि यहां सड़कों का काम भी 60 फीसदी ही हो पाया। प्लॉट महज तीन बिके हैं। कमाई की पूरी योजना इन प्लॉट्स को बेचकर ही तैयार की जा रही है। यहां से 850 पेड़ों की शिफ्टिंग की, लेकिन कलियासोत के जंगल में इन्हें बेतरतीब लगाकर खत्म कर दिया गया। यहां एक पेड़ की शिफ्टिंग पर 12 हजार रुपए से 15 हजार रुपए तक की राशि खर्च की गई।

सदर मंजिल रिनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत करीब 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसे हेरिटेज लुक दिया गया। केबल स्टेब्रिज के लिए जब निगम के पास राशि खत्म हो गई तो स्मार्टसिटी की मद से 34 करोड़ रुपए खर्च कर इसे पूरा कराया गया। टीटी नगर में करीब 3 हजार आवासों के लिए छह बहुमंजिला इमारतें बनाई गईं। यहां सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाए हैं। यहां अटल पथ और स्मार्टरोड शहर की सबसे महंगी सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन ये शुरुआत में ही टूटने लगीं। प्रतिकिमी 20 करोड़ रुपए के बड़े खर्च की सड़कों पर डामर के पैबंद लगाने पड़ रहे। 750 करोड़ रुपए का कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया। यहां से पूरे शहर की व्यवस्था बनानी और निगरानी रखनी थी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। इंटेलीजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से कैमरों की मदद से ट्रैफिक को सुचारू संचालित कराना था, स्थिति ये है कि हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को ही काम देखना पड़ रहा है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

विकास कार्यों की स्थिति

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल में जो काम कराए गए हैं, उनकी स्थिति भी चिंताजनक है। सात खूबियों वाले स्मार्ट पोल से मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, फायर अलार्म सिस्टम का काम करना था। अभी सिर्फ विज्ञापन के बोर्ड लटक रहे हैं। प्लेस मेकिंग के तहत शहर के क्षेत्रों को विकसित करना था। न्यू मार्केट की दो गलियां, लिंक रोड किनारे स्पेस डेवलपमेंट, एमपी नगर में स्मार्ट स्ट्रीट और अन्य काम किए हैं। लिंक रोड किनारे पार्क खराब है। 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद एमपी नगर में स्मार्ट स्ट्रीट टूट-फूट चुकी है। हरियाली और जलस्त्रोतों के संरक्षण के लिए ग्रीन व व्यू मास्टर प्लान बनना था। बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। नर्मदापुरम रोड किनारे स्मार्ट सिटी ने 3 करोड़ से साइकिल ट्रैक बनाया। माय बाइक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। न साइकिलें चल रही हैं और न ट्रैक बचा है। एबीडी-28 सड़कें अधूरी हैं। टीटी नगर के 342 एकड़ में सरकारी आवास तोड़कर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बिना हितग्राहियों से बातचीत किए काम शुरू हुआ। नतीजतन शिकायतों की वजह से यहां बनने वाली छोटी-बड़ी 28 सड़कें अब तक अधूरी हैं।

जंग में भारतीयों की तस्करी

मोटी सैलरी और चमचमाती लाइफस्टाइल वाली नौकरी... ये लालच देकर धोखे से भारतीयों को रूस-यूक्रेन की जानलेवा जंग में शामिल कराया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में रूस पहुंचने से पहले लोगों को यह नहीं बताया जाता कि उन्हें रूस-यूक्रेन जंग में भेजा जाएगा। रूस पहुंचने के बाद उनसे एक कॉन्ट्रेक्ट साइन कराया जाता है, जो कि रूसी भाषा में होता है। कॉन्ट्रेक्ट में लिखा होता है कि वे रूसी सेना के साथ हेल्पर के तौर पर काम करेंगे, जिसके बदले उन्हें हर महीने 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह गिरोह पर अब सीबीआई की नजर में आ गया है। इसलिए धरपकड़ के लिए 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक ऐसे 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सोशल मीडिया चैनलों, परिचितों और एजेंटों के माध्यम से मोटी सैलरी वाली नौकरियों के झूठे वादे कर युवाओं को रूस ले जाया गया।

दरअसल, रूस-यूक्रेन जंग में अब तक दो भारतीयों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। इनमें से एक गुजरात के सूरत तो वहीं दूसरा तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था। आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए पहुंचे कैसे और किन परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई। पहला केस सूरत के हेमिल अश्विन भाई मंगूकिया का है। इनकी जंग लड़ते हुए मौत हो गई थी। हेमिल रूस के लिए लड़ रहे थे। दावा है कि उनकी मौत यूक्रेन के एक मिसाइल अटैक में हुई। 23 साल के हेमिल रूस की सेना से **बतौर हेल्पर** जुड़े थे। वहां उन्हें 50 हजार रुपए महीने की सैलरी पर रखा गया था। हेमिल ने आखिरी बार 20 फरवरी को अपने परिवार से बात की थी। मंगूकिया के चचेरे भाई दर्शन ने दावा किया था कि रूस जाने के लिए हेमिल ने एक एजेंट को 3 लाख रुपए दिए थे। वहां उन्हें 50 हजार रुपए की सैलरी की जॉब मिली थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनकी कंपनी ने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि उन्हें वॉरजोन में तैनात किया जाएगा और हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। मंगूकिया ने एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए रूस में नौकरी के लिए आवेदन किया था। सूरत से चेन्नई पहुंचे हामिल को सीधे मॉस्को पहुंचा दिया गया था। दूसरा केस हैदराबाद के मोहम्मद असफान का है। अफसान के भाई इमरान का कहना है कि अफसान 9 नवंबर को बाबा व्लॉग (यू ट्यूब चैनल) के जरिए रूस गया था। वह एजेंट रमेश, नाजिल, मोइन और खुशप्रीत के कॉन्टेक्ट में था। रमेश और नाजिल चेन्नई के रहने वाले हैं, जबकि खुशप्रीत पंजाब का है। मैंने कुछ दिनों पहले इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि अफसान को गोली लगी है, वह घायल है।

अफसान के भाई इमरान कहते हैं कि भाई को गोली लगने की बात सुनकर मैं डर गया और मैंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क किया। मैं ओवैसी साहब से मिलने पहुंचा और वहां से ही इंडियन एंबेसी के इमरजेंसी नंबर पर फोन किया, ताकि उनकी बात करा सकूं। जब मेरा कॉल रिसीव हुआ तो मैंने उनसे अफसान से जुड़ा कोई अपडेट बताने के लिए कहा। फोन को एक मिनट तक होल्ड रखने के बाद एंबेसी के अधिकारी ने मुझसे कहा कि अफसान की मौत हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। मैंने ओवैसी साहब से बात कराई तो उन्हें भी यही बात बताई गई। धोखाधड़ी कर भारतीयों को रूस भेजने के सिर्फ ये दो मामले ही नहीं हैं। ये दो मामले इसलिए चर्चा में आ गए, क्योंकि इन दोनों की ही मौत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सामने आया था, जो रूस-यूक्रेन जंग में फंसे 7 भारतीयों ने जारी किया था। जिन 7 भारतीयों का वीडियो सामने आया है, उनमें से 5 पंजाब और 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। वीडियो में सभी मिलिट्री डिजाइन वाली जैकेट और कैप पहने नजर आए। 6 लोग पीछे खड़े थे, जबकि एक वीडियो बना रहा था। ये सभी लोग नया साल मनाने रूस गए थे। वहां उन्हें एक एजेंट मिला था, जिसने उन्हें पहले तो रूस घुमाया-फिराया और फिर बेलारूस घुमाने की बात कही। बेलारूस में एजेंट ने उनसे और पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए तो एजेंट सभी को बेलारूस हाईवे पर छोड़कर चला गया। यहां पुलिस ने उन्हें पकड़कर रूस की आर्मी को सौंप दिया।

दरअसल, जिस बाबा व्लॉग के बारे में इमरान बात कर रहे हैं, वह एक यूट्यूबर है। जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को यह बताता है कि लोग कैसे अलग-अलग देशों में जाकर काम कर सकते हैं और उसके बदले अच्छा-खासा पैसा कमा सकते हैं। अब तक उसने अपने चैनल पर 148 वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक महीने पहले न्यूजीलैंड विजिट का एक वीडियो अपलोड किया गया है। बाबा व्लॉग खुद के वीडियो का प्रचार-प्रसार करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करता है। इस यूट्यूबर समेत कई फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

रूसी आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा

वीडियो जारी करने वालों ने दावा किया था कि रूस की आर्मी ने उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा, और कहा कि या तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और आर्मी में हेल्पर की जॉब करो या फिर 10 साल की जेल होगी। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उन्होंने बताया, हमें थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग दी गई और यूक्रेन भेज दिया। हमारे साथ और भी लोग थे, जिन्हें फ्रंटलाइन में डाल दिया गया। हमसे भी कहा गया। हमें ठीक से बंदूक भी पकड़नी नहीं आती और हमें फ्रंटलाइन में डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस में फंसे ज्यादातर भारतीय उप्र, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 29 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि रूस में करीब 20 भारतीय नागरिकों ने भारत वापसी के लिए मदद मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया था कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने को लेकर रूस के अधिकारियों से भी बात की है। उन्होंने लोगों से युद्धग्रस्त इलाकों में न जाने की अपील भी की।

परियोजनाओं के सहारे वोट पर नजर

जल्द लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है। इससे पहले मप्र सरकार उन लाखों किसानों को साधने में जुट गई है, जो केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजना के जरिए लाभांवित होंगे। तय किया गया है कि जिन जिलों और 11 लोकसभा क्षेत्रों से यह नदियां और इनके प्रोजेक्ट जुड़ेंगे वहां के लोगों को योजना के बारे में विस्तार से बताया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 मार्च को मां नर्मदा के जल को कलश में प्रवाहित कर केन-बेतवा एवं पार्वती-कालीसिंध-चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल कलश यात्रा के पांच रथों को झंडी दिखाकर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर से रवाना किया। यात्रा के अंतर्गत एक सौ एलईडी प्रचार रथ, केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लाभान्वित 17 जिलों के लगभग 3600 ग्रामों में प्रचार-प्रसार के लिए भेजे गए। कार्यक्रम में परियोजना के लाभ एवं जल के महत्व पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बताया गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और भाजपा के मोहन सरकार के कार्यकाल में अगले पांच साल में तीन हजार गांवों के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा।

खास बात यह है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है उसमें इंदौर, उज्जैन और धार लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर बाकी टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, गुना, मुरैना, राजगढ़, झाबुआ, देवास के लिए भाजपा ने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है। 44,605 करोड़ रुपए की केन-बेतवा लिंक परियोजना में केंद्र सरकार का अंश 90 प्रतिशत और मप्र-उप्र सरकारों का अंश 5-5 प्रतिशत रहेगा। केन-बेसिन से उप्र में 2.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। वहीं केन-बेसिन से मप्र में 4.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। जबकि बेतवा बेसिन से मप्र में 2.06 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। परियोजना से छतरपुर जिले के 688 गांवों को फायदा होगा। वहीं टीकमगढ़ जिले के 132, दमोह जिले के 156, निवाड़ी जिले के 80 और पन्ना जिले के 326 गांवों को फायदा होगा। इस परियोजना में 5 जिलों के कुल 1382 गांवों को फायदा मिलेगा और कुल 8 लाख 14 हजार 964 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। इस लिंक परियोजना से खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह लोकसभा क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फायदा होगा। उन्हें पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

निवाड़ी से कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का लाभ दिए जाने के नाम पर भाजपा ने पता नहीं कितने चुनाव में फायदा ले लिया। लेकिन, जमीन पर कुछ नहीं आया। अब एक बार फिर भाजपा केन-बेतवा के नाम पर कलश यात्रा निकालने जा रही है। सरकार ने किसानों के 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए धान खरीदी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। लाड़ली बहना को तीन हजार रुपए देने का जो वादा किया उसका क्या हुआ। इसलिए भाजपा के लोग जब केन-बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर कलश यात्रा निकालें या कोई इवेंट करें और लोगों के बीच आएं तो किसान उनसे सवाल जरूर करें कि जो वादे नौजवानों से रोजगार के लिए किए थे, जो वादे किसानों से किए और जो वादे महिलाओं के साथ किए, उसका क्या हुआ। इसका जवाब नहीं लिया तो फिर ये छलावा कर चुनाव के समय खुद का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। पार्वती-चंबल-कालीसिंध नदी लिंक परियोजना की लागत 75,000 करोड़ रुपए है। परियोजना से 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। राजस्थान में सिंचाई एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर, मप्र का सिंचाई एरिया 2.8 लाख हेक्टेयर होगा। इस परियोजना में 90 प्रतिशत केंद्र व 5-5 प्रतिशत मप्र-राजस्थान को खर्च करना होगा। पार्वती, कालीसिंध-चंबल परियोजना से गुना-शिवपुरी, मुरैना, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, राजगढ़, झाबुआ लोकसभा क्षेत्रों को फायदा पहुंचेगा।

गौरतलब है कि अलग-अलग परियोजनाओं से मिलकर नदी जोड़ो परियोजना बनेगी। कुंभराज 1 परियोजना से गुना जिले के 139 गांव की 50821 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। कुंभराज 2 परियोजना से गुना के 137 गांवों की 53075 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। लखुंदर बैराज परियोजना से आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, जिलों की 136 गांव की 61966 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। रणजीत सागर परियोजना से राजगढ़ जिले की 137 गांवों की 75918 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बचोरा परियोजना से इंदौर और उज्जैन जिले के 21 गांवों की 4407 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।

● **राकेश ग्रोवर**

चुनाव के बाद केन-बेतवा के शिलान्यास की संभावना

मप्र और उप्र की बहुप्रतिक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। इस परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी का निर्धारण जून तक फाइनल होगा, तब तक वहां भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि शिलान्यास का कार्यक्रम लंबे समय से टल रहा है। भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। कुछ ही दिनों के अंदर प्रधानमंत्री का मप्र का कोई दौरा कार्यक्रम घोषित नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजना का शिलान्यास करते भी हैं तो उनका वर्चुअल जुड़ना ज्यादा संभव होगा। लेकिन इस बड़ी परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री वर्चुअल नहीं करेंगे। इसके चलते लोकसभा चुनाव के बाद परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है। दौधन बांध निर्माण के लिए पांच मार्च तक टेंडर डाले गए। इसके बाद टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया जाएगा। कंपनियों का कार्य अनुभव और समस्त दस्तावेजों के परीक्षण के बाद टेंडर की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अब तक 11 कंपनियां हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, दिलीप बिल्डकान, एसटीएन सहित अन्य कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

बुलंदियों पर पहुंचा बुंदेलखंड

वर्ष 2023 बुंदेलखंड को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला साल साबित हुआ। इस वर्ष योगी सरकार ने बुंदेलखंड में मिशन मोड पर काम किया और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी, जिसने कभी प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक माने जाने वाले इस क्षेत्र को अग्रणी स्थान पर लाने का काम किया। योगी सरकार की ओर से जहां झांसी में नोएडा की तर्ज पर इंडस्ट्रियल सिटी बसाने के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) की स्थापना की गई तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण को भी हरी झंडी मिली। पेयजल उपलब्धता के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के काम यहां पूर्ण होने की अवस्था में पहुंच गए तो डिफेंस कॉरिडोर में बीडीएल ने भूमिपूजन करने के साथ ही यूनिट के निर्माण का काम शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी झांसी की कई परियोजनाएं पूरी हुईं तो पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल आदि के क्षेत्र में इस एक वर्ष में कई बड़े निर्णय सरकार की ओर से लिए गए।

उप्र सरकार ने वर्ष 2023 में झांसी शहर के निकट 33 गांवों में विस्तारित बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, सीईओ के पद पर नियुक्ति करने के साथ ही झांसी जिले में कार्यालय खोलने का प्रस्ताव भी आमंत्रित कर दिया। सीईओ ने झांसी पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया और जमीन अधिग्रहण का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। देश के कई बड़े औद्योगिक समूहों ने उप्र सरकार से बीडा में जमीन आवंटन के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। उप्र सरकार का यह कदम इस क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के लिहाज से बड़ा परिवर्तनकारी निर्णय माना जा रहा है। योगी सरकार की योजना नोएडा की तर्ज पर यहां इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की है, जो बुंदेलखंड के लिए एक नई संजीवनी का काम करेगा।

योगी सरकार का डिफेंस कॉरिडोर भी झांसी के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) की इकाई की स्थापना के लिए वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी थी। वर्ष 2023 में इसकी यूनिट के निर्माण के लिए भूमिपूजन के साथ ही स्थापना का काम शुरू कर दिया गया। उप्र सरकार झांसी के गरौठा में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने में जुटी है। इस क्षेत्र में कई अन्य इकाइयों की स्थापना के लिए उप्र सरकार के सामने प्रस्ताव आए हैं। बड़ी-बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां जब अपनी यूनिट स्थापित करेंगी तो रोजगार के इतने साधन उपलब्ध होंगे कि युवाओं को नौकरी के लिए बुंदेलखंड से बाहर जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी।

समग्र विकास पर सरकार का फोकस

योगी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास को केंद्रित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। निरंतर सभी जिलों में बड़ी गौशालाओं का निर्माण, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट सिटी और माइनिंग फंड के माध्यम से सुविधाओं का विकास, अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं की बढ़ोत्तरी, कृषि से संबंधित योजनाओं में कृषकों को सहायता, असहाय और कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक सहायता सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उन पर नियमित निगरानी पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। शासन के शीर्ष अफसरों और मंत्रियों के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरंतर इस क्षेत्र का दौरा कर योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेते रहे हैं। इटावा से चित्रकूट तक 296 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को सोलर एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया जा रहा है। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए की स्वीकृति, झांसी और चित्रकूट में एयरपोर्ट को मंजूरी, जालौन में 350 करोड़ से 79 एकड़ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 68.83 करोड़ की स्वीकृति, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, चित्रकूट के रानीपुर में उप्र के चौथे टाइगर रिजर्व की स्थापना, चित्रकूट में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा, 1400 करोड़ की लागत से झांसी से खजुराहो तक 4 लेन हाईवे का निर्माण प्रगति पर है।

ललितपुर जिले में पांच गांव में 1472 एकड़ क्षेत्रफल पर बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। मास्टर प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के लिए यूपीसीडा ने काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में 300 एकड़ क्षेत्रफल में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिहाज से डीपीआर तैयार किया जाना है। उप्र सरकार ललितपुर जिले को जेनरिक दवाओं के हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है। इस पार्क को विकसित करने के लिए उप्र सरकार कई प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों को नॉलेज पार्टनर बना रही है।

बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थलों को एडॉप्ट-ए-हेरिटेज योजना के तहत विकसित करने के लिए सरकार ने कई स्थलों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। देश के कई प्रतिष्ठित होटल समूहों ने इन स्थानों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस स्थानों की तस्वीर बदलती दिखाई देगी। एडॉप्ट-ए-हेरिटेज योजना के माध्यम से झांसी के बरुआसागर किला, राम जानकी मंदिर गरौठा, पठामढ़ी का मंदिर गरौठा और बंजारी का मंदिर एवं बेर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। इनके अलावा बुंदेलखंड के रॉक कट गुफाएं देवगढ़ ललितपुर, सुमेरगढ़ का प्राचीन मंदिर ललितपुर, सोमनाथ मंदिर मानिकपुर चित्रकूट, खाकरा मठ चरखारी महोबा, रणछोर मंदिर धोजरी ललितपुर, प्राचीन बैठक तालबेहट ललितपुर, चंदेली मंदिर करियारी हमीरपुर, शांतिनाथ मंदिर भरवारा महोबा, शिव मंदिर उल्दना कला ललितपुर, दशरथ घाटी चित्रकूट और खंडेह के मंदिर मौदहा हमीरपुर के लिए प्रस्ताव मंगाए गए। बुंदेलखंड के सभी सातों जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने का काम लगभग अंतिम अवस्था में है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

क्या भाजपा कर पाएगी 400 पार...?

2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा खासी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा ने अबकी बार 400 पार का नारा दिया है और उसे उम्मीद है कि इस बार पार्टी पिछले दो आम चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य को लेकर अलग-अलग बिसात बिछाई है। कई जगह से उसे सीटें बढ़ने की उम्मीद है। उधर, इंडिया गठबंधन भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी मैजिक के सहारे वह लक्ष्य हासिल कर लेगी। लेकिन सवाल उठता है कि भाजपा दक्षिण की लक्ष्मण रेखा को कैसे पार कर पाएगी। और क्या इंडिया गठबंधन का रणनीतिक मुकाबला इस बार फेल हो जाएगा?

● राजेंद्र आगाल

लगातार दो चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा मिशन 2024 के लिए इस कदर उत्साहित है कि उन्होंने अबकी बार 400 पार का नारा दे दिया है। केवल नारा ही नहीं बल्कि इसके लिए पार्टी ने चुनावी चौसर भी बिछा दी है। यह बड़े लक्ष्य वाला मुकाबला इसलिए भी रोमांचक होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले प्रदर्शन के आधार पर विपक्षी खेमा भाजपा के लिए जिन राज्यों को आपदा बता रहा है, भाजपा के रणनीतिकार वहीं सीटें बढ़ाए जाने की गुंजाइश को अवसर के रूप में देख रहे हैं। नई संभावनाओं वाले राज्यों में जिस तरह के राजनीतिक व सामाजिक समीकरण बिठाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनके भरोसे भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि उप्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। केरल में भी नए समीकरणों के साथ भाजपा आजादी के बाद पहली बार खाता खोलने की उम्मीद कर रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो हमेशा मिशन मोड में रहती है। साल के 365 दिन संघ के साथ ही भाजपा की सरकारें और संगठन जनता के बीच काम करते हैं। इसके चलते इन्होंने अपनी जमीन और जड़ें देश के हर घर-घर में जमा ली हैं। अपनी योजनाओं, रणनीति से भाजपा ने हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। खासकर आधी आबादी यानी महिलाओं को तो इस कदर साधा गया है कि उनको मोदी के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि भाजपा पूरे विश्वास के साथ अबकी बार 400 सीटें जीतने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह बेपटरी नजर आ रही है। कांग्रेस में लगातार टूट हो रही है। पार्टी के लोकप्रिय नेता या तो हाशिए पर चले गए हैं या उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो समय चुनाव की रणनीति बनाने का था, उस समय कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस मजबूत कैसे हो सकती है। रहा सवाल इंडिया गठबंधन का, तो नीतीश कुमार के पलायन के बाद गठबंधन पूरी तरह कमजोर हो गया है। यही नहीं गठबंधन के नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर रार अभी भी चल रही है।

भाजपा को बड़ी उम्मीद

उप्र में 71 अकेले और दो सहयोगियों के साथ 73 सीटें जीतकर भाजपा ने 2014 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2019 में सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद भाजपा सहयोगी अपना दल(एस) के साथ 64 सीटें जीतने में सफल रही थी। यहां उसकी नौ सीटें कम हो गई थीं, जिन्हें बढ़ाने के जतन चल रहे हैं। इस बार बसपा ने एकला चलो का नारा दिया है। 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन देख चुकी भाजपा इस बार भी इस गठजोड़ को कोई चुनौती मानकर नहीं चल रही है। वहीं, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से पश्चिम और पूर्वी उप्र में कई सीटों के समीकरण भाजपा अपने पक्ष में मजबूत होते देख रही है। भाजपा के रणनीतिकार सहयोगियों के साथ इस बार 75 का आंकड़ा पार करने की उम्मीद कर रहे हैं।

इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा इस बार 10 से 15 अधिक सीटें जीतने की उम्मीद लगाए है। ममता बनर्जी के विपक्षी गठबंधन से बाहर होकर सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से साफ हो गया है कि इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच होगा। यदि माकपा और कांग्रेस का गठबंधन पिछली बार की तरह बना तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन संदेशखाली की घटना के बाद भाजपा के आक्रामक तेवर ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माकपा व कांग्रेस के लिए ज्यादा जमीन पैर जमाने के लिए छोड़ी नहीं है। यहां पिछली बार भाजपा को 18 और तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं, वहीं कांग्रेस दो सीटों पर सिमटी थी। भाजपा पहले से यहां 33 सीटों पर मजबूती से लड़ने और उनमें 25 से अधिक सीटे जीतने की रणनीति पर काम कर रही थी, लेकिन संदेशखाली की घटना और शाहजहां शेख के सीबीआई की हिरासत में आने के बाद बदले माहौल को देखते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार का मानना है कि इस बार भाजपा यदि 32-33 सीटें भी जीत ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

ओडिशा में भले ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी हो, लेकिन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि किसी न किसी रूप में बीजद और भाजपा का साथ आना तय है। लोकसभा की 21 सीटों वाले ओडिशा में भाजपा के पास अभी 8, बीजद के पास 12 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। यदि बीजद और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सभी 21 सीटें राजग के खाते में आ सकती हैं। इसी तरह से तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीआरएस का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने की उम्मीद है। बीआरएस के दो सांसद भाजपा में आ चुके हैं और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि बीआरएस के चार-पांच और सांसद संपर्क कर रहे हैं। वह पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने पार्टी के पुराने नेताओं में नाराजगी के डर से उन्हें चुनाव के पहले शामिल करने से इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा 4, कांग्रेस 3 और बीआरएस 10 सीटें जीती थी। भाजपा के

पुरानों पर भरोसा, नए को भी मौका

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी तक जितने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उससे साफ है कि पार्टी ने जहां पुरानों पर भरोसा जताया है, वहीं नए प्रत्याशियों को मौका दिया है। 15 मार्च तक भाजपा ने कुल 267 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें आसनसोल से पवन सिंह और बाराबंकी सीट से उपेंद्र रावत ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। इस तरह पार्टी ने 265 लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें भाजपा ने पुराने और नए चेहरों के लिए 50:50 का फॉर्मूला अपनाया है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने अपने दो लिस्टों में 265 सीट पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने पहली लिस्ट में 195 सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया था, जिसमें 33 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे थे। इसके बाद दूसरी लिस्ट में 72 सीट पर कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं, जिनमें से 30 सांसदों के मौजूदा टिकट काटे हैं। इस तरह भाजपा ने अपनी दोनों ही लिस्ट में 63 मौजूदा सांसद के टिकट काटे हैं जबकि 140 सांसदों को रिपीट किया है। भाजपा के अभी तक घोषित उम्मीदवारों का विश्लेषण करते हैं तो दिखता है कि 265 सीटों में से 203 सीट पर उसका कब्जा रहा है और 63 सीट 2019 में वो जीत नहीं सकी थी। इस तरह पार्टी ने अपने 21 फीसदी मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट काट दिए हैं जबकि करीब 50 फीसदी सीटों पर मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बना दिया है।

मप्र में आरएसएस से जुड़े साढ़े चार लाख मुस्लिम

लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस भी अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से एक्टिव है। संघ के अनुषांगिक संगठन अपने-अपने कार्यक्षेत्र में दिए गए टारगेट पर काम कर रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मप्र में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। मुस्लिम मंच का दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रवादी विचारधारा से मप्र के करीब साढ़े चार लाख मुस्लिम जुड़े हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश पदाधिकारी तौफीक अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। बीते आठ माह से मंच की विचारधारा से मुस्लिमों को रूबरू कराने का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक साढ़े चार लाख से अधिक मुस्लिम संगठन से जुड़े। उन्होंने बताया कि यदि बीते विधानसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा में यह बात सामने आई कि मप्र के मुस्लिम मतदाताओं ने राष्ट्रवाद को वोट दिया। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी प्रभावित होकर संघ के साथ जुड़ रहे हैं। मंच का दावा है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, बुरहानपुर, नीमच समेत अन्य जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम संघ से जुड़े हैं।

रणनीतिकारों का मानना है कि बीआरएस की काफी कम सीटें आएंगी, वहीं कांग्रेस व भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। नई परिस्थितियों में भाजपा अपने दम पर तेलंगाना में 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है।

भाजपा और खासकर राजग के लिए ओडिशा के बाद सबसे बड़ा बूस्टर डोज आंध्रप्रदेश से मिल सकता है। 2019 में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) राजग से बाहर थी और लोकसभा की 25 सीटों वाले आंध्रप्रदेश में भाजपा खाता तक खोलने में विफल रही थी। इस बार तेदेपा राजग में आ चुकी है और भाजपा को छह सीटें गठबंधन में मिल रही हैं। पिछली बार अकेले दम पर तेदेपा तीन सीट ही जीत पाई थी। इस बार राजग गठबंधन से वाईएसआर कांग्रेस को तगड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। भाजपा यहां गठबंधन के सहयोगियों के साथ 15 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। आंध्रप्रदेश की तरह भाजपा 2019 में तमिलनाडु और केरल में भी खाता खोलने में विफल रही थी। तमिलनाडु में 39 में से 38 सीटें द्रमुक और कांग्रेस के साथ उनके सहयोगियों को मिली थीं, जबकि 2014 में इसके ठीक उल्टा परिणाम आया था। तब भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन सभी 39 सीटें जीतने में सफल रहा था। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच चुनाव दर चुनाव इस तरह प्रदर्शन लंबे समय से होता रहा है। तमिलनाडु की पुरानी परंपरा को देखते हुए इस बार एआईएडीएमके गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एआईएडीएमके ने राजग से नाता तोड़ लिया है। जयललिता और के करुणानिधि जैसी बड़ी शख्सियत के अभाव में होने जा रहे इस चुनाव में जमीनी मुद्दे हावी रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के लोगों के साथ दिल के तार जोड़ने और तमिल संस्कृति व विरासत को सहेजने की कोशिशों के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई के जमीनी स्तर किए गए कामों को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। एआईएडीएमके पेन्निरसेल्वम गुट के साथ भाजपा समझौता करने की कोशिश कर रही है। वहीं, तमिल मनीला कांग्रेस राजग में आ चुकी है। भाजपा नेता अभी तक जीती जाने वाली सीटों के बारे में खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि 2019 तक इस बार वह शून्य पर आउट नहीं होगी।

केरल में तीसरी ताकत का उभार

आईएनडीआईए में साथ-साथ और केरल में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस व सीपीएम के बीच भाजपा तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं की संतानों को शामिल कराकर भाजपा ने वामपंथी गठबंठन के खिलाफ खाली विपक्ष के स्थान को भरने की कोशिश शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को शामिल कर भाजपा ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। मुस्लिम वोटों को साथ लेने की कांग्रेस और सीपीएम के बीच मची होड़ के बीच भाजपा ईसाई वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। लोकसभा की कुल 20 सीटों वाले केरल में भाजपा चार-पांच सीटों पर गंभीरता से लड़ रही है और इस बार खाता खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत से भी भाजपा को तीन-चार अतिरिक्त सीटें मिलने की उम्मीद है।

कब-कब बड़े बहुमत की सरकार

आजादी के बाद से अब-तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और दिलचस्प बात ये है कि लगभग आधी बार यानी 8 दफा मुख्य विपक्षी पार्टी 50 से नीचे सीटों पर सिमट गई। 2014 के चुनाव में मोदी लहर आई और कांग्रेस हवा हो गई। मोदी लहर की आंधी में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। भाजपा ने सत्ता की हैट्रिक लगाने के साथ-साथ 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए गठबंधन के लिए अबकी बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है। भाजपा दोनों टारगेट को पूरा करने के लिए अपने गठबंधन के सियासी कुनबा बढ़ाने के साथ-साथ विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं को भी अपने पाले में करने में जुटी है। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, जबकि 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए है।

कांग्रेस 2014 और 2019 का चुनाव बुरी तरह हार चुकी है और अब 2024 का चुनाव उसके लिए करो या मरो से कम नहीं है। ऐसे में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया, जिसका पहिया चुनाव से पहले ही पंचर हो गया। 2024 के रणभूमि में उतरने से पहले ही इंडिया गठबंधन से कई दलों ने किनारा कर लिया है। विपक्षी गठबंधन के शिल्पकार रहे नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं, तो पश्चिम

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एकला चलो की राह पर कदम बढ़ा चुकी हैं। इस तरह विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी भी अपनी उलझन को सुलझाने में जुटा है, लेकिन वो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इस बार कांग्रेस 40 के आंकड़े को भी नहीं छूने वाली है। भाजपा ही नहीं इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद ममता बनर्जी भी कांग्रेस के लिए ऐसी ही बात कह चुकी हैं।

44 पर सिमटी कांग्रेस

आजादी के बाद से देश में अब-तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं और दिलचस्प बात ये है कि लगभग आधी बार यानी 8 दफा मुख्य विपक्षी पार्टी 50 से नीचे सीटों पर सिमट गई। अब तक के इतिहास में कांग्रेस महज एक बार 50 सीट क्रॉस नहीं कर सकी, वो भी 2014 के लोकसभा चुनाव में। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, जिस तरह से आज के समय है। पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली थीं और मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआई को मात्र 16 सीटें मिली थीं। 1957 में कांग्रेस ने 371 सीटों पर जीत दर्ज की थी और सीपीआई को 27 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 11 सीटों का फायदा हुआ था। साल 1962 में कांग्रेस को 361 सीटें और सीपीआई को 29 सीटें मिली थीं। इसके बाद 1967 में कांग्रेस की सीटें घटकर 283 हो गई थीं, लेकिन उसे जीत जरूर मिल गई थी और बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, जबकि मुख्य विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी बनी, लेकिन महज उसे 44 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

साल 1971 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोबारा बढ़त हासिल करते हुए 352 सीटों पर जीत दर्ज की थी और मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीएम 25 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं, 1980 में कांग्रेस को 351 और विपक्ष जनता पार्टी (सेक्युलर) को 41 सीटें मिली थीं और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत हासिल की थी। इस बार उसे सबसे ज्यादा 404 सीटों पर विजय पताका फहराने का मौका मिला था और मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) बनकर उभरी थी। उसे 30 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि 2014 के चुनाव में मोदी लहर आई और कांग्रेस हवा हो गई। मोदी लहर में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और ये आजादी के बाद उसकी सबसे बड़ी हार थी। 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में महज 44 सीटों पर ही सिकुड़ गई। भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 282 सीटों पर अपना परचम लहराया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 50 सीटों का आंकड़ा पार किया, लेकिन 52 सीट पर ही रुक गई। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है और भाजपा लगातार दो चुनाव जीत चुकी है और अब सत्ता की हैट्रिक लगाने की जुगत में है।

कांग्रेस के लिए मोदी-ममता की भविष्यवाणी

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस 40 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी हाल ही में अलग हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में ही बता दिया था कि बंगाल से आपको चुनौती ममता बनर्जी से मिलने जा रही है, ऐसे में कांग्रेस 40 का आंकड़ा छू भी नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 सीटों पर जीत हासिल कर ले। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही ममता बनर्जी कांग्रेस को 40 पार करने की चुनौती दे चुकी हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा में कहा था कि उन्होंने कांग्रेस को 300 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसको कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। अब मुझे संदेह हो गया है कि 2024 में कांग्रेस क्या 40 सीटें भी जीत पाएगी? कांग्रेस 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी भी सीटें देशभर में नहीं जीत सकी थी कि संसद में नेता प्रतिपक्ष बना सके। कांग्रेस 2014 में 44 तो 2019 में 52 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस के सामने अब तीसरी बार चुनौती खड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ममता ने जिस तरह से भविष्यवाणी करने का काम किया है, उससे लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत सकेगी? अब कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय राजनीति में दखल बढ़ने के बाद से कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। 2024 में भाजपा से मुकाबले के लिए हर एक समझौता भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू है, उससे लोकसभा चुनाव की राह और भी मुश्किल होती जा रही है।

दक्षिण की सीटें बढ़ाए कांग्रेस

2019 में कांग्रेस दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में खाता भी नहीं खोल सकी थी। 2014 में भी लगभग यही स्थिति थी। इसके अलावा उप्र, मप्र, बिहार में कांग्रेस को एक-एक सीट मिली थी, जबकि छत्तीसगढ़ में दो लोकसभा सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा उत्तर भारत में काफी मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर भारत में कांग्रेस का धीरे-धीरे सिमटना उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है।

दक्षिण के राज्यों में भले ही कांग्रेस अपना दायरा बढ़ा रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत जीते बिना काम नहीं चलेगा इसलिए कांग्रेस उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस उत्तर भारत में कमजोर स्थिति में है, जिसके चलते सहयोगी दलों के बैसाखी के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कांग्रेस खुद को ज्यादा मजबूत मान रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है, जबकि तमिलनाडु में सरकार में भागीदार है। राहुल गांधी ने केरल को अपना सियासी ठिकाना बना रखा है। इस तरह कांग्रेस की कोशिश दक्षिण से अपनी सीटें बढ़ानी हैं, लेकिन भाजपा भी दक्षिण पर फोकस कर रही है और अपना सियासी कुनबा भी बढ़ा रही है। अब देखना है कि 2024 में कांग्रेस क्या 50 के पार होगी या फिर 40 सीटों पर सिमट जाएगी?

तेलंगाना की चुनौती

तेलंगाना एक राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य की स्थापना के बाद से राजनीति पर हावी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का दबदबा

खत्म हो रहा है और कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापस आ चुकी है। बीआरएस नेता राजशेखर रेड्डी का जादू काम नहीं कर रहा है। 2019 के चुनावों में राज्य की 17 में से भाजपा को 4, कांग्रेस को 3, बीआरएस को 8 और उसके सहयोगी ओवैसी की पार्टी को 2 सीटें मिली थीं। गौर करने लायक बात ये है कि भाजपा को करीब 20 प्रतिशत, कांग्रेस को 30 प्रतिशत और बीआरएस को 44 प्रतिशत वोट मिले थे। कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को बदलने की कोशिश की है। बीआरएस की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसका जितना खेत उसको उतना मुआवजा थी। इसके चलते बड़े किसानों को सरकार से ज्यादा और छोटे, गरीब किसानों को कम मुआवजा मिलता था। रेवंत रेड्डी ने छोटे और गरीब किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की नई नीति शुरू की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का समर्थन बढ़ गया है। ओवैसी की एआईएमआईएम और बीआरएस अब भी साथ हैं। कांग्रेस अब राज्य में 10 से 13 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। यह तभी हो सकता है जब बीआरएस और भाजपा दोनों की सीटें कम हों।

कहां जाएगा आंध्रप्रदेश?

आंध्रप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का कोई खास वजूद नहीं बचा है। राज्य में दो मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां हैं- सत्तारूढ़ वाईआरएस कांग्रेस और विपक्षी तेलुगु देशम। 2019 के लोकसभा चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस को 50 प्रतिशत वोट और राज्य की 25 सीटों में से 22 और तेलुगु देशम पार्टी को 40 प्रतिशत वोट और 3 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को एक प्रतिशत से कुछ अधिक और भाजपा को एक प्रतिशत से भी कम वोट मिला था। इस बार भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी और अभिनेता पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच समझौता हो गया है। भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। समझौते के मुताबिक टीडीपी 17, भाजपा 6 और जनसेना 2 सीटों पर लड़ेगी।

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को पार्टी अध्यक्ष बनाकर

अपनी खोई हुई ताकत को फिर से बटोरने का दांव फेंका है। जगनमोहन पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी के पुत्र हैं। वाईएसआर की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज जगनमोहन ने पिता के नाम पर अलग पार्टी बना ली। आंध्र और तेलंगाना के विभाजन और हैदराबाद में आंध्र को हिस्सा नहीं मिलने से नाराज लगभग पूरी की पूरी कांग्रेस जगनमोहन के साथ चली गई। शर्मिला के आने से कांग्रेस चर्चा में आ गई है, लेकिन चुनाव में फायदा मिलना आसान नहीं है। भाजपा के साथ समझौता नहीं होने से जगनमोहन का नुकसान हो सकता है।

भाजपा का ईसाई दांव

केरल में पैर जमाने की कोशिश भाजपा लंबे समय से कर रही है। राज्य की आबादी में करीब 51 प्रतिशत हिंदू, 49 प्रतिशत ईसाई और मुसलमान हैं। मुसलमान आमतौर पर कांग्रेस और ईसाई वाम मोर्चा के साथ हैं। इसके चलते भाजपा को चुनाव में कोई कामयाबी अब तक नहीं मिली है। कुछ दिनों पहले भाजपा ने केरल में कांग्रेस के बड़े नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पार्टी में शामिल करके पार्टी के आधार को बढ़ाने की पहल शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों के कुछ पादरियों से दिल्ली में मुलाकात की। इसे ईसाईयों को पार्टी की तरफ खींचने का एक प्रयास माना गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में राज्य की 20 में से 19 पर कांग्रेस और 1 पर वाम मोर्चा को जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस की बड़ी जीत का कारण राज्य की वायनाड सीट से पार्टी के नेता राहुल गांधी का चुनाव लड़ना भी माना गया था। वाम मोर्चा, बंगाल और त्रिपुरा में हारने के बाद अपने इस आखिरी गढ़ को बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। वाम मोर्चा ने वायनाड से सीपीएम के बड़े नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनाव में उतारने की घोषणा कर दी है। ये कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए चुनौती है। भाजपा ने यहां 12 सीटों पर खुद और 4 सीटों पर सहयोगियों को उतारने की घोषणा की है लेकिन माना जा रहा है कि इस बार राज्य की सभी सीटों पर ताकत झोंकने की जगह उन तीन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है जहां पिछले चुनाव में उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। राजधानी तिरुअनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मैदान में हैं जिनका मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर से होगा। पथानमठित्ता से अनिल एंटनी को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता पीसी जॉर्ज ने इस पर आपत्ति जताई है। जॉर्ज इस सीट से खुद लड़ना चाहते थे। भाजपा राज्य के सिरियन ईसाईयों को साथ लेकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।

दक्षिण की लक्ष्मण रेखा को कैसे पार करेगी भाजपा?

दक्षिण भारत के पांच राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लोकसभा की 130 सीटें हैं। भाजपा 400 पार जाने के लक्ष्य के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। 2019 में भाजपा को दक्षिण से सिर्फ 29 सीटें मिली थीं। इनमें से भी 25 सीटें कर्नाटक से थीं। 2019 के चुनावों के समय कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी और अब कांग्रेस सत्ता में है। भाजपा को चार सीटें तेलंगाना में मिली थी, यहां भी अब कांग्रेस की सरकार है। दोनों राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भाजपा को अभी खाता खोलना बाकी है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक और तेलंगाना में अपने 2019 के नतीजों को बरकरार रखना है। दक्षिणी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से कई नेताओं को तोड़कर भाजपा अपने साथ ले आई है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जैसे नाराज नेताओं को मना लिया है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं लग रही हैं। दक्षिण में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ कर्नाटक में कांग्रेस ने खुद को पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा मजबूत कर लिया है। यहां कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि दो बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच के मतभेदों पर लगाम लगाना है। दूसरी तरफ भाजपा स्थानीय नेतृत्व के संकट से बाहर नहीं आ पा रही है।

मंहगा सौदा बनती राजनीति

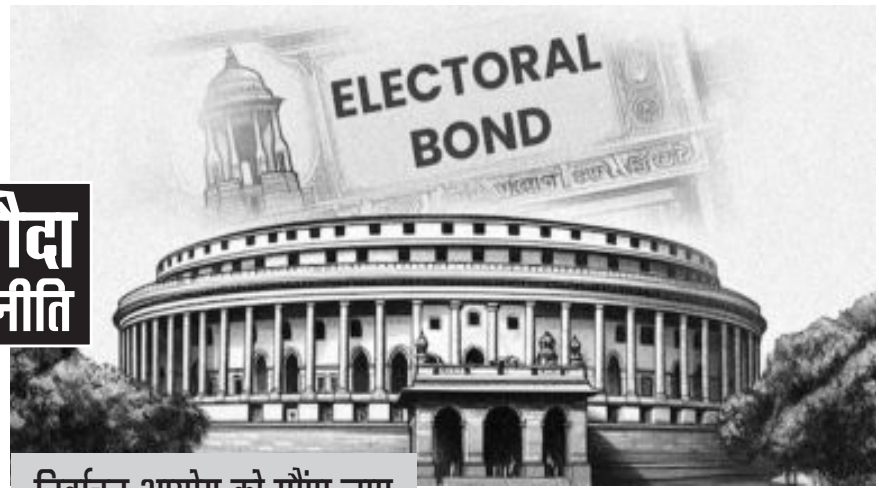

जैसे-जैसे चुनावी खर्च बढ़ा है, राजनीतिक पार्टियों की हैसियत भी बढ़ते हुए हजारों करोड़ की हो गई है। चुनावी बॉन्ड के जरिए भारतीय लोकतंत्र के गले में पड़ी पूंजी की फांस को लेकर देश की सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर लगी है। मालूम हो कि बीते 15 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले चुनावी चंदे की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने बैंक को कहा है कि वह तीन सप्ताह के भीतर सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराए और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

वर्ष 2022-23 के लिए आंकड़ा मोटा-मोटी 1600 करोड़ रुपए का है, जो राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में मिला है। देखना यह है कि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर कितना पैसा दर्शाता है और सभी पैसा देने वालों के नाम उजागर करता है या नहीं? साफ सुथरे संसाधन के साथ चुनाव लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य माना गया है। लेकिन बाजार की दखलअंदाजी के कारण चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से अधिक भरोसा पेशेवर लोगों पर कर रहे हैं। पार्टियां अपने चरित्र और कार्यशैली को पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर के रूप में बदल रही हैं। टेक कंपनियां भी इस मौके को खूब भुना रही हैं और राजनीतिक दलों को अपना क्लाइंट बनाकर मोटी कमाई कर रही हैं। इस संकट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही भांप लिया था। वर्ष 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉर्पोरेट से चुनावी चंदे के प्रचलन को खत्म करने के लिए लोकसभा में निजी सदस्य बिल पेश किया था। तर्क दिया गया था कि संभव है कि सभी पक्षों को कॉर्पोरेट से चंदा लेना मंजूर न हो, इसलिए उनकी सहमति लिए बिना कॉर्पोरेट से चंदा लेने को मंजूरी देना अनैतिक होगा।

वाजपेयी का कहना था कि ऐसे चंदों से केवल कॉरपोरेट के हित सधेंगे। जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिल का स्वागत किया, वहीं तत्कालीन सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी ने इसके पक्ष में वोट नहीं किया। उसके बाद ऐसा बिल कभी पेश नहीं हुआ। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29बी के तहत राजनीतिक पार्टियां विदेशी स्रोतों को छोड़कर किसी से भी चंदा ले सकती हैं। इससे दो निष्कर्ष निकालते हैं, पहला- धन में राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करने की क्षमता है। दूसरा, विदेशी चंदा चुनावी शुचिता को खंडित करता है। यह दोनों बातें उस व्यक्ति, गैर मतदाता पर भी बराबर लागू होती हैं जिसका चुनाव प्रक्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। विदेशी स्रोत से चंदे के साथ जैसी चुनौतियां जुड़ी हैं, वैसी ही चिंताएं कॉर्पोरेट से मिलने वाले चंदे के साथ भी जुड़ी होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहां विदेशी चंदा न्यायिक परिधि से बाहर है तो दूसरा यानी कॉर्पोरेट चुनाव में प्रतिभागी न होने से चुनावी प्रक्रिया के लिए बाहरी तत्व हैं। लेकिन पार्टीगत हितों के चलते इस कानून को ठोस नहीं बनाया गया।

वाजपेयी ने अपने बिल में कॉर्पोरेट बनाम आम नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया था। आमतौर पर कॉर्पोरेट ग्रुप अपने सदस्यों, जिन्हें व्यापार की स्वतंत्रता है, के आर्थिक हितों को साधने वाले संगठन होते हैं। इसलिए उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य कारोबारी स्वतंत्रता से होता है। यकीनन यह स्वतंत्रता व्यावसायिक उद्देश्य वाली होती है। दूसरी तरफ नागरिकों के पास अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता है, जो राजनीतिक क्षेत्र तक विस्तार ले लेती है। चूंकि कॉर्पोरेट मतदाताओं की भांति लोकतंत्र में प्रतिभागी नहीं होते, इसलिए उनका राजनीतिक भाषण और अभिव्यक्ति के लिए कोई दावा नहीं होता। इसीलिए जहां नागरिक मतदाता अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं, वहीं कॉरपोरेट को किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देने से बचना चाहिए। वाजपेयी जी ने सदन में जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था उसका मूल मकसद चुनाव सुधार से जुड़ा था।

अदालत के हालिया निर्णय के बाद चुनाव सुधार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है तो उसके कारणों में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता भी शामिल है। भारत में समय-समय पर इस प्रक्रिया की कमियों को दूर करने के लिए सुधार किया जाता रहा है। टीएन शेषन जैसे निर्वाचन आयुक्तों ने अपने कुछ कड़े निर्णय से बड़े सुधार किए और ख्याति प्राप्त की। उस दौर में धनबल के साथ बाहुबल का प्रयोग कर पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव को प्रभावित किया जाता रहा। तब बूथ कैपचरिंग जैसे हथकंडे अपनाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनकर संसद और विधानसभाओं में पहुंचने लगे थे, लेकिन उनके समर्थकों पर जब शेषन और केजे राव की शक्ति का डंडा चला था, तब बाहुबली जड़ मूल से खत्म हो गए।

● **बृजेश साहू**

निर्वाचन आयोग को सौंपा जाए चुनावी चंदा संबंधी मामला

जरूरी है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनावी चंदा संबंधी मामले को निर्वाचन आयोग को सौंप दिया जाए। राजनीतिक दलों को निष्पक्ष और पारदर्शिता से चंदा मुहैया कराने के लिए जरूरी है कि बेहिसाबी पैसे और कॉरपोरेट और गैर मतदाता द्वारा राजनीतिक दलों को सीधे चंदा दिए जाने का नियमन हो। इस क्रम में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सरकार की तरफ से धन मुहैया कराना भी कारगर विकल्प हो सकता है। इस तरह की योजना प्रत्यक्ष करों पर एक प्रतिशत का उपकर लगाकर कारगर बनाई जा सकती है। निर्वाचन आयोग एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष बना सकता है, जिसमें उपकर से संग्रहित धन जमा किए जाएं। उपकर प्रगतिशील होने के कारण गरीब उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों को मतदाताओं से सीधे चंदा लेने की छूट हो। जो मतदाता नहीं है वह अपना योगदान तटस्थ रूप से निर्वाचन कोष में दे सकते हैं। कॉर्पोरेट द्वारा अगर इस कोष में पैसा दिया जाता है तो उससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि चुनाव में लोगों की निष्ठा में इजाफा होगा। राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में आने के बाद अधिक से अधिक समावेशी एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित होंगी। मतदाताओं का महत्व बढ़ेगा और तभी लोकतंत्र वास्तव में लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बन सकेगा।

टारगेट के साथ कुनबा भी बढ़ाया

मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए भाजपा ने अपना कुनबा भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। देशभर में दूसरी पार्टियों के नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। सबसे अधिक मप्र में कांग्रेसी भाजपाई बने हैं।

लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेतृत्व कर रही भाजपा ने इन चुनावों में अबकी पार, 400 पार का नारा दिया है। अब पार्टी इस नारे को चुनाव नतीजे में तब्दील करने के लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समीकरण सेट करने में जुट गई है।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), उप्र में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल सेक्यूलर (जेडीएस) की एनडीए में वापसी के बाद अब ताजा अपडेट आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर आ रहा है। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) और ओडिशा से सत्ताधारी नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजेडी) के एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोरो पर है। भाजपा और बीजेडी में दिल्ली से भुवनेश्वर तक बैठकों का दौर चल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के हालिया ओडिशा दौरे के दौरान उनकी नवीन पटनायक के साथ अच्छी केमिस्ट्री नजर आई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की। भाजपा और बीजेडी गठबंधन के ऐलान को अब महज औपचारिकता बताया जा रहा है। वहीं, चंद्रबाबू नायडू ने भी गत दिनों दिल्ली पहुंचकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं और टीडीपी चाहती है कि जल्द से जल्द गठबंधन को मूर्त रूप दिया जाए। फिलहाल, टीडीपी का आंध्र में पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन है और दोनों ही दल संयुक्त उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर चुके हैं।

भाजपा को पहली बड़ी सफलता बिहार में मिली। विपक्षी एकजुटता की कवायद के सूत्रधार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने विपक्षी गठबंधन से किनारा कर एनडीए में वापसी कर ली। उप्र में पश्चिमी उप्र की राजनीति पर अच्छा प्रभाव रखने वाली आरएलडी भी एनडीए में आ गई तो वहीं भाजपा कर्नाटक में जेडीएस को साथ लाने में भी सफल रही। ये तो हुई पार्टियों के एनडीए में आने की बात। छोटे स्तर पर भी भाजपा ने दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में करने के लिए भी राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। महाराष्ट्र से लेकर अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक दूसरे दलों के कई नेता हाल के दिनों में भाजपा का दामन थाम चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में तापस रॉय टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के चार में से तीन विधायक, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के आधा दर्जन से अधिक विधायक अब तक भाजपा का दामन थाम चुके हैं। गुजरात में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, पूर्व विधायक अंबरीश डेर और तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके के 16 पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे।

एनडीए में जिस तरह साथ छोड़ गई पार्टियां वापस लौट रही हैं, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की वापसी को लेकर भी चर्चा होती रही है। तेलंगाना चुनाव में हार के बाद केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के भी भाजपा के साथ आने की चर्चा है। हालांकि, अकाली दल के नेता एनडीए में वापसी की अटकलों को नकारते रहे हैं। उप्र में विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) के चीफ व्हिप रहे मनोज पांडेय, पवन पांडेय, पूजा पाल समेत सात और हिमाचल में कांग्रेस के राजेंद्र राणा समेत छह विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इन सभी के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। केरल में एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के बाद अब एक और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल भी भाजपा में आ रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू एनडीए में दोबारा शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। वहीं सीट शेयरिंग का मुद्दा बेहद अहम है। जिस पर बातचीत जारी है। भाजपा के साथ-साथ पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की सीटें भी तय करने पर बात हो रही है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को 18, जनसेना को 2, भाजपा को 5 सीटें दिए जाने के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। जिस पर टीडीपी भी सहमत हो

भाजपा का टारगेट 370

लोकसभा चुनाव में भाजपा 370 का टारगेट लेकर चल रही है। बीते चुनाव में उसे 303 सीटें मिली थीं। 2019 में भाजपा ने उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में 90 से 100 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल की थी। ऐसे में बिहार, झारखंड, उप्र, मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में सीटें बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम है। फिर सवाल एक ही है- 67 सीटें कहां से आएंगी? तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां से भाजपा को इस चुनाव में बड़ी उम्मीद है। राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं। फिलहाल भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। 2019 के चुनाव में उसका अपना वोट प्रतिशत मात्र 3.66 फीसदी था। उसे कुल 15,51,924 वोट मिले थे। भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके को एक सीट मिली थी। बाकी की 38 सीटें डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए को मिलीं। 2014 के चुनाव में जब भाजपा ने पूरे उत्तर भारत में जबर्दस्त जीत हासिल की तब इस राज्य में उसे केवल एक सीट मिली।

पार्टी बनाई और भूल गए, अधिकांश दल नहीं लड़ते हैं चुनाव

चुनाव आयोग देश में राजनीतिक दलों की तेजी से बढ़ रही संख्या और उनके रवैये से चिंतित हैं। लंबे-चौड़े दावों और बड़े-बड़े नामों से दल तो बना लिए गए, लेकिन अधिकांश गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर लड़ते ही नहीं। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूती देने की जगह चुनावी व्यवस्था के सामने वे एक बोझ जरूर बन गए हैं, क्योंकि ये भले ही चुनाव लड़ें या न लड़ें, आयोग को इनके लिए भी सारी मशक्कत ठीक वैसे ही करनी पड़ती है, जैसी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे दलों के लिए की जाती है। चौंकाने वाली बात यह है ऐसे दलों का आंकड़ा कोई 100-200 नहीं, बल्कि दो हजार से ज्यादा है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव आयोग ऐसे दलों की चुनौतियों से निपटने में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में आयोग ने कई चुनावों से निष्क्रिय और सालाना रिपोर्ट न देने वाले रजिस्टर्ड करीब चार सौदों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसके तहत इन दलों को रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया है। साथ ही इन्हें दिए गए चुनाव चिन्ह को छीनते हुए इन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया है। चुनावी चंदे का हिसाब न देने और पिछले चुनावों के खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर करीब 250 दलों को आयकर में मिलने वाली उनकी छूट को समाप्त करने की भी सिफारिश की है।

सकती है। बता दें कि आंध्रप्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। चंद्रबाबू नायडू पिछले कुछ समय से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पहले भी भाजपा का हिस्सा रही है। नायडू केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा था कि देश का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि भाजपा को 370 सीटों पर जीत हासिल होगी। ऐसे में भाजपा 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए सभी समीकरण सेट कर रही है। बीते दिनों हुए एक सर्वे में एनडीए को उत्तर भारत में जहां लाभ होता दिख रहा है, तो वहीं साउथ में इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। ऐसे में भाजपा अपने टारगेट को हासिल करने के लिए साउथ पर फोकस कर रही है।

साउथ इंडिया के 5 राज्यों (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में लोकसभा की 129 सीटें आती हैं, इसमें अकेले आंध्र प्रदेश में 25 सीटें आती हैं। सर्वे के आंकड़ों में चंद्रबाबू नायडू बड़ा उलटफेर करते दिख रहे हैं। टीडीपी को जहां 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं, जगनमोहन रेड्डी की वायएसआरसीपी को 8 सीटें मिलती नजर आ रहीं हैं, जबकि भाजपा को यहां बड़ा नुकसान होने का अनुमान है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए के साथ आ जाते हैं, तो भाजपा के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था, तब वह सूबे के मुख्यमंत्री थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तब विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने भाजपा से 20 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत दिनों ओडिशा के दौरे पर थे और उसी दिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती भी थी। प्रधानमंत्री ने बीजू बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे अपना सौभाग्य बताया और लगे हाथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना मित्र कहकर संबोधित किया, जमकर तारीफ की। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी के बाद अब बीजू जनता दल (बीजेडी) की भी पुराने गठबंधन में वापसी होने वाली है?

हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेडी ने भाजपा उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था। इसे नवीन पटनायक की पार्टी की ओर से गठबंधन के लिए भाजपा को सॉफ्ट सिग्नल की तरह देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे के दौरान उनकी नवीन पटनायक के साथ दिखी केमिस्ट्री ने इस चर्चा को और हवा दे दी। अब दोनों दलों का गठबंधन तय बताया जा रहा है लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि 2000 से ही ओडिशा का पावर सेंटर बने रहे नवीन पटनायक को 15 साल बाद अब आखिर फिर से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है?

दरअसल, नवीन पटनायक 2000 से ही ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां बीजेडी की 24 साल पुरानी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को वोट के रूप में कैश कराने की कोशिश में हैं। बीजेडी की अंगुली पकड़कर 2009 तक चलती रही भाजपा के लिए ओडिशा में सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का था। पार्टी ने रणनीतिक रूप से धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव के रूप में दो मजबूत नेता खड़े किए और जुएल ओराम, जय बैजयंत पांडा, मनमोहन सामल जैसे नेताओं को भी आगे किया।

बीजेडी ने साल 2009 के चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। 2009 में भाजपा को 15.1 फीसदी वोट शेयर के साथ छह सीटों पर जीत मिली थी और तब से अब तक, चुनाव दर चुनाव पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। बीजेडी 2009 में 38.9 फीसदी वोट शेयर के साथ 146 सदस्यों वाली विधानसभा में 103 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन 2014 और 2019 चुनाव के एक ट्रेंड ने पटनायक की पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। भाजपा का ग्राफ चुनाव दर चुनाव चढ़ा है। 2014 और 2019 के ओडिशा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेडी का वोट शेयर बढ़ा जरूर है लेकिन मामूली ही सही, सीटें घटी हैं। साल 2014 में बीजेडी का वोट शेयर पांच फीसदी इजाफे के साथ 43.9 फीसदी पहुंच गया और 117 सीटें जीतकर पार्टी ने फिर से सरकार बना ली। 26 फीसदी वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीतकर कांग्रेस दूसरे और भाजपा 18.2 फीसदी वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। 2014 की हार के बाद भाजपा ने ओडिशा में सक्रियता बढ़ा दी। नतीजा 2019 के विधानसभा और लोकसभा, दोनों ही चुनाव में देखने को भी मिला।

● **विपिन कंधारी**

अप्रैल-मई में होने जा रहे आम चुनाव के पहले कांग्रेस ने तमाम भाजपा विरोधी दलों को इंडिया नामक गठबंधन के साझा मंच पर एकजुट करने की कोशिश इस उम्मीद में की थी कि विपक्षी एकता के बल पर वह मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने से रोक सकेगी, लेकिन यह गठबंधन चुनाव की घोषणा के पहले ही ताश के पत्तों जैसे ढेर होता दिख रहा है।

दुविधा में कांग्रेस

अजीब-सी दुविधा में दिखती है कांग्रेस पार्टी। 10 वर्ष पूर्व केंद्र की सत्ता गंवाने के बाद मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के खिलाफ उसकी कोई रणनीति कारगर नहीं रही है। पार्टी को कुछ प्रदेशों में सत्ता में काबिज होने का मौका तो मिला, लेकिन दिल्ली की गद्दी अब भी उससे दूर है। इस साल अप्रैल-मई में होने जा रहे आम चुनाव के पहले कांग्रेस ने तमाम भाजपा विरोधी दलों को इंडिया नामक गठबंधन के साझा मंच पर एकजुट करने की कोशिश इस उम्मीद में की थी कि विपक्षी एकता के बल पर वह मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने से रोक सकेगी, लेकिन यह गठबंधन चुनाव की घोषणा के पहले ही ताश के पत्तों जैसे ढेर होता दिख रहा है।

ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की बंगाल यात्रा से दूरी बना ली तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर इस गठबंधन के ताबूत में मानो आखिरी कील ठोंक दी। यह वही नीतीश हैं, जिन्होंने सभी मोदी-विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की थी। इन सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के निशाने पर कांग्रेस ही रही है, जिस पर गठबंधन में मनमानी करने का आरोप लगा है। जाहिर है, कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह ऐसा संकट है जिससे वह उबर नहीं पा रही है।

कांग्रेस के अधिकतर घटक दल, खासकर वे प्रादेशिक पार्टियां उसके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो अपने-अपने राज्यों में राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं। उनमें से अधिकतर पार्टियों में यह विश्वास नहीं दिखता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। अपने प्रति सहयोगी दलों का ऐसा अविश्वास कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या रही है जिससे वह लगभग हर चुनाव में जूझती रही है। इस बार भी इंडिया गठबंधन के बिखरने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह लगती है। गौरतलब है कि जो प्रादेशिक क्षत्रप सियासी तौर पर जितना सशक्त है, कांग्रेस के प्रति उसका अविश्वास उतना ही अधिक दिखता है। उन्हें लगता है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में वे राहुल गांधी से ज्यादा सक्षम हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हर बड़े प्रादेशिक दल के नेता को अपने आप को साझा विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखने की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ख्वाहिश रखने में कोई गुरेज नहीं है।

ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी करे तो क्या करे? कांग्रेस अपने आप को विपक्ष की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखती है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रादेशिक क्षत्रप को विपक्षी एकता के रथ का सारथी बनाना उसे गवारा नहीं हो सकता। ममता की भले ही बंगाल के चुनावों में तूती बोलती हो और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी भले ही उप्र में अपने आप को कांग्रेस से बड़ा जनाधार वाली पार्टी समझती हों, कांग्रेस के लिए वे सिर्फ प्रादेशिक पार्टियां हैं जिनके हाथों में मोदी-विरोधी राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान वह नहीं सौंप सकती। प्रथम दृष्टि, नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही दिखता है कि जिस मंसूबे के साथ उन्होंने विपक्षी एकता को हकीकत में बदलने का प्रयास किया, उसके अनुरूप उन्हें कांग्रेस से प्रतिक्रिया नहीं मिली। नीतीश को

भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं

मोदी विरोधियों का मानना है कि भाजपा के लिए इस बार लड़ाई उतनी आसान नहीं है जितना आम तौर पर समझा जा रहा है। उनके मुताबिक आज किसानों से लेकर नौजवानों में असंतोष है। महंगाई और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष मोदी सरकार की कमजोरी मान रहा है। हालांकि भाजपा अपनी विजय को लेकर आश्वस्त दिख रही है। लेकिन, जीत की चाबी हर चुनाव की तरह इस बार भी इस देश के जनता के हाथ है जो अंतिम समय तक पत्ते नहीं खोलती है। यहां का मतदाता उसी उम्मीदवार का चयन करता है जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि वह अपने कार्यकाल में उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। तमाम सियासी दावों और धारणाओं, आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच जनता आखिरकार उसी को चुनती है जिसके उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की संभावना सबसे अधिक रहती है। यही कारण है कि मोदी पिछले दो लोकसभा चुनावों में विजयी रहे हैं और इस बार भी उन्हें सत्ता के रेस में आगे बताया जा रहा है। लेकिन वे अंततः हैट्रिक लगाएंगे या नहीं, यह आखिरकार जनता के हाथ में है जिसका फैसला अंतिम होता है। यही भारतीय लोकतंत्र के बहुरंगे चुनावों की खूबसूरती है जिसके कारण सबकी निगाहें इस चुनाव पर हैं।

शायद लगता होगा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल उन्हें 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में पेश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

क्या कांग्रेस के लिए ऐसा करना मुमकिन था? क्या पार्टी नीतीश, ममता या किसी अन्य क्षत्रप को राहुल गांधी के स्थान पर गठबंधन का नेतृत्व सौंप सकती थी? कांग्रेस आखिरकार एक पुराना सियासी दल है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। अपने राजनीतिक वजूद की कीमत पर वह किसी क्षेत्रीय दल के नेता को मोदी-विरोधी अभियान की अगुवाई करने का मौका कैसे दे सकती है? बिहार समेत कई राज्यों में पार्टी ने भाजपा को हराने के नाम पर प्रादेशिक दलों का पिछलग्गू बनकर अपनी सियासी जमीन खो दी है, जिसे पुन: हासिल करने की अब कोई उम्मीद नहीं दिखती। भले ही किसी राज्य का क्षत्रप कितना भी ताकतवर और स्वच्छ छवि का हो, कांग्रेस उसके नेतृत्व को स्वीकार कर अपनी बची हई जमीन खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। जो क्षत्रप कांग्रेस की कमजोरियों का आंकलन करके यह सोचते हैं कि पार्टी उन्हें अपने गठबंधन का नेता घोषित कर देगी, वे मुगालते में हैं। उन क्षत्रपों को यह समझना होगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का कोई साझा मंच तैयार होता है तो उन्हें उसका सिरमौर स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को ही मानना होगा। जिन्हें यह स्वीकार नहीं होगा उनकी राहें जुदा हो जाएंगी, जैसा संभवत: नीतीश के मामले में हुआ। कांग्रेस के लिए भी यही बेहतर है कि दूसरों की बैसाखी पर निर्भर होने के बजाय वह अपने संगठन को हिंदी पट्टी में मजबूत करे और आम लोगों से सीधा संपर्क बनाए, जिनसे वह कट गई सी लगती है।

अगर सब कुछ तयशुदा समय पर होता है तो जल्द ही आगामी आम चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी और केंद्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसका औपचारिक शंखनाद हो जाएगा। इस चुनाव पर दुनियाभर की नजर रहेगी और सबके मन में यही सवाल होगा कि क्या भाजपा के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की हैट्रिक लगाएंगे। हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति के हर लीप ईयर में होने वाले चुनाव के अलावा भारत के लोकसभा चुनावों के बारे में ही सबसे ज्यादा जिज्ञासा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहती है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि मोदी पिछले एक दशक में प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं, बल्कि इसलिए भी कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का शांतिपूर्ण संचालन अपने आप में अन्य देशों के लिए कौतुहल का विषय है।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण भारत के आम चुनाव पर दुनिया, विशेषकर सुपर पावर समझे जाने वाले पाश्चात्य देशों की नजर रही है। शुरुआत में इन देशों के हुक्मरानों के साथ-साथ वहां की मीडिया को भी मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में सफल होने के बारे में संशय था। गोधरा कांड के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया में मोदी को अल्पसंख्यक विरोधी नेता के रूप में आरोपित किया गया था। उन्हें लगता था कि मोदी को अपने गृह राज्य गुजरात के बाहर भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन, मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में उन देशों में भी अपनी स्वीकार्यता बना ली, जिन्हें लगता था कि वे विविधता भरे देश में सुचारू रूप से शासन चलाने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कई ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष जो मोदी को पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, अब उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी नजरिया उनके प्रति हाल में बदला दिखता है जो कभी थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले देश को अब एक मजबूत इकोनॉमी वाले मुल्क के रूप में चित्रित कर रहे हैं। जाहिर है, 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में व्यापक दिलचस्पी मुख्य तौर से इस बात को लेकर है कि क्या भारत की जनता एक बार फिर देश के शासन की बागडोर मोदी के हाथों में देने जा रही है या इस बार कोई बड़ा परिवर्तन होगा?

बनते और बिगड़ते रहे गठबंधन

2024 के लोकसभा चुनाव में माहौल भाजपा के पक्ष में पहले ही बन गया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ले रहीं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में वोटरों को बहलाया नहीं जा सकता। गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग कर लेने भर से विपक्षी दलों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की वारिस है, उसे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। 2004 में यूपीए गठबंधन को सत्ता मिली थी लेकिन यह निरंतरता 2014 में टूट गई, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में आक्रामक हिंदुत्व को स्वीकृति प्राप्त हो गई। भाजपा का नया नेतृत्व लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ-ही-साथ गौरवशाली इतिहास पर भी जोर दे रहा है। 1996 में भाजपा केंद्र सरकार में सिर्फ तेरह दिनों तक ही टिक सकी थी। लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में देश ने दो प्रधानमंत्रियों को देखा। और इस प्रकार 1998 में फिर एकबार लोकसभा चुनाव के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस चुनाव में यद्यपि भाजपा को बहुमत नहीं मिला तथापि एनडीए के तत्कालीन संयोजक जॉर्ज फर्नांडीज के कौशल ने गैरकांग्रेसी सरकार के गठन के सपने को साकार किया। भारत की संसदीय राजनीति में एक नया अध्याय तब जुड़ा, जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग को अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने का अवसर मिला।

इस सिलसिले में सर्वे और ओपिनियन पोल का दौर शुरू हो चुका है। जमीनी हकीकत को जानने के लिए भारत की सियासत में दिलचस्पी लेने वाले विदेशों के पत्रकार और राजनयिकों का विभिन्न प्रांतों का दौरा शुरू हो चुका है। आज इस बात से अधिकतर राजनीतिक टिप्पणीकार इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के आसार प्रबल हैं। इस तरह की धारणा बनने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी दो प्रमुख वजहें स्पष्ट दिख रही हैं। पहला, पिछले दो चुनावों की तुलना में भाजपा का मोदी ब्रांड अब ज्यादा प्रभावी प्रतीत होता है। इसलिए पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति प्रधानमंत्री की छवि के इर्द-गिर्द ही बनाई जा रही है। दूसरा, तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी के विरोधियों का राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच पर आकर उन्हें साझा चुनौती देने की संभावना दिनोदिन क्षीण होती जा रही है।

जनता दल-यूनाइटेड के सिरमौर नीतीश कुमार, जो मोदी विरोधी मुहिम के सूत्रधार थे, वापस एनडीए खेमे में जा चुके हैं। यह भी जगजाहिर है कि विपक्ष के महत्वाकांक्षी गठबंधन इंडिया के विभिन्न घटक दलों के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के चुनाव पूर्व बिखरने का फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगा जिसके गठबंधन में मोदी के कारण नेतृत्व का संकट नहीं है।

● **इन्द्र कुमार**

बिजली विभाग में गड़बड़ी...

छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी के अफसर उपभोक्ताओं की श्रेणी बदलकर बिलिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं। यह खेला 2023 और उसके पहले का है। यह मामला कंपनी की विजिलेंस (सतर्कता) की जांच और आरटीआई में मिले दस्तावेजों से सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर खेले गए इस खेल में राजधनी रायपुर के एक सर्किल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी पकड़ में आई है। सूत्रों का दावा है कि इस तरह का खेल बिजली कंपनी के कई सर्किलों में चल रहा है। बिजली कंपनी में यह खेल पूर्ववर्ती सरकार के समय से चल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बिजली कंपनी ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है और ऊर्जा विभाग पहले भी मुख्यमंत्री के पास था और अभी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही ऊर्जा विभाग के भारसाधक मंत्री हैं।

बिजली कंपनी को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले इस खेल को समझने से पहले यह जान लें कि बिजली उपभोक्ताओं की अलग-अलग श्रेणी होती है और श्रेणी के हिसाब से ही बिजली की दर तय होती है। विद्युत अधिनियम और कंपनी के रूल बुक में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यानी कौन सा कनेक्शन घरेलू होगा, कौन सा गैर घरेलू और कौन सा औद्योगिक कलेक्शन की किस श्रेणी में आएगा, यह सब तय है। यह भी तय है कि एक परिसर में एक से अधिक कनेक्शन नहीं हो सकते। इन्हीं नियमों के आधार पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को बिल जारी करती है और उल्लंघन मिलने पर कार्यवाही की जाती है। कंपनी के इस खेल के संबंध में कंपनी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी (इंजीनियर) ने आरटीआई के जरिये दस्तावेज हासिल किया है।

कंपनी को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले इस खेल के दो रूप अब तक सामने आए हैं। इनमें एक मामला एक ही औद्योगिक परिसर में अलग-अलग नाम से एक से अधिक कनेक्शन का है। दरअसल औद्योगिक कनेक्शन लोड यानी खपत के हिसाब से दिए जाते हैं। लोड बढ़ने के साथ बिजली की दर बढ़ जाती है। ऐसे में बिजली बिल का भार कम करने के लिए कुछ लोग 2 कनेक्शन ले लेते हैं जो नियमों के विरूद्ध है। विजिलेंस की जांच में ऐसे 3 मामले पकड़े गए जिसमें एक ही औद्योगिक परिसर में एक से ज्यादा कनेक्शन थे। दोनों ही कनेक्शन का उपयोग एक ही काम में किया जा रहा है। विजिलेंस की जांच में पकड़े जाने के बाद भी ऐसे उपभोक्ताओं के यहां से न तो दूसरा कनेक्शन हटाया गया है और न ही वसूली की कार्यवाही की गई है।

कंपनी में दूसरा खेल उपभोक्ताओं की श्रेणी में किया जा रहा है। विजिलेंस की जांच में ऐसे कई मामले पकड़ में आए, जिनका कनेक्शन गैर घरेलू में आएगा, लेकिन कंपनी के रूल का उल्लंघन करते हुए उनकी बिलिंग औद्योगिक श्रेणी में की जा रही है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि कबाड़ का काम करने वालों, टायर रिमोल्डिंग करने वालों और फर्नीचर का काम करने वालों की औद्योगिक श्रेणी में बिलिंग की जा रही है। बिजली कंपनी के एक अफसर ने बताया कि औद्योगिक श्रेणी की टैरिफ (बिजली दर) गैर घरेलू से कम है। इस वजह से बिलिंग में यह खेल किया जा रहा है।

विजिलेंस की टीम ने सिंतबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 20 ऐसे कनेक्शनों की जांच की जहां फर्नीचर का काम किया जा रहा था। जांच में पता चला कि इन सभी के यहां औद्योगिक श्रेणी में बिलिंग की जा रही है। विजिलेंस टीम ने पंचनामा की कार्यवाही की और वसूली के लिए संबंधित सर्किल के अफसरों को आदेशित कर दिया। अफसरों के मुताबिक, रूल बुक के अनुसार आरा मिल औद्योगिक श्रेणी में आता है, लेकिन फर्नीचर वर्क गैर घरेलू कनेक्शन में आएगा। इन मामलों के पकड़े जाने के बाद बिजली कंपनी की तरफ से 30 मई 2023 को राज्य विद्युत नियामक आयोग को एक पत्र लिखा गया जिसमें आयोग से आग्रह किया गया कि फर्नीचर वर्क को औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया जाए। कंपनी के आग्रह को स्वीकार करते हुए आयोग ने 19 जुलाई 2023 को फर्नीचर वर्क को एलवी-5 औद्योगिक श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। बिजली कंपनी के अफसरों के अनुसार फर्नीचर वर्क को औद्योगिक श्रेणी में जुलाई 2023 में शामिल किया गया है, लेकिन जो केस बनाए गए हैं वो सभी उस तारीख के पहले के हैं। ऐसे में नियमानुसार उनसे वसूली की जानी चाहिए, लेकिन कंपनी ने इन 20 लोगों का करीब 46 लाख से ज्यादा बकाया माफ कर दिया।

विजिलेंस की जांच में दर्जनभर ऐसे कनेक्शन पकड़े गए जहां कबाड़ में खरीदे गए प्लास्टिक के टुकड़े किए जाते थे। इन लोगों ने औद्योगिक कनेक्शन ले रखा था। विजिलेंस ने इनके कनेक्शन को गैर घरेलू श्रेणी का मानते हुए पंचनामा की कार्यवाही की और एलवी-5 के स्थान पर एलवी-2 (गैर घरेलू) बिलिंग करने के लिए निर्देशित कर दिया। सर्किल के अफसरों ने इनमें से 9 उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूला लेकिन 3 पर यह कहते हुए कार्यवाही नहीं की, कि उनके यहां प्लास्टिक काटने के लिए ग्रेंडर मशीन का उपयोग किया जाता है जो निम्न दाब उद्योग की श्रेणी में आता है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

रिमोल्डिंग वालों की भी बिलिंग निरस्त

जांच के दौरान 10 टायर रिमोल्डिंग करने वालों के यहां भी औद्योगिक कनेक्शन मिला। विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर बिजली अफसरों ने इनमें से 7 से तो वसूली की, लेकिन 3 का 33 लाख से अधिक का बिल यह कहते हुए निरस्त कर दी कि इनका जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र में पंजीयन है। जानकारों के अनुसार जिला उद्योग केंद्र में पंजीयन उपभोक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है न कि किसी जांच के आधार पर। ऐसे में जब 7 लोगों के कनेक्शन को गलत माना गया तो फिर 3 को क्यों छूट दी गई। इस पर सवाल उठना लाजिमी है।

टिकट बंटवारे का महासंकट

उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में जुटी भाजपा की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उसके सहयोगी दल बन रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहली सूची जारी करते समय उसे उम्मीदवार चयन करने के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं रहना था। बिहार में नीतीश 2019 की तरह 17 सीटों पर लड़ने का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे है, वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी भाजपा से लोकसभा सीटों को लेकर किसी तरह का लिहाज करने के मूड में नहीं है।

उप्र की 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें आती हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ कर महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता का स्वाद चख रहे एकनाथ शिंदे और अजित पवार सीटों के बंटवारे में भाजपा से अपने योगदान का पूरा हिस्सा मांग रहे हैं। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि 2019 की तर्ज पर 23 सीटें उनकी शिवसेना के लिए छोड़ी जाएं और अजित पवार भी पश्चिम महाराष्ट्र में अपने दबदबे के आधार पर 10 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हैं। शिंदे और अजित पवार की मांग और अपने रुख पर अड़े रहने के कारण गतदिनों महाराष्ट्र के दौरे पर रहे गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह ने इस बैठक में साफ कह दिया है कि शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत से ज्यादा पहले ही दिया जा चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर वह ज्यादा महत्वकांक्षा न पालें।

भाजपा का तर्क है कि 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और 40 विधायकों वाले अजित पवार को उपमुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय जैसा भारी मंत्रालय दिया जा चुका है। भाजपा का मानना है कि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम और मोदी के काम पर लड़ा जाएगा ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का उनका नैतिक अधिकार है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों के फंसे पेच को सुलझाने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में शिंदे और अजित पवार को लेकर मचे घमासान को साधने के लिए अमित शाह ने विवाद की सीटों पर विस्तार से बात की और नेताओं से साफ कहा कि जितनी ज्यादा सीटें हम जीतेगें उतना विपक्ष कमजोर होगा और मोदी उतने मजबूत होंगे। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कई बार अच्छे स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवाई निगलनी पड़ती है। उसी तरह सत्ता के लिए कई बार विचारधारा के विपरीत जाकर गठबंधन करने पड़ते हैं। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी संदेश भेज दिया है कि गठबंधन में सीटें हारने के लिए नहीं दी जा सकती। शाह ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 8 सीटें और अजित पवार को 4 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। भाजपा अपने लिए खुद 36 सीटें रखना चाहती है। महादेव जानकर, राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी जैसे छोटे दलों के साथ यदि कुछ बात बनती है तो भाजपा इनको अपने कोटे से सीट देगी।

अमित शाह ने एकनाथ शिंदे के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें शिवसेना ने 2019 की तर्ज पर अविभाजित शिवसेना को दी गई 22 सीटों पर दावा ठोका था। भाजपा का मानना है कि 2019 के बाद परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में हैं और सिर्फ 2019 में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को 2024 में आधार नहीं बनाया जा सकता। भाजपा ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से पूछा है कि पहले वह बताएं कि उनके पास उनकी मांगी जा रही सीटों पर कौन से जिताऊ उम्मीदवार हैं। शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से यह भी कहा है कि आपके साथ आपकी पार्टी का मूल वोटर भी आया है कि नहीं, लोकसभा चुनाव में इसका फैसला भी हो जाएगा। शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को यह प्रस्ताव भी दिया है कि मोदी के चेहरे और मोदी की लोकप्रियता पर हो रहे इस चुनाव में कुछ सीटों पर आपके उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर भी मैदान में उतारे जा सकते हैं।

महाराष्ट्र में जिन सीटों को लेकर विवाद है उनमें अमरावती, मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई उत्तर पश्चिम और ठाणे की सीटें शामिल हैं। भाजपा अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को समर्थन देना चाहती है, वहीं शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल अमरावती सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मुंबई की छह सीटों में से तीन सीटों पर शिवसेना के सांसद हैं और एकनाथ शिंदे इन तीनों सीटों को अपने लिए मांग रहे हैं जबकि भाजपा मुंबई की छह सीटों मे से सिर्फ एक सीट एकनाथ शिंदे को देना चाहती है। भाजपा ने एकनाथ शिंदे से साफ कहा है कि ठाणे की सीट अगर वह अपने बेटे श्रीकांत के लिए चाहते हैं तो कल्याण डोंबिवली सीट भाजपा को देनी होगी। शिंदे के साथ समस्या यह है कि अगर वह भाजपा के सामने ज्यादा झुकते हुए दिखते हैं तो उनके सांसद और नेता उद्धव ठाकरे खेमे का रुख कर सकते हैं और अगर वह भाजपा के सामने कठोर बनते हैं तो गठबंधन टूटने का खतरा सामने खड़ा है।

● **बिन्दु माथुर**

टिकट बंटवारे में भी मोदी मैजिक का ध्यान रखेगी भाजपा

17-18 फरवरी को दिल्ली में हुई भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टिकटों को लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह को कुछ टिप्स दिए थे। इनमें प्रमुख रूप से जिन बातों पर जोर था उनमें यह भी था कि बहुत जरूरी होने पर ही 75 पार के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। मोदी ने यह भी कहा था कि महिला उम्मीदवारों की संख्या 33 प्रतिशत बढ़ाई जाए। ब्यूरोक्रेट्स को महत्व दिया जाए, तीन बार के सांसदों से तौबा की जाए और परिवारवाद से बचा जाए। मोदी ने निर्देश दिया था कि ऐसे उम्मीदवारों पर ध्यान दिया जाए जो पार्टी में सक्रिय न हों लेकिन अपने क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम हो। मोदी ने कहा था कि जल्द से जल्द कम से कम 300 सीटों के उम्मीदवार फाइनल कर लिए जाएं। मोदी से मिले टिप्स और दिशा-निर्देश के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा ने लगातार 11 दिन मैराथन बैठक कर 11 राज्यों से आने वाली 306 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया था। भाजपा हर सीट का महत्व जानती है इसलिए छोटे-छोटे दलों को भी साधने की हरसंभव कोशिश कर रही है।

जाटों को लेकर संकट में भाजपा!

राजस्थान में लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा एक बार फिर दो दशक पुरानी स्थिति में नजर आ रही है, जब जाट वोटर पूरी तरह पार्टी से छिटका हुआ था। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अग्निवीर योजना को लेकर जाट पहले ही भाजपा से नाराज थे। वहीं, मौजूदा कैबिनेट में भी जाटों को बड़ी जगह न मिलना, टारगेट कर तबादले किए जाना और साथ ही राहुल कस्वां का टिकट काटे जाने की घटना ने इस आग में घी का काम कर दिया है। राहुल कस्वां का टिकट क्यों कटा? इसका सीधा जवाब राजेंद्र राठौड़ हैं। इससे चार महीने पहले राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा चुनावों में चूरू की तारानगर सीट से कांग्रेस के जाट नेता नरेंद्र बुढ़ानियां के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। राठौड़ की इस हार के लिए राहुल कस्वां की भितरघात को जिम्मेदार बताया गया। यहीं से बदले की शुरुआत हुई और राहुल कस्वां का टिकट कट गया।

राजस्थान के चुनावी इतिहास की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार जाटों को भाजपा की तरफ खींचकर लाई थीं। इसका असर यह हुआ कि भाजपा को विधानसभा चुनावों 163 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली। इससे पहले भैरोसिंह शेखावत के समय भाजपा के पास कोई बड़ा जाट चेहरा कभी नहीं रहा। मौजूदा दौर की बात करें तो भाजपा के मंत्रिमंडल में जाट मंत्री तो हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो राजस्थान में जाटों का प्रतिनिधित्व करने का दम रखता हो। भाजपा ने सतीश पूनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हो सके। 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को पार्टी में शामिल कर उन्हें अपनी पारंपरिक सीट नागौर से चुनाव लड़वाया। लेकिन कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा ने उन्हें हरा दिया। हालांकि अब हरेंद्र मिर्धा और उनके बेटे विजय पाल मिर्धा भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अगर यहां हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लिया तो भाजपा के लिए चुनौती बढ़ जाएगी।

पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से नागौर सीट पर गठबंधन किया। इसमें हनुमान ने नागौर की सीट तो जीती ही, साथ ही अजमेर, बाड़मेर और राजसमंद सीट पर भी उनके प्रभाव का फायदा भाजपा को मिला। लेकिन इस बार बेनीवाल भी भाजपा से छिटक गए। जाट नेताओं के नाम पर अब भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जो हैं वे कांग्रेस से आयातित हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले जाट नेता अपने साथ इस वर्ग को भी भाजपा में ला पाएंगे। वहीं, इस सवाल के जवाब में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जाटों को खांटी नेता चाहिए और वर्ग की नाराजगी किसी एक नेता के आने-जाने से तय नहीं होती, इसके लिए समग्र परिप्रेक्ष्य (ओवरऑल पर्सपेक्टिव) देखा जाता है।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती है। पार्टी इंडिया गठबंधन के घटकदलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान सहित कई राज्य में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। राजस्थान में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का दम भर रही है, पर कांग्रेस के लिए यह लड़ाई आसान नहीं है। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खाता तक खोलने में नाकाम रही थी। वहीं, भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 सीट फतह करते हुए अपने वोट बैंक में भी वृद्धि की है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में करौली-धौलपुर और दौसा लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी सीट पर जीत का अंतर एक लाख से ज्यादा रहा है। भीलवाड़ा में जीत का अंतर छह लाख था। यह पार्टी के लिए सोच का विषय है। राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिले हैं। जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34 फीसदी के आसपास रहा है। कुछ माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 39 प्रतिशत वोट मिले। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 39 फीसदी वोट मिले थे। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव का मैदान जीतने के लिए अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना होगा।

रणनीतिकार मानते हैं कि पिछले दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार के चुनाव अलग हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और 2019 में पुलवामा की घटना ने पूरी चुनावी तस्वीर बदल दी थी, पर इस बार महंगाई, बेरोजगारी के साथ किसानों की समस्याएं बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस के पास अपनी स्थिति को बेहतर करने का मौका है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 47 फीसदी वोट के साथ राज्य में 21 सीट जीतने में सफल रही थी। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार एक बड़ा झटका है, पर पार्टी लगातार कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि वह अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेगी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

क्या कांग्रेस इसे भुना पाएगी?

अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि जाटों की भाजपा से नाराजगी का सीधा फायदा किसे होगा। राजस्थान में विकल्प के तौर पर फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन जिस रफ्तार से जाट नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, क्या कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ बनाए रख पाएगी? राजनीतिक विश्लेषक नारायण बाहरेठ का कहना है कि जाट वोटर काफी समय से भाजपा से छिटकना शुरू हो चुका था। भाजपा ने इसकी परवाह नहीं की। अब चुनावों के समय कुछ जाट नेताओं को लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाटों की नाराजगी के चार बड़े फैक्टर पहले से काम कर रहे थे। इनमें पहला किसान आंदोलन, दूसरा पहलवान आंदोलन, तीसरा अग्नीवीर योजना और चौथा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ हुआ सलूक। इसके अलावा सतीश पूनिया की बात करें तो चार साल उन्हें संगठन में काम करवाने के बाद चुनावों से ठीक पहले बदल दिया गया। मौजूदा कैबिनेट में भी जाटों को बड़ी जगह नहीं दी गई। अब इसमें राहुल कस्वां का फैक्टर और जुड़ गया, जिसने नाराजगी बढ़ाने का काम किया है।

ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

उप्र के सभी इलाकों में लग रही इंडस्ट्री

संगठित माफिया गिरोह तथा जेल में बैठकर सत्ता चलाने वाले अपराधियों के डर से कोई निवेशक नोएडा-गाजियाबाद से सुदूर चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में आने को तैयार नहीं था। आज उप्र के सभी इलाकों में छोटी-बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सात वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उप्र में निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। पहले चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना-झपटी यही खबरें आती रहती थीं। उस दौरान अगर कोई कहता कि उप्र में निवेश लाएंगे और उप्र को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, मानना तो दूर की बात है। परंतु आज लाखों-करोड़ का निवेश उप्र की जमीन पर उतर रहा है। अपराध पर अंकुश के चलते बीते सात साल में उप्र में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। आर्थिक सुधारों एवं निवेश की बदौलत बीते सात वर्षों में उप्र बड़ी छलांग लगाते हुए महाराष्ट्र के बाद देश का दूसरा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य बन चुका है। वर्ष 2018 के फरवरी महीने में जब योगी सरकार ने पहली बार उप्र इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, तब विपक्षी दल उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन सरकार अपने प्रयासों में जुटी रही। पहले ही इन्वेस्टर्स समिट में 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उप्र को मिले थे।

जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है। क्या उप्र में यह क्षमता है, वह भी तब जब इसकी पहचान एक पिछड़े और बीमारू राज्य के तौर पर रही हो, अपराध और माफिया जिस राज्य की पहचान रहे हों, निवेशक जिधर देखना पसंद ना करते हों, क्या वह उप्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना भी देख सकता है। कुछ साल पहले तक तो इस सवाल का जवाब ना में होता, लेकिन मोदी-योगी के डबल इंजन शासन में राज्य इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। जिस राज्य ने आर्थिक सुधारों की बदौलत सात सालों में अपनी जीडीपी को 12.47 लाख करोड़ से बढ़ाकर 26 लाख करोड़ तक पहुंचाया है, वह राज्य यह सपना देख सकता है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना आसान नहीं है, लेकिन आपको एक छोटी सी कहानी के जरिये बताते हैं कि कोशिश हो तो यह मुश्किल भी नहीं है।

बनारस से सटे चंदौली जनपद में पुराने जीटी रोड पर स्थित डांडी में उद्योगपति दीपक बजाज ने 2008 में अनिरुद्ध फूड लिमिटेड की स्थापना की थी। इस प्रोजेक्ट ने सैकड़ों लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। दीपक बजाज ने अपनी कई **अन्य व्यवसायिक गतिविधियों** को भी जनपद चंदौली तक ही सीमित रखा। राज्य के ही किसी दूरदराज के जिले में अपने व्यवसाय का एक्सटेंशन करने या नया उद्योग स्थापित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उप्र में लालफीताशाही और माफिया गिरोहों के आतंक के बीच कोई भी उद्योगपति खुद को परेशानी में डालने को समझदारी नहीं मानता था। अतीत में व्यवसायियों के साथ हुई घटनाओं का इतिहास देखते हुए तो कई उद्योगपति उप्र से अपना अच्छा खासा चलता उद्योग समेटकर दूसरे राज्यों में ले गए।

उप्र को 1991 के कल्याण सिंह के छोटे से कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो उप्र वर्ष 2017 तक ऐसा ही था। माफिया सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उप्र में अपराध उन्मूलन और संगठित माफिया गिरोह के खिलाफ जब गोली और बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तब राज्य के लोगों को पहली बार विश्वास हुआ कि सत्ता संचालित करने वाले अपराधियों को भी रौंदा जा सकता है। वरना जनता तो यह नियति मान चुकी थी कि उप्र में सत्ता भले ही बदल जाए, माफियाओं के दहशत और रसूख में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार बदलते ही माफिया सत्ता के साथ हो लेते थे। योगी सरकार ने जब माफिया गिरोहों पर अंकुश लगाकर उद्योग और निवेश का माहौल बनाना शुरू किया तब उद्योगपतियों का विश्वास सरकार पर बढ़ा।

सरकार की कार्यशैली पर भरोसा बढ़ने के बाद दीपक बजाज ने गोरखपुर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीयल अथॉरिटी में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर 2021 में प्लॉट नंबर के-29 पर सक्षम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। सक्षम एग्रो कंपनी प्रतिदिन सवा लाख से ज्यादा बोरियों का उत्पादन कर रही है और सैकड़ों लोगों को नौकरी और रोजगार दे रही है। दीपक बजाज 2021 से पहले भी निवेश करने और रोजगार देने में समक्ष थे, लेकिन तब किसी मुख्यमंत्री या सरकार को दीपक बजाज जैसे उद्योगपति की शायद जरूरत ही नहीं थी। तब सरकारों की प्राथमिकता उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की बजाय अपनी पार्टी तथा अपने लोगों की झोली भरने पर ज्यादा थी, परंतु बीते सात सालों में उप्र की कार्यप्रणाली बदली है। उद्योग एवं उद्योगपतियों की महत्ता को प्रदेश ने समझा है। इस बदलती फिजा का असर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को 10 लाख करोड़ की 14,000 से ज्यादा उद्योग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उप्र में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के जरिये हुआ निवेश प्रदेश के 34 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने में सफल होगा।

दरअसल, सैकड़ों दीपक बजाज उप्र की तकदीर और तस्वीर बदलने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें लालफीताशाही से छुटकारा, उद्योग का माहौल, सुरक्षा और संरक्षा चाहिए। वरना यही उप्र है, जहां मुख्तार अंसारी जैसा कोई सत्तापरस्त माफिया कोयले के बड़े व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा का फिरौती के लिए अपहरण और हत्या करने के बावजूद बेखौफ रहता था, और उद्योगपति और व्यवसायी डरे-सहमे रहते थे। पुलिस ऐसे माफियाओं के आगे-पीछे घूमती थी, और वह जेल से अपनी सल्तनत चलाते थे। जेल से ही किसी विधायक की हत्या तक करा देते थे। योगी सरकार की नीयत और कार्रवाई का असर है कि वही मुख्तार अंसारी, जो गाजीपुर की जेल में तालाब खुदवाकर अपने खाने के लिए मछली पालता था, अब उप्र की जेल में नहीं रहना चाहता है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

लालू का परिवार बनाम मोदी का परिवार

पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने तरीके से राजनीतिक वापसी की। अपने तीखे और चुटीले भाषण के लिए विख्यात लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाया तो पूरी भाजपा बचाव में उतर आई। मोदी के बचाव में भाजपा ने मोदी का परिवार कैम्पेन ही शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने जो सवाल उठाया है क्या वह पूरी तरह से गैर जरूरी है? पटना की रैली में लालू यादव ने मां के स्वर्गवास पर मोदी द्वारा मुंडन न कराने का भी सवाल उठाया और कहा था कि मोदी तो हिंदू भी नहीं हैं। लालू के सवाल को भाजपा ने कितनी गंभीरता से लिया है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तत्काल भाजपा की ओर से पूरा देश मोदी का परिवार... का नारा चला दिया गया। हर प्रदेश से मोदी का जुड़ाव पैदा करने के लिए एआई की मदद लेकर इस बार उस प्रदेश की भाषा में ही मोदी का भाषण सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही अलग-अलग भाषाओं में नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया है जहां उसी भाषा में सूचना दी जाएगी।

निश्चित रूप से चुनाव की घोषणा होने के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने परिवार का सवाल उठाकर नरेंद्र मोदी को एक बड़ा हथियार दे दिया है। अब वो इसी हथियार को पूरे विपक्ष की ओर चलाएंगे और पूरा कैम्पेन इस दिशा में ले जाएंगे कि पूरा देश ही मोदी का परिवार है। देश का हर नागरिक उनके परिवार का हिस्सा है। पटना में 5 मार्च को मौजूद निर्मला सीतारमन ने इसका इशारा भी कर दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो सवाल उठाया है वह कहीं असर ही नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है। भारत में जो राजनेता शीर्ष पर बैठे होते हैं उनका निजी जीवन सार्वजनिक चर्चा का विषय बनता ही है। फिर वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर बैठे कोई अन्य राजनेता। उनका निजी जीवन उनका निजी नहीं रह जाता। उनके निजी जीवन के आधार पर ही उनकी सार्वजनिक छवि का निर्माण होता है। मोदी से सीधे तौर पर सवाल पूछने की हिम्मत तो किसी की नहीं है लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी से तो एक पत्रकार द्वारा सीधे पूछ ही लिया गया था कि क्या आप ब्रह्मचारी हैं? इस पर हाजिर जवाब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो अविवाहित हैं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। इसी तरह एक और टीवी प्रोग्राम में उस समय के एक चर्चित पत्रकार ने जब उनसे यह पूछा कि अटलजी अपने निजी जीवन के प्रेम-प्रसंग के बारे में कुछ बताइए। तब एक बार फिर हाजिर जवाब अटलजी यह कहते हुए बच निकले थे कि निजी जीवन की चर्चा सार्वजनिक मंचों पर नहीं की जाती। यह तो हाजिर जवाब अटलजी थे जो ऐसे मारक प्रश्नों का भी मुस्कुराने वाला जवाब दे देते थे लेकिन मोदी के सामने अव्वल तो ऐसे प्रश्न आते नहीं और आते भी हैं तो वो उसका राजनीतिक प्रतिप्रश्न पैदा करते हैं। याद करिए 2014 का चुनाव। उस समय मोदी की पत्नी यशोदाबेन की बहुत चर्चा उछाली गई थी। लेकिन न तो तब और न ही अब। मोदी ने इस प्रश्न को कभी अपने तक पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने इस प्रश्न को लेकर मौन साध लिया और शायद यही मौन उनका आखिरी जवाब है।

यह बात सही है कि मोदी के अपने निजी प्रशंसकों की बड़ी फौज है जो उनको अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। हमारे यहां शास्त्र भी कहते ही हैं कि उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात् जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी उनका परिवार है। लेकिन इस परिवार का अर्थ यह नहीं कि आपके जैविक परिवार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भारतीय संविधान भले ही परिवार के अस्तित्व को स्वीकार न करे और उसकी जगह सिर्फ व्यक्ति को मान्यता देता हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत परिवार व्यवस्था के बाहर चला गया है। परिवार व्यवस्था भारतीय समाज संरचना का आधार है। व्यक्तियों का परिवार, परिवारों का कुल, कुलों का समूह जाति और जातियों का समूह मिलकर भारतीय समाज की संरचना करते हैं। भारत की इस सामाजिक संरचना से अगर जैविक परिवार को ही निकाल दिया जाए तो पूरी भारतीय सामाजिक संरचना भरभराकर गिर जाती है। इसलिए लालू ने मोदी के जिस परिवार पर सवाल किया है उसको राजनीतिक बयानबाजी करके ही नहीं मिटाया जा सकता। जो मोदी के समर्थक हैं या नहीं हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर हलचल पैदा करेगा कि मां के मरने पर भी मोदी ने मुंडन क्यों नहीं करवाया? स्वयं नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के जिस परिवारवाद पर प्रहार करते हैं तो उनका आशय डाइनेस्टी पॉलिटिक्स से होता है। मतलब एक ही परिवार में सत्ता सिमटकर नहीं रहनी चाहिए जैसे लालू यादव के परिवार में सिमटी हुई है। मोदी की इस बात से कोई असहमत भी नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में रजवाड़ा सिस्टम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनकी अपनी पार्टी में ही जब नेताओं के पुत्र-पुत्रियों को टिकट मिलता है तो वो उसका ठीक से बचाव नहीं कर पाते। अभी संसद के आखिरी सत्र में भी वे परिवारवाद पर बोल रहे थे लेकिन इस सवाल का ठीक से बचाव नहीं कर पाए कि उनकी पार्टी में नेता पुत्रों को टिकट क्यों दिया जाता है। तब उन्होंने यह कहा कि वो प्रतिभावान नेताओं को सिर्फ इसलिए किनारे करने के पक्षधर नहीं हैं कि उसका संबंध किसी नेता के परिवार से है।

● **विनोद बक्सरी**

चुनावी मुद्दा बनता जा रहा परिवार प्रथम या राष्ट्र प्रथम

इंडी एलायंस बनने के नौ महीने बाद उसी पटना में पहली रैली हुई, जहां एलायंस की पहली बैठक हुई थी। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि एलायंस की पहली बैठक बुलाने वाले नीतीश कुमार रैली में निशाने पर थे, क्योंकि वह एनडीए में वापस लौट चुके हैं। रैली में इंडी एलायंस के 31 में से सिर्फ चार दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिससे इंडी एलायंस की एकता का मैसेज नहीं जा सका क्योंकि एलायंस में शामिल दलों के मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, पिनयारी विजयन और चंपई सोरेन में से कोई भी शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों में से भी कोई नहीं पहुंचा। इसलिए रैली सिर्फ आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों का जमावड़ा बनकर रह गई, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा शामिल हुए। लालू यादव बड़ी-बड़ी रैलियां करने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की यह रैली उन रैलियों के मुकाबले की नहीं थी। भाषण तो सबके हुए, लेकिन अपने पुराने स्टाइल से भाषण देकर सारी वाहवाही लालू यादव ने लूट ली, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करके उनके हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया।

जम्हूरियत के नाम पर जमूरियत का प्रदर्शन

अरबी के शब्द जम्हूरिया का अर्थ होता है भीड़। लेकिन इसी जम्हूरिया को इस्लामिक देशों ने डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के रूप में परिभाषित कर लिया है। हालांकि इसका सटीक अर्थ होगा भीड़तंत्र। इस्लाम में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी बीसवीं सदी में मजबूरन जिन इस्लामिक देशों ने अपने आपको रिपब्लिक या डेमोक्रेसी घोषित किया उन्होंने वहां लोकतंत्र लाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंतत: वहां लोकतंत्र की बजाय जम्हूरियत या भीड़तंत्र ही आया है। पाकिस्तान इन्हीं में से एक है। पिछले महीने 8 फरवरी को पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली का एक और आम चुनाव हुआ। हर बार की तरह इस चुनाव को पर्दे के पीछे से पाक फौज ने संचालित किया। इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की इमरान खान से गहरी दुश्मनी है इसलिए चुनाव से पहले न केवल उनको 21 साल की सजा दिलवा दी गई बल्कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की मान्यता भी रद्द करवा दी गई।

इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप भी है और फौज पर हमले का आरोप भी। सत्ता के लालच में जल्द चुनाव कराने को बेताब इमरान खान पिछले साल रैलियां निकालकर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट (सत्ता पर नियंत्रण रखने वालों) पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव घोषित हो जाएं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, जो मुख्यरूप से फौज ही है, वह इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए नवाज शरीफ लंदन से बुलाए गए। उनको जमानत दिलवाई गई ताकि वो चुनावी मैदान में उतरकर इमरान खान का पत्ता साफ कर सकें। सारा मैदान साफ होने के बाद भी नवाज शरीफ ऐसा करने में सफल नहीं हो सके। जिस पीटीआई की मान्यता ही रद्द कर दी गई थी उस पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। मतदान के अगले दिन 9 फरवरी को मतगणना शुरू होनी थी। लेकिन शुरु हुई 10 फरवरी को। इस बीच फौज ने अपने अधूरे काम पूरे किए। फौज पर चुनाव में धांधली करने, खुद ठप्पा मारकर बैलट बॉक्स भरने का आरोप तो लगा ही था। इस देरी के बाद आरोप लगा कि नवाज शरीफ की पार्टी को विजेता बनाने के लिए फौज द्वारा मतपेटियां भी बदल गईं।

आखिरकार रिजल्ट आया तो वह चुनाव से भी ज्यादा पेंचीदा था। 266 सीटों में 93 निर्दलीय जीत गए थे। ये निर्दलीय कोई और नहीं बल्कि उसी पीटीआई के वर्कर बताए गए थे, जिन्होंने पार्टी सिंबल की बजाय निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया था। जिस नवाज शरीफ को फौज का संपूर्ण समर्थन था, उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 75 सीटों पर अटक गई और आसिफ अली जरदारी की पीपीपी 54 सीटों पर जीत के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। अब संकट यह खड़ा हुआ कि सरकार कौन बनाएगा? निर्दलीयों की कोई सरकार नहीं होती। प्रेसिडेंट के सामने आखिरकार किसी न किसी पार्टी को ही अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करना होता है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी पीटीआई अपना दावा पेश ही नहीं कर सकती थी क्योंकि पाकिस्तान चुनाव आयोग उसकी मान्यता ही खत्म कर चुका है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक बार फिर साथ आना चाहें तो पहले साथ रहने के दोनों के अनुभव बहुत खट्टे थे।

लेकिन अभी नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टियों की एक तकनीकी जीत होनी बाकी थी। पाकिस्तान में यह नियम है कि नेशनल एसेम्बली में राजनीतिक दल अपनी कुल सीटों का 33 प्रतिशत महिला और कुछ माइनॉरिटी मनोनीत करते हैं। इस लिहाज से शरीफ की पार्टी के हिस्से में 19 महिला और 4 माइनॉरिटी मेम्बर आए। इमरान खान के निर्दलीय समर्थक ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास किसी पार्टी का सिम्बल नहीं था। अत: महिलाओं और माइनॉरिटी को मनोनीत करने के बाद अब नवाज शरीफ की पार्टी के 98 मेम्बर हो गए तथा जरदारी की पार्टी में 68 मेम्बर। अब नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान इलेक्शन की सबसे पार्टी बन गई थी और इस तरह 3 मार्च को पाकिस्तान की 336 सीटों वाली (चुने गए और मनोनीत मिलाकर) नेशनल असेम्बली में 201 वोटों के समर्थन के साथ शाहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री घोषित हो गए। 2024 के नेशनल इलेक्शन में वो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हैं। मियां नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री बनने के लिए ही लंदन से वापस लौटे थे, अब फिर शायद छोटे भाई शाहबाज के कंधों पर इस्लामिक जम्हूरियत अर्थात् इस्लामिक भीड़तंत्र का जिम्मा लादकर लंदन लौट जाएं। पाकिस्तान में हुए आमचुनाव का यह संक्षिप्त विवरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किसी इस्लामिक देश में डेमोक्रेसी कितना कठिन रास्ता होता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

अस्थिरता का माहौल

इस्लामिक शरीयत के मुताबिक अमीर का शासन स्थापित करने का वैचारिक माहौल पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी तैयार कर रहे हैं। बहुत हद तक वो इसमें कामयाब भी हैं। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब कोई मुल्ला उमर या इस्लामिक शूरा पाकिस्तान पर भी हावी हो जाए और जम्हूरियत के नाम पर जारी जमूरियत को उखाड़कर हमेशा के लिए फेंक दे। इसमें अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह हैं वह वैश्विक आर्थिक संस्थाएं जो पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों के बाजार को खोना नहीं चाहती हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर सेकुलर वैल्यू रखने वाला व्यक्ति पाकिस्तान चलाएगा तो मुल्ला मौलवी द्वारा बनाया गया इस्लामिक निजाम का माहौल ठंडा पड़ जाएगा। शाहबाज शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी। इन पर दांव लगाकर फौज भी पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो जाने से ही बचाने का प्रयास कर रहा है। कम से कम ये दोनों इमरान खान की तरह हाथ में तस्बी (माला) लेकर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति पर जादू टोना करने का प्रयास तो नहीं ही करेंगे। पाकिस्तान के लिए फिलहाल वही सेकुलर वैल्यू वाला शासन है कि प्रधानमंत्री सूरा फातिहा पढ़कर अपने भाषण की शुरुआत न करे या फिर जिसके घर में बीवी के रूप में कोई जादूगरनी न बैठी हो। फिलहाल इन चुनावों में बड़ी मुश्किल से फौज इतना ही हासिल करने में सफल रही है। लेकिन कब तक? अगर अफगानिस्तान हो जाना ही पाकिस्तान की नियति हो तो कोई अमेरिका, यूरोप, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या फौज उसे कब तक रोककर रख पाएंगे?

बाइडन की बेचारगी

जब एक बड़े अमेरिकी नेता (जो बाइडन) के लिए कुछ भी ठीक न हो रहा हो, तब उसे धर्म (बाइबिल) की शरण में जाना ही पड़ता है। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके धर्म में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो उनके विरोधी (डोनाल्ड ट्रंप) को ईश्वर की पसंद बता रहे हैं। वृद्धावस्था के स्वाभाविक लक्षणों से जूझ रहे बाइडन को उन किताबों में ही सांत्वना मिल सकती है, जो बुढ़ापे को जीवन के गौरवशाली शिखर के रूप में स्थापित करती हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के न्याय विभाग द्वारा नियुक्त किए गए विशेष जांच अधिकारी ने ओबामा के प्रशासन छोड़ने के बावजूद आधिकारिक दस्तावेजों के उनके पास होने की जांच की, पर उन्हें दोषी नहीं पाया। हां, जांच अधिकारी ने बेहद विनम्रतापूर्वक उनकी मानसिक तीक्ष्णता पर संदेह जरूर प्रकट किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, राष्ट्रपति नेक इरादे वाले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनकी याद्दाश्त कमजोर है और बुढ़ापे में उनकी क्षमताएं भी कुछ कमजोर हुई हैं।

एक राष्ट्रपति, जो मैक्रों को मिटर्रेंड और मर्केल को कोहल समझ लेते हैं और उस आतंकी संगठन तक का नाम भूल जाते हैं, जिसके साथ इस्राइल गाजा में लड़ रहा है, मुमकिन है कि याद्दाश्त संबंधी समस्याओं से जूझ रहा हो। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की ये व्यक्तिगत समस्याएं क्या वाकई इतनी सामान्य हैं? आप कभी-कभार हैरान-सी दिखने वाली उनकी मुख-मुद्रा को देखिए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके तौर-तरीके व उनकी फिटनेस को देखिए, ये सब दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी पात्रता के बारे में सार्वजनिक चिंताओं को बढ़ाते हैं, जिसके अंत में वह 86 वर्ष के हो जाएंगे। शारीरिक भाव-भंगिमाओं से वह खुद को युवा दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जो चीजें स्वाभाविक रूप से भीतर से आ रही हों, उन्हें क्या कहें? एक लेखक कहते हैं कि जो बाइडन को अपने सामने देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी प्रतिमा में तब्दील हो रहे हैं।

क्या यह अमेरिकी स्वप्न का धूमिल होना है, क्योंकि 2024 का चुनाव, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर होगी, दो बुजुर्गों के बीच होने वाली प्रतियोगिता बन गई है? 77 साल के डोनाल्ड ट्रंप अपेक्षाकृत युवा प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन तमाम सर्वेक्षण, रिपब्लिकन और व्यापक रूप से जनता उनकी उम्र को लेकर कम चिंतित दिखाई देती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह प्रतीत होता है कि बढ़ती उम्र ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया है, जिससे वह परंपरागत राजनीति को रौंदने वाले महामानव ज्यादा दिखने लगे हैं।

दूसरी ओर, बाइडन के अपने उदार प्रशंसक हैं, जो तर्क दे सकते हैं कि शारीरिक-मानसिक कमजोरियां भले उनकी सार्वजनिक मौजूदगी में दिखती हों, पर इनका राष्ट्रपति के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह कि राजनीति और शासन में कुछ चीजें अंदरखाने में चलती हैं, इसलिए इस मामले में चुप्पी ही श्रेष्ठ है। लेकिन इस तर्क में दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेता की शारीरिक-मानसिक कमजोरी के अलावा एक गंभीर लोकतांत्रिक हताशा भी छिपी है।

बाइडन की पार्टी खुद उनसे पीड़ित है, क्योंकि वह ट्रंप नहीं हैं। दूसरी ओर, रिपब्लिकन बेहद गुस्से वाले ट्रंप को नाराज करने से बहुत डरते हैं। बाइडन की चौंका देने वाली बेतरतीबी और ट्रंप का कच्चा यथार्थवाद एक पुरानी कहावत की सीमा को उजागर करता है कि जितना अधिक शरीर बूढ़ा होता है, आप उतने ही समझदार होते हैं।

यह कहावत दरअसल पूर्व से ली गई है, जहां बुद्धिमान लोग हमेशा एक खास क्षेत्र के माने जाते थे। जब चीनी साम्यवाद ने अपने सांस्कृतिक इतिहास से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपनाया, तो झोंगनानहाई के प्राचीन साथियों को जीवंतता की अतिरिक्त खुराक मिल गई। हालांकि कन्फ्यूशियस ने कभी सार्वजनिक मंच नहीं छोड़ा। माओ जब मार्क्स से मिलने के लिए रवाना हुए, तब वे 82 वर्ष के थे। माओ के बाद सबसे प्रभावशाली चीनी देंग जियाओपिंग, जो सांस्कृतिक क्रांति के बाद भी बचे थे, जब मंच छोड़ा, तो 92 वर्ष के थे। जाहिर है कि बुढ़ापे ने इन महान व्यक्तियों की गति कभी धीमी नहीं की। इनकी सक्रियता शारीरिक बंधनों के बावजूद बनी रही। इतिहास बताता है कि क्रांतियां तभी परिपक्व होती हैं, जब उन्हें पुराने क्रांतिकारियों द्वारा पोषित किया जाता है। जाहिर है कि उम्र का अपना महत्व होता है और पूर्व ने इस चीज को हमेशा महत्व दिया है। वह हमेशा से ही बुद्धिमान बुजुर्गों का पक्षपाती रहा।

● **कुमार विनोद**

भारत में भी कई प्रधानमंत्रियों की उम्र 70 पार

हमारे देश में बाइडन जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। जब मोरारजी देसाई अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदा उम्र 81 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री बने, वह भारतीय राजनीति के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तो थे ही, कांग्रेस-विरोधी लहर की पहली पंक्ति के राजनेता भी थे। उनके पास स्वस्थ रहने के अपने स्वदेशी तरीके थे। लेकिन उन्होंने कभी भी जयप्रकाश नारायण को जगजीवन राम समझने की भूल नहीं की। उनके उत्तराधिकारी बनने वाले चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनने का सपना जब पूरा हुआ, तब वह उनसे मात्र चार वर्ष छोटे थे, जो 77 वर्षीय ट्रंप से कुछ ही महीने कम थे। 81 साल की उम्र में अपने सपनों का पीछा करने वाले आडवाणी के रास्ते में बाधा बनकर उम्र खड़ी नहीं हुई, बल्कि एक यात्रा थी, जिसने उन्हें विफल बना दिया। शायद हमने आदर्शवादियों की अपेक्षा अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी। हो सकता है कि जैविक उम्र को हराने के विज्ञान की शुरुआत पूर्वी परंपराओं में हुई हो। हमने लंबे समय तक जीने के लिए अपने सिर के बल खड़े होना, सांस रोकना और मोर की तरह मुद्रा बनाना सीख लिया है। तो क्या बाइडन की शारीरिक-मानसिक समस्याओं का कोई सांस्कृतिक पहलू है? यह लोकतांत्रिक कॉफ़ेफे का मामला हो सकता है। इस शब्द का इस्तेमाल एक बार ट्रंप ने टाइपिंग की गलती से कवरेज के लिए किया था। अगर यह बात जो बाइडन ने कही होती, तो जाहिर है कि इसे बेहद सामान्य माना जाता।

स्नेहिल रिश्तों में भी हो हर कदम पर सावधानी

युवतियां-महिलाएं कई बार फरेब भरे रिश्तों के जाल में फंस जाती हैं चाहे वह वर्चुअल दुनिया हो या असल। कुछ स्वार्थी लोग दोस्ती के नाम पर महिला के जीवन की जानकारी लेते हैं और खुद दुराव-छुपाव रखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि स्नेहमयी रिश्तों में भी हर कदम सजगता बरतें।

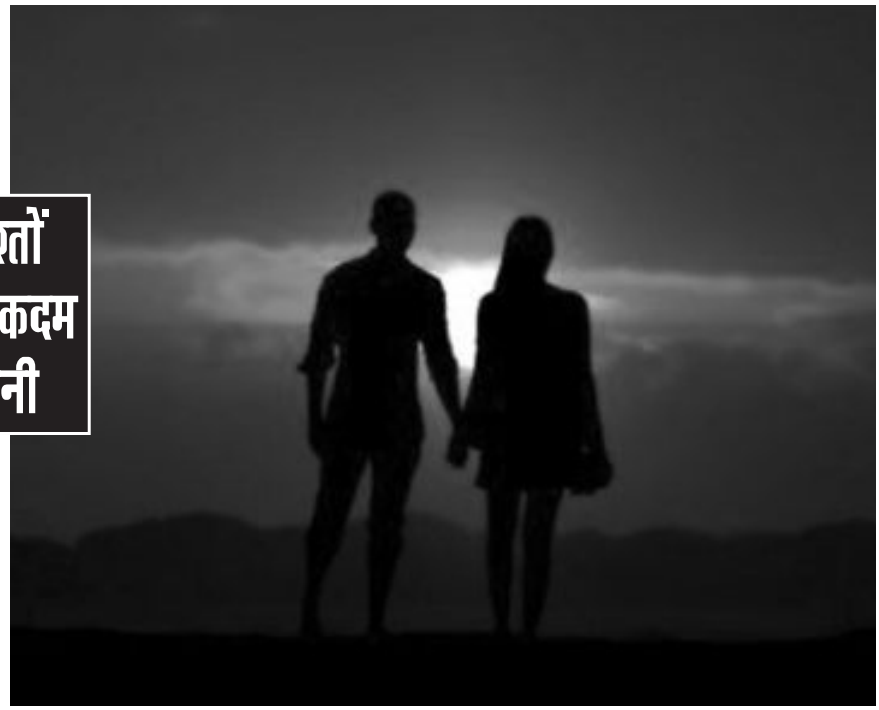

मन से जुड़े संबंधों में धोखा खाने की खबरें आए दिन सामने आती हैं। अधिकतर महिलाएं ऐसे रिश्तों की उलझनों में फंसकर अपने लिए अनगिनत समस्याओं को न्योता दे बैठती हैं। इसे भावनात्मक बहाव कहें या आज की उलझती जिंदगी की मन:स्थिति का भटकाव। युवतियां ही नहीं, महिलाएं भी कई बार फरेबी रिश्तों के जाल में फंस जाती हैं। आपराधिक घटनाओं के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पढ़ने, करियर बनाने की राह पर चलती बेटियां भी धोखेबाजी का शिकार हो रही हैं और घर-गृहस्थी बसा चुकी महिलाएं भी। कहीं वर्चुअल दुनिया से शुरू हुई बातचीत बहकावे के हालात बना देती है तो कहीं वास्तविक संसार में कमजोर मन:स्थिति को भांपकर लोग दिशाहीनता की परिस्थितियां पैदा करते हैं। जरूरी है कि महिलाएं समय रहते चेतें। व्यावहारिक धरातल पर भी ऐसे रिश्तों को परखें। साथ ही अपने जीवन से जुड़े दूसरे रिश्ते-नातों की उलझनों के दौर में थोड़ा संयत होकर सोचें। अधिकतर मामलों में ऐसे फरेबी रिश्ते जीवन को देते तो कुछ नहीं, पर छीन बहुत कुछ लेते हैं। इस तरह की धोखेबाजी को पहचानिए।

प्रेम और लगाव के नाम पर महिलाओं को भावनात्मक सहारा देने का फरेब करने वाले लोग अपने पारिवारिक रिश्तों की बात कभी नहीं करते। वे पहले से जानते हैं कि यह एक अस्थायी जुड़ाव है, अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई पहलू आपके सामने नहीं लाएंगे। जबकि महिलाएं मन-जीवन से जुड़ी बहुत सी बातें साझा कर लेती हैं। कई बार तो आगे चलकर ऐसी गलतियां ब्लैकमेलिंग का कारण बनती हैं। युवतियों को अपने भविष्य को लेकर डराया जाता है तो विवाहित महिलाओं को पारिवारिक बिखराव को लेकर। किसी से प्रेमपगा जुड़ाव रखना गलत नहीं है पर सजगता तो ऐसे स्नेहमयी रिश्तों में भी बरतनी ही चाहिए।

यह बात हर महिला को समझनी चाहिए कि समय बिताने के लिए आपसे जुड़ने या लगाव के नाम पर दिखावा करने वाले इंसान में इमोशनल जुड़ाव का बहाव नहीं होगा। घंटों फोन पर बतियाने, वीडियो चैट करने या मिलने के बावजूद मन का कोई कनेक्शन जोड़ने की कोशिश ही नहीं की जाएगी। वहीं कथनी और करनी में भी फर्क रहता है। ऐसे इंसान का ध्यान अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर ही रहता है। एजेंडे के साथ ऐसे निष्ठाहीन व्यक्ति अंतरंगता बढ़ाने के बाद भी आपको अपनी दुनिया में शामिल नहीं करते। मित्र या परिजन, किसी से मिलवाने में हिचकते हैं, बहाने ढूंढकर बचते हैं। आपके जानकारों से मिलने से भी बचता है। अपनी पहचान सामने लाना ही नहीं चाहते। ऐसी बातों और बर्ताव को लेकर सजग रहिए।

धोखेबाजी के ऐसे रिश्तों में विश्वास करने से कहीं ज्यादा शक की स्थितियां बनती हैं। बावजूद इसके महिलाएं भावुक होकर बनावटी बातों के फेर में फंसती जाती हैं। एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं कि महिलाओं ने जानते-बूझते इस भंवर में डूबने की गलती की। अपने जीवन में दुश्वारियां पैदा कर लीं। जबकि ऐसे व्यक्ति के लिए रिश्ते के पहले ही पड़ाव से उनकी भावनाएं और इच्छाएं कोई मायने नहीं रखतीं। ऐसे लोग फरेब के इस खेल में माहिर होते हैं। मिलने-जुलने का समय तक अपनी योजनाओं के अनुसार निकालने वाले ऐसे लोग आर्थिक रूप से सक्षम युवतियों और महिलाओं से फाइनेंशियल मदद के नाम पर भी ठगी करते देखे जाते हैं। समझना जरूरी है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान की आवश्यकताओं, परिस्थितियों और चिंताओं को ध्यान में रखे बिना संबंध जोड़ता है तो अपने निजी फायदे के सिवा कुछ और नहीं सोच पाता। उनका टॉक्सिक व्यवहार बनावटी-दिखावटी बातों से महिलाओं के मन को दिशाहीन करता है।

● **ज्योत्सना**

वर्चुअल धोखेबाजी की राह

आजकल वर्चुअल दुनिया के जुड़ाव में यह फरेब खूब देखने को मिल रहा है। क्योंकि आभासी संसार में अपनी असलियत छिपाना और आसान है। वर्चुअल धोखेबाजी वाले लोगों से ऑनलाइन जुड़ाव रखने में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। टेक्स्ट मेसेज हो या वॉइस कॉल, महिलाएं सजग रहें। बहकावे में आकर अपनी कोई तस्वीर या वीडियो न भेजें। मर्यादा से परे बात न करें। पीड़ा जताने से भी बचें। रोमांटिक रिश्तों के फेर में उपजते बिखराव की स्थितियां ऐसी हैं कि देश के 19 महानगरों में अपराध के आंकड़ों से जुड़ी एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में हत्या के मामलों की तीसरी सबसे बड़ी वजह लव अफेयर बताया गया है। ऐसे मामले आत्महत्या की भी बड़ी वजह हैं। ऑनलाइन दुनिया के रोमांस स्कैमर्स स्नेह, साथ और वर्चुअल संवाद के नाम पर झांसा देते हैं। इसीलिए असल दुनिया हो या वर्चुअल वर्ल्ड, महिलाएं ऐसे फरेबी रिश्तों को समय रहते समझें।

श्री रामचरितमानस में सामाजिक समरसता

यदि हम सामाजिक समरसता की दृष्टि से देखें तो वहां भी रामचरितमानस हमें प्रतिबिम्ब और पथ दोनों दिखाता है। प्रतिबिम्ब इसलिए कि हम अपने व्यक्तित्व एवं तदनुरूप कार्य व्यवहार व सामाजिक योगदान के वास्तविक रूप को जान सकें, और पथ इसलिए कि जहां हम एक समाज के रूप में भटक रहे हैं वहां सन्मार्ग का चयन कर सकें और उस पर चलने का साहस-सामर्थ्य जुटा सकें। इसी क्रम में श्रीराम को मनाकर वापस ले जाने के लिए चित्रकूट जाते हुए भरत की भेंट निषादराज से होती है तो इस समरसता और मर्यादा का अद्‌भुत दृश्य देखने को मिलता है जब निषाद अपना नाम बताता है-

देखि दूरी ते कहि निज नामू... (बताने के लिए कि मैं नीची जाति का हूं), और इस पर भरत की प्रतिक्रिया इस समरसता का प्रमाण देती है जब वह अपना रथ त्याग कर बड़े प्रेम से उसकी ओर जाते हैं -

राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा,
चले उतरि उमगत अनुरागा।
करत निषाद दंडवत पाई,
प्रेमहि भरत लीन्ह उर लाई।
भेंटत भरत ताहि अति प्रीती,
लोग सिहाहिं प्रेम कइ रीती।...

और इसकी अप्रत्याशित पराकाष्ठा तो तब होती है जब चित्रकूट में निषाद नीची जाति का होने के कारण डर व संकोचवश दूर से प्रणाम करता है और मुनि वशिष्ठ (ब्राह्मण होने के नाते जिनसे अधिक ऊंचा व प्रतिष्ठित होने की उस समय कल्पना नहीं की जा सकती) निषादराज को अपने बाहुपाश में भरकर मिलते हैं -

प्रेम पुलक केवट कहि नामू
कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू,
रामसखा ऋषि बरबस भेंटा
जिमि महि लुठत सनेह समेता।

मानस में वर्णित यह सामाजिक सद्‌भाव यहीं तक-अर्थात् निषाद (आज के सामाजिक संदर्भों में तथाकथित अनुसूचित जाति) तक सीमित नहीं रहता। इसके आगे श्रीरामचरितमानस जनजाति को भी समाज का अभिन्न और सम्मानित अंग बनाता है जब गोस्वामी तुलसीदासजी श्री हनुमान जी के माध्यम से वानरराज सुग्रीव की भेंट भगवान राम से करवाते हैं।

किसी ने वानर को वन में रहने वाला नर कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुग्रीव और उनकी सेना के सदस्य वानर-भालू ही न होकर जंगल में रहने वाली जातियां रही होंगी जो कि नगर और गांव में रहने वालों से कम शिक्षित-सभ्य मानी जाती रही होंगी (यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से हनुमान जी को इस श्रेणी में रखना अनुचित होगा)।

किष्किंधा में राम-लक्ष्मण से भेंट होने पर हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव का परिचय देकर उनके साथ मित्रता का निवेदन करते हैं -

नाथ शैल पर कपि पति रहई,
तेहि संग नाथ मयत्री कीजै।

मानस में किष्किंधाकांड का प्रसंग रखने की पृष्ठभूमि में गोस्वामी जी के मन में केवल मित्रता मात्र का वर्णन करना नहीं था वरन इसके माध्यम से वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि राजा (शासक) को किसी बड़े काम की सफलता के लिए (चाहे वह शत्रु-विजय हो अथवा कोई अन्य बड़ा सामाजिक-राष्ट्रव्यापी अभियान), जन-सहभागिता (सबके विकास के लिए सबका साथ) परम आवश्यक है। मानस के उपर्युक्त प्रसंग इस बात की पर्याप्त पुष्टि करते हैं कि समरसता (सोशल हारमनी) के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण (नेशनल इंटीग्रेशन) रामचरितमानस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्‌देश्य रहा है।

यदि हम थोड़ी और गहराई में उतरें तो पाएंगे शंकर और राम (अर्थात् शैव-वैष्णव) समीकरण-एकीकरण मानस का छिटपुट प्रसंग न होकर यत्र-तत्र-सर्वत्र का प्रसंग है। इसका प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि श्रीराम-शंकर का परस्पर स्नेह-सम्मान, पूजा-अर्चना बालकांड से प्रारंभ होकर अयोध्याकांड और लंकाकांड होते हुए उत्तरकांड तक बारहमासी पवित्र सलिला सदृश निरंतर चलती रहती है।

वनगमन-प्रसंग में भी श्रीराम अपने चौदह-वर्षीय वनवास की यात्रा पर अयोध्या से प्रस्थान करते समय विघ्नहर्ता गणेश और मां भवानी के साथ भगवान शंकर का ही स्मरण करते हैं

गणपति गौरि गिरीसु मनाई,
चले असीस पाई रघुराई।

और गंगा जी को पार करने के बाद पुनः शंकर को शीश झुकाकर वनगमन करते हैं -

तब गणपति सिव सुमिरि प्रभु,
नाइ सुरसरिहि माथ।
सखा अनुज सिय सहित वन,
गवन कीन्ह रघुनाथ।

लंका विजय हेतु सेतु बंधन के समय जब परंपरानुसार पूजा की बात आती है तो भगवान राम कहते हैं -

करिहउं इहां संभु थापना,
मोरे ह्रदय परम कल्पना।
लिंग थापि विधिवत करि पूजा,
सिव समान प्रिय मोहि न दूजा।
सिव द्रोही मम दास कहावा,
सो नर मोहि सपनेहुं नहि पावा।
संकर विमुख भगति चह मोरी,
सो नारकी मूढ़ मति थोरी।
संकर प्रिय मम द्रोही,
सिव द्रोही मम दास।
सो नर करहिं कल्प भरि,
घोर नरक माह बास।

राम से ऐसा कहलवाकर तुलसीदास जी वैष्णवों को भी शैवों के प्रति वैर-वैमनस्य छोड़कर उन्हें मैत्री भाव हेतु प्रेरित ही नहीं बल्कि विवश करते हैं। कितना अद्‌भुत और सुखद है कि यह क्रम सेतुबंध के साथ यहीं समाप्त न होकर लंका-विजय तक चलता है जब समस्त देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना के क्रम में भगवान शंकर आते हैं और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल-नयन समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव विनती करते हुए कहते हैं-

मामभिरक्षय रघुकुल नायक,
धृत वर चाप रुचिर कर सायक।
अनुज जानकी सहित निरंतर,
बसहु राम नृप मम उर अंतर।

इसके साथ यह कहकर जाते हैं कि-

नाथ जबहि कौशल पुरी होइहि तिलक तुम्हार,
कृपासिंधु मैं आउब देखन चरित तुम्हार।

और अयोध्या आने के बाद जब श्रीराम-राज्याभिषेक होता है तो पुनः शंकर जी का आगमन होता है -

बैनतेय सुनु संभु तहं आये जहं रघुबीर,
बिनय करत गद्‌द गिरा बोले पुलक सरीर।
जय राम रमा रमनं समनं
भवताप भयाकुल पाहि जनम।

और अंत में-बरनि उमापति रामगुन हरखि गए कैलास।

यह पंथ अथवा संप्रदाय-आधारित राष्ट्रीय-एकता में मानस के योगदान की बात है।

● ओम

विचारों की फसल

मैं नहीं छोड़ जाऊंगा
धन-संपदा विरासत में कोई
बीमा भी कोई नहीं
कि मरने पर तुमको प्रतिदान मिले
बच्चों, निराश पर मत होना
ये लेखन, जो
मिट्टी के लगता मोल अभी
अनमोल किसी दिन
साबित होने वाला है
आने वाली पीढ़ियों को
यही राह दिखाने वाला है।
वह लेखक था आश्वस्त स्वयं,
बच्चों को भी
आश्वस्ति यही देने की
कोशिश करता था
निर्धन होकर भी मन से था समृद्ध
नहीं चिंता भविष्य की अपनी या
बच्चों की कोई करता था
बोए थे उसने बीज विचारों के
जो,
था निश्चिंत
बड़े होकर फल से वे पेड़ सभी
लद जाएंगे
दुनिया को वैचारिकता से
समृद्ध खूब कर जाएंगे।
जाने पर कैसी थी जमीन,
या बीज बांझ थे!
फसल नहीं लहलहा सकी,
समृद्ध न मन हो सके
नहीं सह पाया सदमा,
लेखक वह मर गया
समझ ही पाया नहीं अंत तक,
गलती कहां हुई
बंजर तो बीज न हरगिज थे,
क्यों नहीं उगे?
सदियां बीतीं,
वह पीढ़ी मर-खप गई,
नई कोंपल फूटी
लहलहा उठी दुनिया में
फसल विचारों की
बोए थे बीज विचारों के
जो लेखक ने
वे फलीभूत अब हुए
नहीं दुनिया में वह सशरीर
देख पाया यह सब
पर कहते हैं बारिश की बूंदों,
या कोयल की कूकों में
उस लेखक की
आवाज सुनाई देती है!

- हेमधर शर्मा

निर्मम खुशी

अरे, सुन! तुझे एक खुशखबरी सुनाती हूं। फोन पर एक चहकती हुई आवाज आई।

हां, बता न। दूसरी ओर भी बेसब्र आवाज थी।

तुझे बताया था न कि मेरी मेड काम छोड़ रही है!

हां, तुम बता रही थी कि उसकी शादी होने वाली है।

हां वही! मेरा तो बीपी बढ़ गया था यार, कैसे मैनेज करूंगी? इस दिसंबर की ठंड में! कोई मिल भी नहीं रही थी।

कोई नई मिल गई क्या? तेरी आवाज तो बड़ी खुश लग रही है!

अरे, सुन तो। आज बोल गई है कि वह काम नहीं छोड़ेगी, करती रहेगी।

क्यों? चौंकते हुए पूछा।

शादी टूट गई।

ओह बेचारी!

तू क्यों दुखी हो रही है। इनका क्या? आज इससे, कल उससे। मेरी तो जान बच गई इस कड़ाके की ठंड में। आवाज ठहाके में बदल गई।

अच्छा रखती हूं आज आराम से मेनिक्योर-पेडीक्योर करवाऊंगी।

और फोन कट गया।

- सत्या शर्मा 'कीर्ति'

अनुकम्पा

रेलवे से रिटायर हुए थे गिरधारी बाबू। दफ्तर के सहकर्मी ढोल-धमाके के साथ जुलूस की शक्ल में उन्हें घर छोड़ने आए...

शाम ढले ढाई-तीन सौ लोगों का खाना था, ऐसा लग रहा था मानो बरात जीम रही हो। सब कुछ ठीक-ठाक निपट गया। फूलों की मालाओं के बोझ तले दबे गिरधारी बाबू को पहली बार अपने कुछ होने का अहसास हुआ... किंतु यह अहसास इतना भारी पड़ा कि रात सोए तो सोते ही रह गए।

सुबह डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि साइलेंट हार्ट अटैक था। सारे घर में कोहराम मच गया। बाहर से आए रिश्तेदार भी इस सुकून के साथ शवयात्रा में शरीक हो गए कि अच्छा रहा, दुबारा नहीं आना पड़ेगा। रामप्यारी की रुलाई समझी जा सकती थी, बुढ़ापे में पति की विछोह वेदना... पर बेटे बिरजू का हाल देखकर सभी रिश्तेदार करुणार्द हो उठे। सभी ढांढस बंधा रहे थे पर बिरजू की रुलाई का बांध टूट चुका था और उसके आंसू के सैलाब से पूरा घर तर-बतर हो चुका था।

छोरे को पिता की मौत का गहरा सदमा लगा है सभी लोग यही कुछ बुदबुदा रहे थे।

तीए की बैठक के बाद गम गलत करने के लिए बिरजू भी बोतल खोलकर दोस्तों के साथ बैठा तो अनायास ही कह उठा- यार माधो बाऊजी दो-चार दिन पहले ही मर जाते तो कितना अच्छा रहता, रिटायरमेंट की पार्टी का पचास-साठ हजार का खर्चा भी बच जाता और मुझे उनकी जगह रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति भी मिल जाती। इस बेरोजगारी से तो छुटकारा मिलता यार...

खाली गिलास फर्श पर पटकते हुए माधो सोच रहा था कि- पापाजी भी अगले साल रिटायर होने को हैं, क्या मुझ पर इतनी भी अनुकंपा नहीं कर सकते...!

- मोहन राजेश

अंग्रेजों की भारत आकर दुर्गति

इंग्लैंड की बैजबॉल रणनीति भारतीय टीम के खिलाफ काम नहीं आ सकी और उसे 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय खिलाड़ी अंग्रेजों पर बीस साबित हुए। इंग्लिश बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट्स मारने के प्रयास में अपने विकेट गंवाए। बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड को भारत के हाथों पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-4 से हार झेलनी पड़ी। भारतीय धरती पर इंग्लिश टीम की यह लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज हार रही। दूसरी ओर भारतीय टीम की अपने घर पर ये लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीत रही। भारत ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने अपने घर पर लगातार 17 टेस्ट सीरीज में विजय हासिल की।

इंग्लैंड की टीम जब भारत आई थी, तो बैजबॉल की काफी चर्चा हो रही थी। इंग्लिश खिलाड़ी इस रणनीति के दम पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में मात देने का ख्वाब देखने लगे थे। शुरुआती टेस्ट मैच में तो इंग्लैंड ने भारत को पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया। पहले वाइजैग... फिर राजकोट, रांची और धर्मशाला में इंग्लैंड की बैजबॉल रणनीति फुस्स हो गई।

चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फील्डिंग... तीनों डिपार्टमेंट में भारतीय खिलाड़ी अंग्रेजों पर बीस साबित हुए। पूरी सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ज्यादातर समय आक्रामक शॉट्स मारने के प्रयास में अपने विकेट गंवाए। जबकि भारतीय विकेट्स पर आक्रामकता के साथ संयम की काफी जरूरी होती है। यदि इंग्लिश बल्लेबाज सूझबूझ भरा क्रिकेट खेलते, तो शायद यह सीरीज काफी रोमांचक होती। इंग्लैंड की सीरीज हार में इन 5 खिलाड़ियों का अहम रोल रहा।

बेन स्टोक्स: इस सीरीज में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का प्रदर्शन काफी खराब रहा। स्टोक्स खासकर भारतीय स्पिनर्स के सामने बुरी तरह फ्लॉप रहे। स्टोक्स ने 10 पारियों में 199 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा। स्टोक्स का एवरेज 19.9 का रहा और उन्होंने सिर्फ 367 गेंदों का सामना किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव की तुलना में सिर्फ 5 गेंदें ज्यादा खेलीं। साथ ही स्टोक्स ने अपनी टीम के स्पिनर टॉम हार्टले से सिर्फ 14 रन ज्यादा बनाए।

बेन डकेट: ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट बैजबॉल को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करते नजर आए थे, लेकिन उनका बल्ले से प्रदर्शन बेहद खराब रहा। डकेट की 153 रनों की पारी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी इनिंग्स में उनका बल्ला खामोश रहा। डकेट ने 10 पारियों में 34.3 के एवरेज से सीरीज में 343 रन बनाए। डकेट का स्ट्राइक रेट (85.75) जरूर शानदार रहा।

147 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। इसका आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला गया। इस सीरीज में आर अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट और जेम्स एंडरसन ने 700 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छुआ। लेकिन अब, सीरीज में वह रिकॉर्ड तार-तार हुआ, जो 147 सालों से चला आ रहा था। यह सीरीज काफी ऐतिहासिक रही है। दरअसल 147 सालों के पुराने इतिहास में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पहली ऐसी सीरीज बनी, जिसमें 100 छक्के पूरे हुए। इन छक्कों को पूरा करने में भारतीय बैटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों को ढंग से रिमांड पर लिया। इस टेस्ट को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सीरीज में मेजबान भारत के खिलाफ मेहमान इंग्लैंड पूरी तरह फेल दिखाई दी है। इंग्लैंड हर डिपार्टमेंट में भारत के आगे बौनी दिखी। इंग्लैंड ने सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन फिर टीम इंडिया ने ऐसी वापसी की, कि इंग्लैंड के लिए कोई चांस नहीं छोड़ा। पांच टेस्ट की सीरीज को रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने सीरीज में 4-1 की अजेय बढ़त से जीत लिया। इसके साथ ही भारत टेस्ट में नंबर वन पायदान पर पहुंच गया है।

जॉनी बेयरस्टो: मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो अपने खेल से ज्यादा विवादों में रहे। धर्मशाला टेस्ट मैच के दौरान बेयरस्टो की शुभमन गिल और सरफराज खान से बहस हो गई थी। बेयरस्टो ने 10 पारियों में 23.80 की खराब औसत से 238 रन बनाए। बेयरस्टो इस सीरीज में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए।

ओली पोप: इंग्लिश बल्लेबाजी की धुरी माने जाने वाले ओली पोप ने अपने फैन्स को काफी निराश किया। पोप ने जरूर हैदराबाद टेस्ट मैच में 196 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद वह एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए। इंग्लैंड के उप-कप्तान पोप ने इस सीरीज में 31.5 के एवरेज से 315 रन बनाए।

मार्क वुड: तेज गेंदबाज मार्क वुड ने इंग्लिश फैन्स को काफी निराश किया। वुड ने इस सीरीज में कुल पांच पारियों में 4 विकेट लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि वुड ने ये चारों विकेट एक ही पारी में लिए। बाकी की चार इनिंग्स में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। भारतीय बल्लेबाजों ने वुड की जमकर क्लास लगाई।

ब्रैंडन मैक्कुलम की कोचिंग और बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की यह पहली सीरीज हार रही। मैक्कुलम को मई 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया था। मैक्कुलम की कोचिंग में इंग्लैंड टीम ने टेस्ट फॉर्मेट में भी तेजी से खेलना शुरू किया। मैक्कुलम अपने समय में जब क्रिकेट खेलते थे तो वो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते थे। तब उनका निकनेम बैज था। इसी निकनेम के साथ बॉल को जोड़ते इंग्लिश टीम ने बैजबॉल शब्द निकाला। यानी इसका मतलब ब्रैंडन मैक्कुलम का निकनेम और उनके खेलने के अंदाज से है।

● **आशीष नेमा**

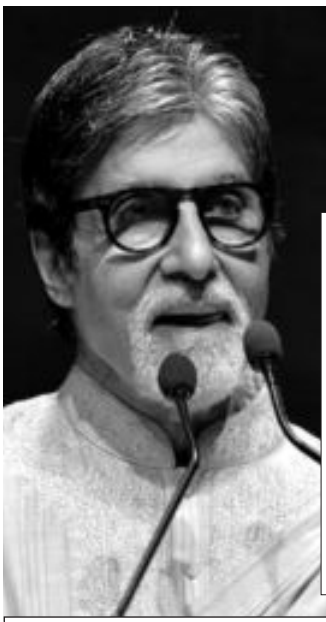

...जब जीतेंद्र-राजेंद्र कुमार के झगड़े में बिग बी को मिल गई फिल्म, और बदल गई किस्मत

कहते हैं कि जीतेंद्र ने दुलाल गुहा को साइनिंग अमाउंट देने के दो दिन बाद सलीम-जावेद के साथ फिल्म की कहानी सुनने के लिए बुलाया।

अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार स्टारर साल 1978 की फिल्म त्रिशूल के बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस फिल्म को जीतेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों बनाना चाहते थे। फिल्म की कहानी थी ही इतनी असरदार, जिसमें एक बेटा अपने पिता को नाजायज बाप कहकर बुलाता है और तालियां बटोर ले जाता है। फिल्म की कहानी एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपनी गर्भवती प्रेमिका को छोड़ एक रईस की बेटी से शादी कर लेता है। बिजनेमैन के शादी के

बाद और शादी से पहले के बच्चे जब आमने-सामने होते हैं, तो क्या तूफान आता है, इसी की कहानी है त्रिशूल। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई है और इसका क्लाइमेक्स फिल्माया गया प्रगति मैदान में।

दो अन्य सुपरस्टार भी बना चुके हैं इसी कहानी पर फिल्म... फिल्म का प्लॉट ही इतना जबर्दस्त था कि जीतेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों ने इस कहानी को पहली बार में ओके कर दिया। बस, निर्देशक दोनों ने एक ही चुन लिया, दुलाल गुहा। कहते हैं कि जीतेंद्र ने दुलाल गुहा को साइनिंग अमाउंट देने के दो दिन बाद सलीम जावेद के साथ फिल्म की कहानी सुनने के लिए बुलाया। यहीं गुहा को पता चला कि ये तो वही कहानी है जो राजेंद्र कुमार उनको सुना चुके हैं। जीतेंद्र और राजेंद्र कुमार में फिल्म कौन बनाएगा, इस बात को लेकर लंबी बहस हुई। आखिर में दुलाल गुहा ने ही साइनिंग अमाउंट लौटाकर इस फिल्म से तौबा कर ली। यही फिल्म बाद में गुलशन राय तक पहुंची और बनी यश चोपड़ा निर्देशित अमिताभ बच्चन स्टारर त्रिशूल। तकरीबन, इसी कहानी पर बाद में 1981 में बनी कमल हासन की फिल्म कादल मीनगल और 1986 में बनी रजनीकांत की फिल्म मिस्टर भारत।

फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान किरण राव को खुद पर हो रहा था संदेह...

किरण राव इन दिनों अपनी फिल्म लापता लेडीज को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। कम लागत से बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में लापता लेडीज की निर्देशक किरण राव अपने शुरूआती दिनों के बारे मीडिया से बातें करती नजर आईं। उन्होंने फिल्म लगान की शूटिंग से जुड़े दिलचस्प किस्से भी साझा किए।

लगान आमिर खान की सबसे बड़ी हिट फिल्मों से एक है। किरण कहती हैं, इस फिल्म के निर्माण के दौरान मैं ज्यादातर मेकअप रूम में ही रहती थी। मैंने कई बार सोचा कि मॉनिटर के पास बैठकर मैं फिल्म की शूटिंग देखूं, लेकिन वह कभी संभव नहीं हुआ। मैं कलाकारों के लिए सामान लाने और ले जाने का काम करती रह गई। हां, फिल्म पूरी हो जाने के बाद मुझे काफी खुशी हुई कि मैं इस महान फिल्म का हिस्सा बनी।

खुद पर हुआ संदेह

किरण राव ने बतौर सहायक निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान में काम किया था। बीते दिनों को याद करते हुए किरण ने कहा, मैं फिल्म लगान के सेट पर साढ़े चार बजे पहुंच जाती थी। मेरा काम फिल्म के कलाकारों के लिए मेकअप, बाल और तमाम चीजें उठाकर सेट पर लाना था। कई बार मैं सोचती थी कि आखिर मैं कर क्या रही हूं।

...फिर अभय देओल ने पत्रकार बनने का इरादा छोड़ एक्टिंग को बनाया करियर

अभय देओल बॉलीवुड में एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। अभय निर्माता-निर्देशक अजीत सिंह देओल के बेटे हैं। उनके चाचा प्रसिद्ध एक्टर धर्मेंद्र हैं। अभय देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2005 में इम्तियाज अली की फिल्म सोचा ना था से की।

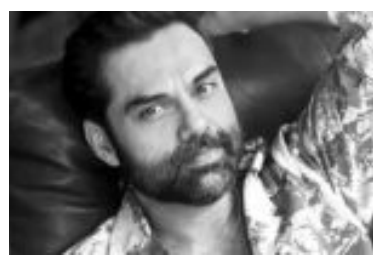

अभय ने न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में एक्टिंग और थियेटर सीखा है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके दिमाग में चार प्रोफेशन थे, एक्टिंग, पेंटिंग, फिलॉसफी और पत्रकारिता, पर उन्होंने एक्टिंग को चुना। वे स्कूल के समय से ही थियेटर से जुड़े रहे हैं और अपने भाइयों की तरह ही बॉलीवुड में पहचान बनाई है। साल 2007 में अभय देओल की फिल्म हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड प्रदर्शित हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। 2009 में अनुराग कश्यप की देव डी में अभय देओल के काम को काफी सराहा गया और फिल्म को क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों ने भी पसंद किया। 2011 में प्रदर्शित जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अभय देओल के करियर के लिए सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अपने दमदर अभिनय के लिए अभय देओल सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किए गए।

ये अपने बस की बात नहीं

बहनों और बहनों... अब वक्त आ गया है कि आप कुछ करो, बहुत सह ली मर्दों की गुलामी, बहुत उठा लिए उनके नखरे, बहुत बन लिए उनके पैरों की जूती...पर कब तक... उठो... जागो... अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होओ.. तोड़ दो यह परतंत्रता की बेड़ियां, आजाद हो जाओ घर की चारदीवारी से, बाहर निकलो अपना अस्तित्व पहचानो, अपनी पहचान बनाओ... यह पूरा आकाश है तुम्हारे लिए... उड़ो... अपनी कल्पना अपने कार्यों को पंख दो... घर की सेवा से बढ़कर है समाज सेवा... वह करो, अनाथ और बेसहारा वृद्धों की सेवा करो... देखो इस समाज में कितने दुखियारे, बेबस, लाचार, कमजोर लोग हैं... इन्हें सहारा दो, दुलार दो, देखो फिर कितनी दुआएं मिलती हैं, कितना सुकून मिलता है कितनी शांति मिलती है... सौम्या बड़ी प्रभावित हुई... इस महिला से तो एक बार मिलना पड़ेगा क्या बोलती है...! कितना दर्द है इसके दिल में दीन दुखियों के लिए... मैं इस से मिलूंगी तो मैं भी कुछ कर पाऊंगी... और मंत्रमुग्ध सौम्या ने मन ही मन सोच लिया अब से वह भी समाज सेवा शुरू करेगी। घर से बाहर निकल लोगों का दुख दर्द सुनेगी, दूर करने की कोशिश करेगी, उनके जरिए अपनी पहचान बनाएगी, आखिर उसका भी कोई अस्तित्व है या नहीं... उसी सम्मोहन में वह घर में दाखिल हुई और रोहन से बोली, सुनो मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं भी समाज सेवा करूंगी...।

रोहन ने मुंह उठाकर उसे देखा, पहले घर सेवा और पति सेवा तो कर लो बाद में करना समाज सेवा... सौम्या चिढ़ गई, जिंदगी भर यही करवाते रहना मुझसे... बांध कर रखना उम्र भर इस घर की चारदीवारी में...घर की, आपकी सेवा करते करते तो यह हालत हो गई मेरी...अब थोड़ी सी खुद कर लो अपनी सेवा, अपने घर की सेवा, तब पता चलेगा कैसे की जाती है सेवा, आए बड़े पहले पति सेवा तो कर लो...।

रोहन क्यों चुप रहता, ओहो... ऐसी कौन सी सेवा कर दी है तुमने मेरी, ऐसा क्या करवा लिया मैंने मेरे घर में... वही करती हो जो सभी बीवियां करती हैं, कोई अनोखा काम तो नहीं किया...।

सौम्या और चिढ़ गई, सब पका पकाया मिल जाता है ना, इसलिए अनोखा काम नहीं लग रहा। जब खुद करना पड़ेगा ना तब पता चलेगा कितना अनोखा है अब तो और नहीं करूंगी... संभालो अपना घर बार बच्चे... करो सेवा मैं तो अब समाज सेवा ही करूंगी समझे! मुझे भी चाहिए आजादी की सांस, खुला आसमान... अब नहीं रहूंगी मैं घर की कैद में... अब मुझे बाहर निकलना है तो निकलना है बस...।

बोलकर वह तो धमकती अंदर चली गई रोहन वहीं बैठा सोचता रह गया कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे... सौम्या दूसरे ही दिन पहुंच गई समाजसेवी मैडम के यहां... मैडम ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे अपनी संस्था से जोड़ने के लिए सदस्यता फीस ली और समाज सेवा के कामों में आगे बढ़ाने के लिए उसे लेकर एक अनाथ आश्रम में पहुंची... बड़ी खुश-खुश सौम्या बच्चों के लिए कुछ करने का उत्साह लेकर वहां पहुंचती...पर अनाथ आश्रम के बच्चे देख कलेजा मुंह को आने लगा... किसी तरह हिम्मत कर आगे बढ़ी... एक साफ-सुथरे बच्चे को देख उसे प्यार किया... वह बुरी तरह चिपक गया, आप मुझे रोज ऐसे ही प्यार करेंगी, यहां रोज आएंगी, रोज मुझे यह बिस्किट चॉकलेट देगी... एक तरफ उसकी बातों का दर्द दूसरी तरफ साड़ी खराब होने की चिंता... सौम्या को समझ नहीं आया कि क्या करे... निकलने लगी तो तीन-चार और बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, आप हमें हमारी मां के पास ले जाएंगे, हमें हमारे घर पहुंचा देंगे! हमारा यहां मन नहीं लगता, मां की बहुत याद आती है, आप ले चलिए ना हमें वहां... सौम्या हैरान-परेशान क्या करें? क्या जवाब दे? कहां से लाए इनकी मां? रोजाना भी तो संभव नहीं... एक ही जगह थोड़ी ना रोज विजिट दी जाएगी और जगह भी तो जाना है... किसी तरह समझा-बुझाकर उन्हें परे धकेलकर बाहर निकली, बाहर आकर गहरी-गहरी सांस ली... साथ आई संचालिका तथा अन्य महिलाओं ने संभाला... इतना कमजोर होना ठीक नहीं, अभी तो न जाने कितने और सामने आएंगे... हमारा काम सिर्फ कपड़े, खिलौने, बिस्किट, चॉकलेट देना है और कुछ नहीं, बाकी वो जाने और उनके आश्रम के संचालक जाने चलो...।

सौम्या हैरान उसका मुंह देखती रही...उस दिन तो न जाने क्या-क्या बोल रही थी इनके दुख दर्द को दूर करने के लिए और आज! घर आकर भी सौम्या की निगाहों में वह बच्चे घूमते रहे, एक बेचैनी सी हावी रही... दूसरे दिन महिला आश्रम जाना था... वहां की अलग गाथा... बुझी-बुझी त्रस्त सी महिलाएं अपने काम में व्यस्त थीं... उन लोगों पर एक निर्लिप्त दृष्टि डाल अपने काम में लगी रहीं... वहां की संचालिका साथ आई महिलाओं से बातें करने लगी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों की वजह से ही आश्रम चलता है... निराश्रित महिलाओं का कुछ भला हो जाता है... उसने काम करती एक महिला को बुलाया, मैडम को बताओ तुम्हें यहां कोई तकलीफ हो तो... उसने एक सहमी सी दृष्टि संचालिका पर डाली और रटे शब्दों में बोली- हमें यहां कोई तकलीफ नहीं है हम यहां आराम से हैं... संचालिका बहन जी हमारा बहुत ध्यान रखती हैं... ठीक है तुम जाओ...।

आंसुओं को पलकों में ही छुपाती वह चली गई, सौम्या चुपचाप देखती रही... वहां से निकली पर बेबस आंखें दूर तक पीछा करती रहीं... उसका जी मिचलाने लगा... साथ आई महिलाएं आपस में खुसर-पुसर करने लगीं, यह बड़े घरों की औरतें इन्हें भी भूत सवार होता है समाज सेवा करने का... अरे काहे की समाज सेवा अखबारों में नाम व फोटो छपवाने का क्रेज रहता है... समाज सेवा का 'स' भी पता नहीं होता इन्हें... सब बड़े लोगों के चोंचले हैं... इतने कमजोर दिल की भी है... पता नहीं क्यों चली आती हैं समाज सेवा, समाज सेवा करती, दो विजिट में देखो क्या हालत हो गई...।

अरे छोड़ ना... दो दिन का चस्का, 4 दिन की चांदनी है, अभी 2 दिन में भूत उतर जाएगा तो आप ही बैठ जाएगी वापस अपने घर... बहुत देखी है ऐसी समाजसेवी...छोड़ ना...सौम्या सुनी अनसुनी कर बैठी रही। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। मैडम का फोन आया शहर से 12 किलोमीटर दूर एक वृद्धा आश्रम है वहां विजिट देना है... आज गाड़ी नहीं है तो अपनी कार ले आना... तुम्हारी कार से जाएंगे...।

● **डॉ. ममता मेहता**

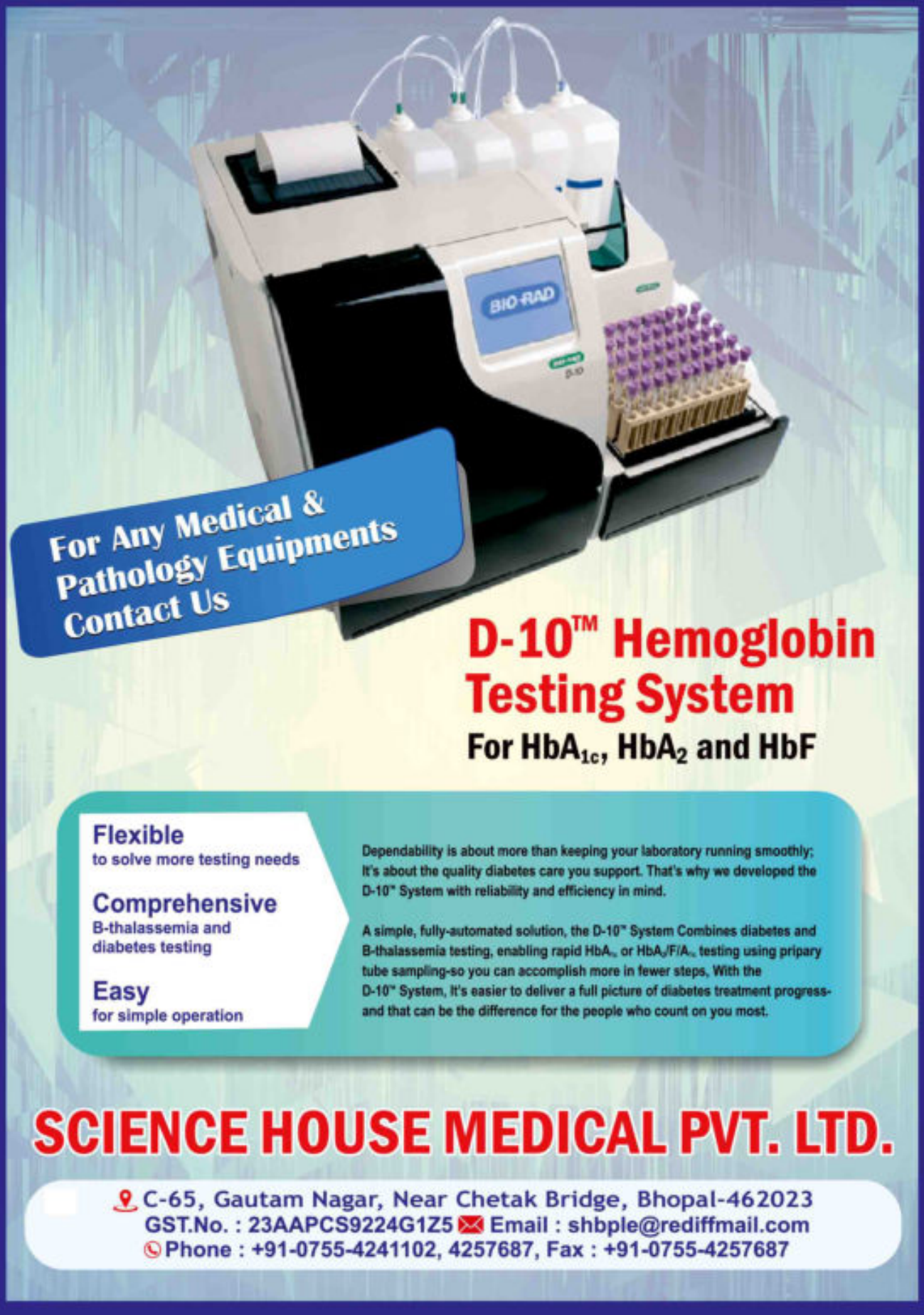

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in